चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 25 जुलाई-31 जुलाई 2011 | मूल्य 5 रुपये

अब काला धन वापस नहीं आएगा

पेज-3

सरकारी दमन से निपटने की तैयारी क्या है

पेज-4

क़ानून नहीं, इंसाफ़ की ज़रूरत

पेज-6

साई की महिमा

पेज-12

थल सेनाध्यक्ष के ख़िलाफ़

सरकार की साज़िश

सभी फोटो-**प्रभात पाण्डेय**

भारत के इतिहास में पहली बार इतना गंभीर होने जा रहा है, जिसका असर भारत के लोकतंत्र पर पड़ने वाला है. आज़ाद भारत की पहली सरकार मनमोहन सिंह की सरकार होगी, जिसे शायद इतिहास की सबसे गंभीर शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी. भारतीय सेना का सर्वोच्च अधिकारी, भारतीय थलसेना का सेनाध्यक्ष न्याय के लिए रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहा है, पर उन्होंने न्याय देने के सवाल पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं. आंखें तो सरकार ने बहुत सी समस्याओं से फेर ली हैं, पर भारतीय सेना से आंखें फेरना और सेना के ईमानदार और सच्चे अधिकारी को न केवल झूठा साबित करना, बल्कि अपमानित करना बताता है कि सरकार कितनी ज़्यादा असंवेदनशील और अकर्मण्य हो गई है.

आख़िर, भारत सरकार (रक्षा मंत्री और उनका मंत्रालय प्रत्यक्ष तौर पर, प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय अप्रत्यक्ष तौर पर) सेना के सर्वोच्च अधिकारी को अपमानित करने पर क्यों तुली हुई है? क्या इसके पीछे देश का ज़मीन माफिया और दुनिया का हथियार माफिया है? जनरल वी के सिंह ईमानदार अफसर माने जाते हैं और आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है. देश के तीन भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायाधीशों ने भी इस मामले पर विस्तार से अलग-अलग विचार किया. सभी ने कहा कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 मानी जाएगी.

जनरल वी के सिंह ख़ुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए. वह चाहते तो अपनी जन्मतिथि स्वयं ठीक करा सकते थे, क्योंकि दोनों ब्रांच उन्हीं के अधीन थीं, लेकिन उन्होंने ईमानदारी और नैतिकता की राह पकड़ी. उन्होंने रक्षा मंत्री को सारा मामला बताया. रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं इस मामले को अटॉर्नी जनरल को भेजना चाहता हूं. जनरल ने कहा, आपकी मर्ज़ी. रक्षा मंत्री ने एजी से दो बार राय मांगी. दूसरी राय में एजी ने लिखा है कि जनरल वी के सिंह ने अपने सारे प्रमोशन 10 मई, 1950 बताकर लिए हैं, जबकि बोर्ड के सारे प्रमोशनों की फाइलें, जिन पर प्रधानमंत्री के दस्तख़त हैं, रक्षा मंत्री के दस्तख़त हैं, उन सब में जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 लिखी है.

भारतीय सेना पर लिखने से हमेशा बचा जाता रहा है, क्योंकि सेना ही है जो देश की रक्षा दुश्मनों से करती है, पर पिछले कुछ सालों में सेना में भ्रष्टाचार बढ़ा है. अक्सर खाने के सामान की शिकायतें आती हैं कि वहां घटिया राशन सप्लाई हुआ है. लोग पकड़े भी जाते हैं, सज़ाएं भी होती हैं. सेना में ख़रीद फ़रोख्त में लंबा कमीशन चलता है, जिसके अब कई उदाहरण सामने आ चुके हैं. ज़्यादातर मामलों के पीछे राजनेताओं का छुपा हाथ दिखाई दिया है. अब जो बात हम सामने रखने जा रहे हैं, वह एक गठजोड़ की ताक़त बताती है कि कैसे सच्चाई को झूठ और ताक़त के बल पर दबाया या झुठलाया जा रहा है. इसका शिकार कौन होने वाला है? भारत का सेनाध्यक्ष. जब हमें छिटपुट ख़बरें मिलीं, जिन्हें भारत के रक्षा मंत्रालय या रक्षामंत्री ने लीक कराया था. तब हमारा माथा ठनका. ख़बरें थीं भारत के सेनाध्यक्ष की जन्मतिथि के बारे में कि आख़िर असली जन्मतिथि है क्या. ख़बरों में यह बताने की कोशिश की गई कि भारत के थल सेनाध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं और उनकी जन्मतिथि वह नहीं है, जो वह बता रहे हैं. भारत के थल सेनाध्यक्ष सच्चाई पर प्रकाश डालने के लिए जब उपलब्ध नहीं हुए तो हमने इस सारे मामले की जांच करने का निर्णय लिया. हमारी जांच में बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जो बताते हैं कि कैसे न्याय का गला सरकार घोंट रही है और सुप्रीम कोर्ट की दी हुई नज़ीरों को अनदेखा कर रही है.

क्या है मामला

श्री कमल टावरी रिटायर्ड आईएएस हैं और एक एनजीओ नेशनल थिंकर्स फोरम के उपाध्यक्ष हैं. उन्होंने जब अख़बारों में भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि पर विवाद उठते देखा तो 28 अक्टूबर, 2010 को एक आरटीआई डाली, जिसे उन्होंने सीपीआईओ, इंडियन आर्मी, इंटीग्रेटेड हेड क्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस (आर्मी), रूम नं. जी- 6, डी-1 विंग, सेना भवन, न्यू देहली को भेजा. इस दरख्वास्त में, जिसे उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 6 के तहत भेजा, जानकारी मांगी कि मौजूदा थल सेनाध्यक्ष जनरल विजय कुमार सिंह और उन लेफ्टिनेंट जनरलों की आयु बताई जाए, जिन्हें जनरल वी के सिंह के रिटायर होने की स्थिति में थल सेनाध्यक्ष बनाया जा सकता है. इसके जवाब में 23 फरवरी, 2011 को सेना के आरटीआई सेल, एडीजीएई, जी-6, डी-1 विंग, सेना भवन, गेट नं. 4, आईएचक्यू ऑफ एमओडी (आर्मी), न्यू देहली ने कमल टावरी को एक ख़त और एक सूची भेजी, जिसमें सेना के छह सर्वोच्च अफ़सरों की जन्मतिथियां थीं. इसके अनुसार सेना के एजी ब्रांच और हाईस्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से इन सबकी जन्मतिथियों की जानकारी है. इस सूची के अनुसार थल सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एडीसी की जन्मतिथि 10 मई, 1951 है. लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप खन्ना, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी की जन्मतिथि 7 फरवरी, 1951 है. लेफ्टिनेंट जनरल ए के लांबा, पीवीएसएम, एवीएसएम की जन्मतिथि 16 अक्टूबर, 1951 है. लेफ्टिनेंट जनरल शंकर घोष एवीएसएम, एसएम की जन्मतिथि 22 मई, 1952 है. लेफ्टिनेंट जनरल वी के अहलूवालिया एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम की जन्मतिथि 2 फरवरी, 1952 है और लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम की जन्मतिथि 19 जुलाई, 1952 है. इस ख़त के बाद डीडीजी आरटीआई एंड सीपीआईसी ब्रिगेडियर ए के त्यागी ने फिर कमल टावरी को एक ख़त भेजा, जिसमें 23 फरवरी, 2011 के ख़त से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी दी और लिखा कि राजस्थान बोर्ड द्वारा दिए गए हाईस्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार जन्मतिथि 10 मई, 1951 है, जिसे एलए (डिफेंस) की सलाह अनुसार करेक्शन के लिए भेज दिया गया है. इस तरह के सबूतों को, सेना के काग़ज़ों को हम आपके सामने रखें, उससे पहले आपको पूरी कहानी बताते हैं, जिसे जनरल वी के सिंह के गांव वालों ने बताया है.

हाईस्कूल बनाम एनडीए

जनरल वी के सिंह का जन्म 10 मई, 1951 को आज के हरियाणा के फफोड़ा गांव में हुआ. उन दिनों हरियाणा और पंजाब एक ही थे. यह गांव भिवानी ज़िले में आता है. बिड़ला स्कूल पिलानी में पढ़ते हुए जनरल वी के सिंह ने सेना में जाना तय किया. यह 1965 का साल था और उनकी उम्र 15 साल थी. एनडीए का फॉर्म भरा जा रहा था. कई लड़के एक साथ बैठकर फॉर्म भर रहे थे. एक शिक्षक उन्हें फॉर्म भरवाने में मदद कर रहा था. यह फॉर्म यूपीएससी का था. शिक्षक के कहने पर या किसी साथी विद्यार्थी के कहने पर ग़लती से उन्होंने उस फॉर्म में जन्मतिथि 10 मई, 1950 भर दी. फॉर्म चला गया और महत्वपूर्ण बात यह कि उस समय तक राजस्थान बोर्ड का हाईस्कूल का सर्टिफिकेट आया नहीं था. यह फॉर्म प्रोविजनल होता है. जब सर्टिफिकेट आया हाईस्कूल का तो उसे यूपीएससी भेजा गया. यूपीएससी ने 1966 में एक ग़लती पकड़ी और वी के सिंह से पूछा कि आपने फॉर्म में जन्मतिथि 10 मई, 1950 लिखी है, जबकि आपके हाईस्कूल सर्टिफिकेट में यह 10 मई, 1951 दर्ज है. वी के सिंह ने क्लेरीफिकेशन भेज दिया कि हाईस्कूल के सर्टिफिकेट में लिखी जन्मतिथि 10 मई, 1951 ही सही है, फॉर्म में भूलवश या मानवीय ग़लती से 10 मई, 1950 लिखा गया है. वी के सिंह के इस उत्तर को यूपीएससी ने स्वीकार किया तथा उन्हें इसकी रसीद भी भेज दी. यूपीएससी का नियम है कि यदि उसने इसे स्वीकार न किया होता तो वी के सिंह का फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता. वी के सिंह एनडीए में चुने गए और 1970 में उन्होंने पास

(शेष पृष्ठ 2 पर)

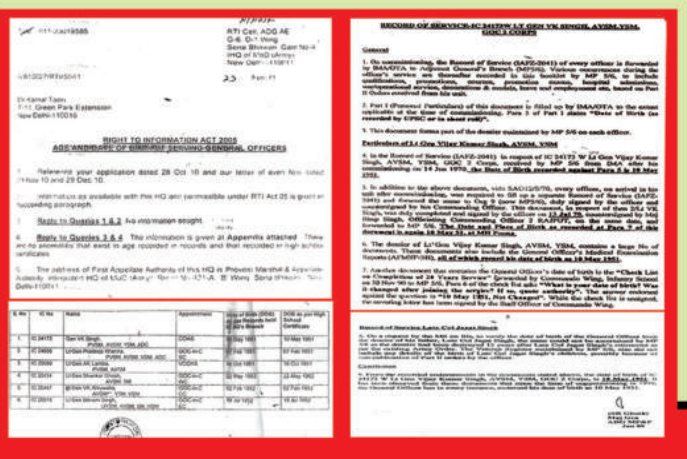

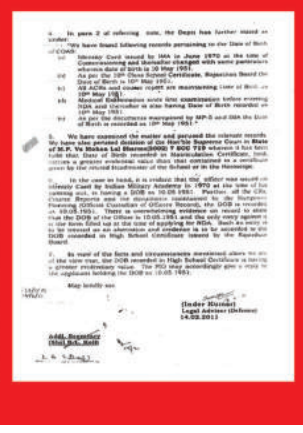

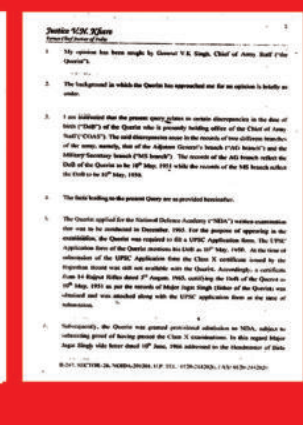

"Cotton ki Jhappi!"

T.T.

Healthy Innerwear

Vest • Brief • Bra-Panties • T-Shirts

Ph. : 011-45060708, E-mail: export@tttextiles.com

एजी को वे फाइलें भेजी गईं, जिन्हें मिलिट्री सेक्रेट्री ब्रांच मेंटेन कर रही थी. उसमें भी पूरे तथ्य नहीं भेजे गए. इसका एक सबूत हमारे हाथ लगा है.

थल सेनाध्यक्ष के ख़िलाफ़ सरकार की साज़िश

पृष्ठ एक का शेष

आउट किया. आईएमए ने उन्हें आई कार्ड दिया, जिस पर जन्मतिथि 10 मई, 1951 लिखी. आर्मी में वी के सिंह की ज़िंदगी शुरू हो गई.

कब खुला मामला

अब आया 2006. मेजर जनरल वी के सिंह को एक ख़त मिला, तत्कालीन मिलिट्री सेक्रेट्री रिचर्ड खरे के हस्ताक्षरित, जिसमें रिचर्ड खरे ने लिखा था कि हम लोगों ने पाया है कि आपकी जन्मतिथि दो तरह की लिखी गई है. एडजुटेंट जनरल ब्रांच और मिलिट्री सेक्रेट्री ब्रांच के रिकॉर्ड में अंतर है. एडजुटेंट जनरल ब्रांच, जो कि कस्टोडियन ब्रांच है, में लिखा है 10 मई, 1951 और मिलिट्री सेक्रेट्री ब्रांच में 10 मई, 1950 मेंटेन हो रहा है. जनरल वी के सिंह ने क्लेरीफिकेशन दिया कि उनकी जन्मतिथि 10 मई, 1951 है, न कि 10 मई, 1950. क्लेरीफिकेशन के साथ वी के सिंह ने हाईस्कूल सर्टिफिकेट भी भेज दिया. मिलिट्री सेक्रेट्री ब्रांच ने लिखा कि वह एडजुटेंट जनरल ब्रांच से क्लेरीफिकेशन लेंगे. एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने सारे काग़ज़ों को खंगाल कर मिलिट्री सेक्रेट्री ब्रांच को लिखा कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 है.

जनरल जे जे सिंह का खेल

जनरल जे जे सिंह उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे. फाइल करेक्शन के लिए उनके पास आई. उन्होंने ऑर्डर निकाला कि पॉलिसी में है कि अगर आप जन्मतिथि में परिवर्तन चाहते हैं तो दो साल के भीतर ही यह हो सकता है, अब यह चेंज नहीं हो सकता. यहां जनरल जे जे सिंह ने एक खेल किया. उन्होंने आंकड़ा लगाया कि जन्मतिथि 10 मई, 1950 हो या 10 मई, 1951, जनरल वी के सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे ही. पर यदि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 रह जाती है तो ले.जनरल बिक्रम सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन पाएंगे. संयोग की बात है कि जनरल जे जे सिंह सिख बिरादरी से आते हैं और ले. जनरल बिक्रम सिंह भी सिख बिरादरी से हैं. उन दिनों भी प्रधानमंत्री सिख समाज के सरदार मनमोहन सिंह थे, आज भी प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह हैं. जनरल जे जे सिंह ने बिक्रम सिंह को देश का सेनाध्यक्ष बनाने की बिसात 2006 में बिछा दी. जनरल जे जे सिंह के ख़त के जवाब में जनरल वी के सिंह ने लिखा कि जन्मतिथि में चेंज का सवाल कहां से आया, यह तो आपका एकतरफ़ा नज़रिया है. मैं तो करेक्शन मांग रहा हूं, जो अब तक हो जाना चाहिए था. मैं चेंज मांग ही नहीं रहा, अत: यह पॉलिसी उन पर लागू नहीं होती.

जनरल दीपक कपूर का दबाव

जनरल जे जे सिंह के बाद जनरल दीपक कपूर सेनाध्यक्ष बने. जनरल दीपक कपूर ने जनरल वी के सिंह को बुलाया और कहा कि सारी फाइलें, प्रमोशन वाली रुक गई हैं आपकी चिट्ठी से और मिनिस्ट्री बार-बार कह रही है कि जनरल वी के सिंह का मामला निबटाओ. मैंने सारे काग़ज़ात देखे हैं, मैं इन्हें लॉ मिनिस्ट्री को भेजना चाहता हूं. मैं तुम्हारा चीफ हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि फाइलों के मूवमेंट को मत रोको. एमएस में बाधा मत बनो, वह जो कह रहा है उसे स्वीकार कर लो. जनरल वी के सिंह ने जनरल कपूर से कहा कि मैं कैसे स्वीकार कर लूं या फिर क्या मेरे स्वीकार करने से मेरी जन्मतिथि बदल जाएगी? मेरा जन्म निर्धारित है, क्या आप हाईस्कूल सर्टिफिकेट को भी बदल देंगे? जनरल दीपक कपूर ने फिर दबाव डाला और कहा कि बात मान लो और फाइलें मूव होने दो. जनरल वी के सिंह ने कहा कि मैं कैसे मान लूं, आप वेरीफाई करा लें, उसके बाद करेक्शन कर दें. यही कंडीशनल एक्सेप्टेंस वी के सिंह ने जनरल दीपक कपूर को दे दी. हमारी जांच बताती है कि जैसे ही जनरल वी

ले. जनरल बिक्रम सिंह

जनरल जे जे सिंह

जनरल दीपक कपूर

जी ई वाहनवती

के सिंह दिल्ली से अंबाला पहुंचे, उस समय शाम के चार बजे थे, उन्हें आर्मी हेडक्वार्टर से सिग्नल मिला कि जैसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताते हैं, वैसा सुबह 10 बजे तक आप नहीं भेजेंगे तो आपके ख़िलाफ़ एक्शन बीईंग एप्रोप्रिएट लिया जाएगा. आर्मी का डिफेंस सर्विस रूल कहता है कि अगर आपके सीनियर ने कोई ऑर्डर, भले ही मौखिक हो, जारी कर दिया है तो आप उससे पूछ नहीं सकते. अगर आप उस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आपको कम से कम तीन महीने का कठोर कारावास का दंड मिलेगा. जनरल वी के सिंह ने इस सिग्नल के जवाब में लिखा, ***एज डायरेक्टेड बाइ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आई एक्सेप्ट.*** जनरल वी के सिंह का अंबाला से कलकत्ता ट्रांसफर हो गया. उन्होंने फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त लिखा कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझसे कहा कि आप मेरे मामले को क़ानून मंत्रालय भेज रहे हैं. आप पर चीफ के नाते मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन आपने वायदे के हिसाब से जो कहा था, वह नहीं किया, एथिकली और लॉजिकली यह सही नहीं है. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वह ख़त रख लिया, जवाब नहीं दिया. जब जनरल वी के सिंह मिलने गए तो जनरल दीपक कपूर ने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा. तुम चीफ बनना तो ख़ुद ठीक करवा लेना अपनी जन्मतिथि. जनरल वी के सिंह चुपचाप वापस चले आए.

रक्षामंत्री और एजी का रवैया

अब जनरल वी के सिंह ख़ुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए. वह चाहते तो अपनी जन्मतिथि स्वयं ठीक करा सकते थे, क्योंकि दोनों ब्रांच उन्हीं के अधीन थीं, लेकिन उन्होंने ईमानदारी और नैतिकता की राह पकड़ी. उन्होंने रक्षा मंत्री को सारा मामला बताया और कहा कि उनका यह मामला पेंडिंग है. रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे पता है, मैं दिखवाता हूं. रक्षा मंत्री ने इस मामले को टाला और रक्षा मंत्रालय ने इसे प्रेस को लीक करना शुरू किया. अख़बारों में पढ़ तीन लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग ली. इन तीन में एक रिटायर्ड आईएएस तथा सेना के भूतपूर्व ऑफिसर कमल टावरी भी थे, जिन्हें सेना की छीछालेदर मंत्रालय द्वारा करना पसंद नहीं आया. उन्होंने आरटीआई में पूछा कि जनरल वी के सिंह और उनके नीचे के पांच जनरलों की डेट ऑफ बर्थ क्या है तथा क्या जनरल वी के सिंह की डेट ऑफ बर्थ में एनोमलीज़ है? क्या उस पर क़ानून मंत्रालय से कोई राय लेकर सुधार किया गया है?

सरकार ने पहला जवाब दिया कि जनरल वी के सिंह की डेट ऑफ बर्थ 10 मई, 1951 है. दूसरा जवाब दिया कि कोई एनोमली नहीं है. एक छोटी भूल एक विभाग में हो गई है. क़ानून मंत्रालय से मशविरा कर लिया गया है और उसकी सलाहानुसार उस विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि वह भूल सुधारे और 10 मई, 1951 मेंटेन करे.

यह जवाब अख़बारों में आ गया. इसे पढ़ रक्षा मंत्री ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया तथा पूछा कि क्या होना चाहिए. चीफ ने उनसे कहा कि जब क़ानून मंत्रालय की राय आ गई है तो उसे मानना चाहिए. इस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं इस मामले को अटॉर्नी जनरल को भेजना चाहता हूं. जनरल ने कहा, आपकी मर्ज़ी.

एजी को वे फाइलें भेजी गईं, जिन्हें मिलिट्री सेक्रेट्री ब्रांच मेंटेन कर रही थी. उसमें भी पूरे तथ्य नहीं भेजे गए. इसका एक सबूत हमारे हाथ लगा है. दरअसल रक्षा मंत्री ने एजी से दो बार राय मांगी. दूसरी राय में एजी ने लिखा है कि जनरल वी के सिंह ने अपने सारे प्रमोशन 10 मई, 1950 बताकर लिए हैं, जबकि बोर्ड के सारे प्रमोशनों की फाइलें, जिन पर प्रधानमंत्री के दस्तख़त हैं, रक्षा मंत्री के दस्तख़त हैं, उन सब में जनरल वी के सिंह की

जनरल जे जे सिंह उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे. तब उन्होंने एक खेल किया. उन्होंने आंकड़ा लगाया कि जन्मतिथि 10 मई, 1950 हो या 10 मई, 1951, जनरल वी के सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे ही. पर यदि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 रह जाती है तो ले. जनरल बिक्रम सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन पाएंगे. संयोग की बात है कि जनरल जे जे सिंह सिख बिरादरी से आते हैं और ले. जनरल बिक्रम सिंह भी सिख बिरादरी से हैं. उन दिनों भी प्रधानमंत्री सिख समाज के सरदार मनमोहन सिंह थे, आज भी प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह हैं. जनरल जे जे सिंह ने ले. जनरल बिक्रम सिंह को देश का थल सेनाध्यक्ष बनाने की बिसात 2006 में बिछा दी.

जन्मतिथि 10 मई, 1951 लिखी है. एजी की पहली राय पर रक्षा मंत्री ने जनरल को बुलाया तथा कहा कि राय आ गई है, आप इसे मान लीजिए. जनरल ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा. उन्होंने रक्षा मंत्री को एक रिप्रजेंटेशन दिया, जिसमें सारे तथ्य दिए गए तथा अनुरोध किया गया कि विचार करें. रक्षा मंत्री ने उसे एजी को भेज दिया, जिस पर एजी ने पहला जवाब दोहरा दिया. क्या रक्षा मंत्री के इस रुख़ के पीछे आईएएस मिलिट्री सेक्रेट्री की ग़लतियां छुपाने का कारण है या प्रधानमंत्री के कार्यालय का कोई इशारा है. अब हम अपनी तलाश में मिले कुछ और तथ्य बताते हैं. इंदर कुमार, लीगल एडवाइजर (डिफेंस) ने 14 फरवरी, 2011 को एडी. सेक्रेट्री आर एल कोहली की जानकारी में एक नोट लिखा, जिसका नंबर है-मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लीगल एडवाइज़ (डिफेंस)

Dy. No. 0486/XI/LA (DEF)
12918/RTI/MP 6-(A).

इस नोट के कुछ मुख्य अंश हैं:-

- *क्या जब यूपीएससी में फॉर्म भरा था, तब की डेट ऑफ बर्थ 10 मई, 1950 सही है या राजस्थान बोर्ड द्वारा 1966 में जारी Xth बोर्ड सर्टिफिकेट में दी गई डेट ऑफ बर्थ 10 मई, 1951 सही है. (इस नोट को हम पूरा छाप रहे हैं)*

इस नोट के प्वाइंट नंबर पांच में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ एम पी बनाम मोहनलाल शर्मा (2002) 7 SCC 719 के फ़ैसले में कहा है, ***दैट डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, हेल्ड, कैरीज ए ग्रेटर, एविडेंशियल वैल्यू, देन, दैट कंटेंड इन ए सर्टिफिकेट गिवेन बाइ द रिटायर्ड हेडमास्टर ऑफ द स्कूल आर इन द हारोस्कोप.*** इस नोट के आख़िरी यानी सातवें नंबर पर लिखा है, ***इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसेज मेंशंड एबव वी आर ऑफ द व्यू दैट, द डीओबी रिकॉर्डेड इन हाईस्कूल सर्टिफिकेट इज हैविंग ए ग्रेटर एविडेंसरी वैल्यू. द पीआईओ मे एकार्डिंगली गिव ए रेप्लाई टू द एप्लीकेंट होल्डिंग द डीओबी एज 10.05.1951.*** इतना ही नहीं, एडजुटेंट जनरल ब्रांच के मेजर जनरल सतीश नायर, एडीजी एमपी ने फरवरी 2011 में एक नोट में लिखा, ***बिफोर रेप्लाई टू द आरटीआई क्वेरी टू द एप्लीकेंट, इज गिवेन, एडवाइज ऑफ द एल ए (डिफेंस) इज रिक्वेस्टेड आन द एबव फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसेज आन द इश्यू व्हेदर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द COAS मे बी इनफार्मड् टू द सैड एप्लीकेंट एज 10th मे 1951.***

- एन अर्ली एक्शन इज रिक्वेस्टेड प्लीज.

भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश क्या कहते हैं

ये सारे नोट, सरकार द्वारा दिया गया जवाब बताता है कि सच्चाई क्या है और जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 है. तब क्यों भारत सरकार (रक्षा मंत्री और उनका मंत्रालय प्रत्यक्ष तौर पर, प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय अप्रत्यक्ष तौर पर) सेना के सर्वोच्च अधिकारी को अपमानित करने पर तुली है? क्या इसके पीछे देश का ज़मीन माफ़िया और दुनिया का हथियार माफ़िया है? जनरल वी के सिंह ईमानदार अफ़सर माने जाते हैं और आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है, सिवाय इस आरोप के कि उनकी जन्मतिथि के रूप में सेना और रक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड में अलग-अलग तिथियां दर्ज हैं. देश के तीन भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायाधीशों ने भी इस मामले पर विस्तार से अलग-अलग विचार किया. उन्होंने विस्तार से अपनी राय लिखी. जस्टिस जे एस वर्मा ने अपने नतीजे में लिखा, ***आई देयर फोर फेल टू एप्रीसिएट हाउ द एमएस ब्रांच ऑर एनी वन एल्स कैन रेज़ ए कंट्रोवर्सी इन दिस बिहाफ ऑर क्वीश्चन द करेक्टनेस ऑफ द डीओबी ऑफ जनरल वी के सिंह रिकॉर्डेड थ्रू आउट बाई द एजी ब्रांच एज 10th मे 1951.*** दूसरे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जी वी पटनायक ने भी विस्तार से अपनी राय लिखते हुए आख़िर में कहा है, ***इट ट्रांसपायर्स दैट द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ व्हिच द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर गिविंग लीगल ओपीनियन टू अदर डिपार्टमेंट्स, हैज आलरेडी ओपेंड टू दिस इफेक्ट दैट डेट ऑफ बर्थ ऑफ द क्वेरिस्ट कैन ओनली बी 10th मे 1951. आई डू नॉट नो ऑन व्हाट बेसिस द लर्नड एटार्नी जनरल हैज गिवेन कंट्रैरी ओपीनियन.*** तीसरे जस्टिस वी एन खरे ने कहा है, ***इन व्यू ऑफ द एबव इट इज माई ओपीनियन दैट एट दिस स्टेज, द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी टू एक्सेप्ट द डीओबी ऑफ द क्वेरिस्ट एज फाउंड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द एजी ब्रांच टू बी 10th मे 1951 एंड मेक नेसेसरी चेंजेज व्हेयर रिक्वायर्ड.*** चौथे रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अहमदी ने मुझसे कहा कि वे तीनों भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों की राय से सहमत हैं तथा अख़बारों में आई एटार्नी जनरल की राय को ग़लत मानते हैं. उन्हें एजी की आधिकारिक राय की प्रति का इंतज़ार है.

समाधान क्या है

अटॉर्नी जनरल वाहनवती टूजी स्पेक्ट्रम मामले में पहले ही संदेह के घेरे में हैं. क़ानून मंत्रालय द्वारा दी गई राय से अलग राय देने के लिए उन पर अवश्य दबाव डाला गया होगा. यह एक षड्यंत्र है, जो राजनीतिज्ञ और कुछ आईएएस मिलकर कर रहे हैं. इसका सामना जनरल वी के सिंह करेंगे या नहीं, पता नहीं, पर उन्हें अपने को सच्चा साबित करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, जहां राष्ट्रपति इस मामले में सर्वोच्च न्यायाधीश की राय मांग सकती हैं. मुख्य न्यायाधीश स्वयं भी इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, धारा 143 इसकी आज्ञा देती है या आख़िर में जनरल वी के सिंह ख़ुद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ताकि अपने चरित्र पर लगे दाग़ को धो सकें.

सरकार की गड़बड़ी जैसे हमने खोली है, इससे ज़्यादा भयानक और गंभीर रूप में सुप्रीम कोर्ट में खुलेगी. सरकार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कपाड़िया से डरना चाहिए, जिनकी निष्पक्षता का डंका सारे देश में बज रहा है. सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अगर जनरल वी के सिंह के पक्ष में आ गया तो रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री के सामने त्यागपत्र देने के अलावा कोई रास्ता बचेगा क्या? मौजूदा सरकार जानबूझ कर प्याज़ भी खाएगी और जूते भी.

विशेष संवाददाता
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 20
दिल्ली, 25 जुलाई -31 जुलाई 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के -2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-4783999/011-23418962
0120-6450888, 0120-6452888
0120-6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120-4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरी घटना घटी. सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने इस्तीफ़ा दे दिया. सरकार ने जानबूझ कर उन्हें अपमानित करने की कोशिश की.

अब काला धन वापस नहीं आएगा

अब देश की जनता हाथ मलती रह जाएगी, क्योंकि काला धन वापस नहीं आने वाला है. अब यह भी पता नहीं चल पाएगा कि वे कौन-कौन कर्णधार हैं, जिन्होंने देश का पैसा लूट कर स्विस बैंकों में जमा किया है. भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड की सरकार के साथ मिलकर एक शर्मनाक कारनामा किया है, लेकिन देश में इसकी चर्चा तक नहीं है. सरकार के कारनामे से विपक्ष भी वाकिफ है. इस पर आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन यह भी एक राज़ है कि काले धन के मुद्दे को सबसे पहले उठाने वाले लालकृष्ण आडवाणी और भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे पर खामोश हैं. लगता है, काले धन के मामले पर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिग बन गई है कि तुम चुप रहो और मैं भी आंखें बंद कर लेता हूं. जनता कुछ दिनों बाद ख़ामोश हो जाएगी.

मनीष कुमार

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के चेयरमैन प्रकाश चंद्र ने एक चौंकाने वाला बयान दिया. यह बयान स्विट्जरलैंड और भारत के बीच काले धन के मामले में हुए क़रार के बारे में है. इस समझौते को स्विट्जरलैंड की संसद की मंजूरी मिल गई है. इस क़रार में भारतीय नागरिकों के स्विस बैंकों के खातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रावधान है. प्रकाश चंद्र ने कहा कि इस क़ानून के लागू होने के बाद खोले गए खातों के बारे में ही जानकारी मिल सकती है. इस बयान का मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि जो खाते इस क़ानून के लागू होने से पहले खुले हैं, उनके बारे में अब कोई जानकारी नहीं मिलेगी. यानी भारतीय अधिकारियों को अब तक जमा किए गए काले धन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकेगी. इसका मतलब यह है कि भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड की सरकार से यह क़रार किया है कि जो खाते पहले से चल रहे हैं, उनकी जानकारी उसे नहीं चाहिए. मतलब यह कि सरकार उन लोगों को बचाने में जुटी है, जिन्होंने अब तक काले धन को स्विस बैंकों में जमा किया है. अब कोई मूर्ख ही होगा, जो इस क़ानून के लागू होने के बाद स्विस बैंकों में अपना खाता खोलेगा. अब यह पता नहीं कि सरकार किसे पकड़ना चाहती है.

अब तक भारत सरकार यह कहती आ रही थी कि स्विट्जरलैंड के क़ानून की वजह से हमें इन खातों के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है. तो भारत सरकार को यह क़रार करना चाहिए था कि अब तक जितने भी खाते चल रहे हैं, उनकी जानकारी मिल सके, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया. इससे यही साफ़ होता है कि सरकार काले धन के मामले पर देश के लोगों को गुमराह कर रही है. दरअसल, काले धन के मामले पर सरकार सोचती कुछ है, बोलती कुछ है और करती कुछ और है. प्रेस कांफ्रेंस और मीडिया के सामने आते ही सरकार चलाने वाले संत बन जाते हैं. मंत्री और नेता भ्रष्टाचार से लड़ने की कसमें खाते हैं. झूठा विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे काले धन को वापस लाने के सभी तरह के प्रयास कर रहे हैं. असलियत यह है कि सरकार देश की जनता और कोर्ट के सामने एक के बाद एक झूठ बोल रही है. पर्दे के पीछे से वह जनता के साथ धोखा कर रही है.

अब ज़रा भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में समझते हैं. यह समझौता पिछले साल अगस्त के महीने में भारत के वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी और स्विस फेडेरल कॉउंसलर मिशेलिन कैमे रे ने किया, जिसमें डबल टैक्सेशन समझौते में बदलाव करने पर दोनों राजी हुए. अब इस समझौते को क़ानूनी शक्ल देने के लिए बीते 17 जून को स्विट्जरलैंड की संसद ने इसे पारित कर दिया. स्विट्जरलैंड की संसद में पारित होने के बाद इसे क़ानून बनने में 90 से 100 दिन लगेंगे. प्रकाश चंद्र के मुताबिक़, जब यह समझौता बतौर क़ानून लागू हो जाएगा, उसके बाद भारत सरकार जिस भी बैंक खाते के बारे में जानकारी लेना चाहे, वह मिल सकती है. मतलब यह क़ानून उन्हीं खातों पर लागू होगा, जो इस क़ानून के लागू होने के बाद खोले जाएंगे. अब सवाल यही है कि जब इस क़ानून के दायरे में पहले से चल रहे बैंक खाते नहीं आएंगे, तब इस क़ानून का भारत के लिए क्या मतलब है. इस क़रार से भारत को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुक़सान होगा, क्योंकि अब हमने पुराने खातों के बारे में जानकारी लेने का अधिकार ही खो दिया है. अब जब जांच एजेंसियां पुराने खातों के बारे में कोई जानकारी लेना चाहेंगी तो स्विट्जरलैंड की सरकार यह क़रार दिखा देगी और कहेगी कि यह खाता क़ानून लागू होने से पहले का है, हम कोई जानकारी नहीं देंगे. अब सवाल यह है कि भारत सरकार और वित्त मंत्री ने ऐसा करार क्यों किया. देश के लोग स्विस बैंकों में काला धन जमा करने वाले अपराधियों को सज़ा दिलाना चाहते हैं और एक तरफ सरकार है, जिसके कामकाज से तो यही लगता है कि वह साम-दाम-दंड-भेद लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश में लगी है.

ऐसी ही राय देश के सुप्रीम कोर्ट की है. सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के मामले पर एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया है, जिसमें जांच की सारी ज़िम्मेदारी सरकार से छीनकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दी गई है. इस टीम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जीवन रेड्डी और जस्टिस एम बी शाह ने अपने आदेश में कई बातें लिखी हैं. सबसे गंभीर बात यह है कि सरकार जो भी कोशिश कर रही है, वह पर्याप्त नहीं है. मतलब यह कि सरकार काले धन के गुनाहगारों को पकड़ने और काला धन वापस लाने को ज़्यादा महत्व नहीं दे रही है. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच का ज़िम्मा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथों में दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ़-साफ़ कहा कि सरकार की यह विफलता एक गंभीर चूक है, जिसका असर देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर पड़ता है, लेकिन सरकार ने सुरक्षा के नज़रिए से इसकी कभी जांच की ही नहीं है. कोर्ट ने कहा कि यह समस्या बहुत पेंचीदा है और कई सरकारी एजेंसियों और विभागों से जैसी उम्मीद थी, उन्होंने वैसा नहीं किया. उन्होंने न तो तत्परता दिखाई और न इस मामले को गंभीरता से लिया. जांच के संदर्भ में पूछे गए सवालों का जवाब केंद्र सरकार से नहीं मिला है कि जांच इतनी धीमी क्यों है. कोर्ट की इस बात का भी सरकार ने जवाब नहीं दिया कि नियम बदल कर स्विट्जरलैंड के यूबीएस बैंक को भारत में रिटेल बैंकिंग करने की अनुमति क्यों दी गई. जबकि इस बैंक को पहले यह दलील देकर लाइसेंस नहीं मिला था कि इसकी भूमिका संदेहास्पद रही है. सरकार ने जवाब में कहा था कि इससे विदेशी निवेश में फ़ायदा होगा. तो सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि क्या हम विदेशी पैसे के लिए देश के क़ानून को ताख पर रख देंगे. सरकार वैसे सुप्रीम कोर्ट को बार-बार यही बताती रही कि वह विदेश में जमा काले धन को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. सरकार कोर्ट में झूठ बोलती रही है, क्योंकि हर बार वह साथ ही यह भी कहती रही कि उसे दूसरे देशों के क़ानून के मुताबिक काम करना पड़ता है, इसलिए यह थोड़ा मुश्किल है. सरकार को यह बताना चाहिए कि जिस नियम-क़ानून का वह हवाला दे रही है, वही नियम-क़ानून तो दूसरे देशों पर भी लागू होता है तो फिर यह कैसे हुआ कि जब अमेरिका ने अपने नागरिकों की लिस्ट मांगी तो उसे मिल गई. अमेरिका ने स्विस बैंकों में काला धन जमा करने वालों के ख़िलाफ़ एक सफल अभियान चलाया. अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बीच कोई संधि भी नहीं हुई, फिर भी सारे खातों की जानकारी स्विट्जरलैंड ने उसे दे दी. अब तो अमेरिका इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कि जिन बैंक अधिकारियों ने इन खातों को खुलवाया या देखरेख की, उन्हें सज़ा मिले. अमेरिका में अब तक 600 से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है. एक भारत की सरकार है, जिसने ऐसे लोगों को पकड़ने के बजाय ऐसा समझौता कर लिया, जिसके बाद काला धन वापस लाना तो दूर, यह भी पता नहीं चल पाएगा कि स्विस बैंकों में किसके-किसके खाते थे और इन महापुरुषों ने भारत का कितना पैसा लूटा. सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश में यह कहना पड़ा कि काले धन के मुद्दे को गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है और यह सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी बनती है कि वह ऐसी संपदा देश में वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास करे और विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वालों को दंडित करे. क़ानून की अपनी ज़ुबान होती है, जज जब लिखते हैं तो उनका अपना सलीका होता है. जब सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़े तो समझा जा सकता है कि कोर्ट ने अब यह मान लिया है कि सरकार काले धन के गुनाहगारों को पकड़ने की इच्छुक नहीं है. जिस तरह देश की जनता को उन लोगों के नामों का इंतजार है, ठीक वही निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, क्योंकि अब तक सरकार यह भी बताना नहीं चाहती है कि काले धन के मामले में किन-किन लोगों से पूछताछ हुई है. लिचटेंस्टीन बैंक की लिस्ट में शामिल लोगों पर जांच चल रही है भी या नहीं. सरकार की गोपनीयता अब देश को खटक रही है.

सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरी घटना घटी. सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने इस्तीफ़ा दे दिया. सरकार ने जानबूझ कर उन्हें अपमानित करने की कोशिश की. अब सवाल यह है कि सरकार गोपाल सुब्रमण्यम को क्यों अपमानित करना चाह रही है, क्या नाराज़ होकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया? असल कहानी कुछ और ही है. सुप्रीम कोर्ट ने काले धन की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी. बताया यह गया कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गोपाल सुब्रमण्यम की दलीलों पर आधारित था. सरकार को लगा कि सॉलिसिटर जनरल ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह काम किया. इस आदेश के अगले ही दिन इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वित्त मंत्रालय को यह सूचित किया कि वह गोपाल सुब्रमण्यम के कथनों से सहमत नहीं है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का प्रवर्तन निदेशालय और सरकार दोनों ही विरोध कर रहे हैं. ये नहीं चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इस जांच का नेतृत्व करें, लेकिन अदालत में गोपाल सुब्रमण्यम ने इस पर सहमति दे दी. इससे पहले भी गोपाल सुब्रमण्यम सरकार के निशाने पर रह चुके हैं, जब 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की निष्क्रियता पर हलफ़नामा मांगा था. सरकार की तरफ़ गोपाल सुब्रमण्यम कोर्ट में दलील दे रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्हें हटाकर एटॉर्नी जनरल जी ई वाहनवती को इस मामले में लगाया गया. सरकारी महकमे गोपाल सुब्रमण्यम से इसलिए नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में वह सरकार को बचा नहीं पाए. यही वजह है कि टेलीकाम मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने उनके रहते हुए किसी प्राइवेट वकील को हायर कर लिया. इस घटना से सरकार को यह सबक लेने की ज़रूरत है कि काले धन और घोटालों के मामलों में वह किस जगह पर खड़ी है. कोर्ट और देश की जनता का नज़रिया इन मामलों पर क्या है. सुप्रीम कोर्ट अगर काले धन की जांच तेज़ करना चाहता है, जांच में पारदर्शिता लाना चाहता है तो इसमें क्या ग़लत है?

मीडिया में कई लोग यह बहस कर रहे हैं कि जांच कराने का काम सरकार का है और अदालत को इससे दूर रहना चाहिए. अब यह समझ में नहीं आता है कि मीडिया के ये दिग्गज ऐसा क्यों कह रहे हैं. उन्हें यह भी जवाब देना चाहिए कि अगर सरकार अपना काम ठीक से नहीं करती है तो उसकी सज़ा क्या हो, किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाए. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से सरकारी तंत्र पर जनता का विश्वास बना हुआ है, वरना जिस तरह सरकार भ्रष्टाचार और काले धन के मामले पर टालमटोल कर रही है, उससे तो जनता का विश्वास ही टूट जाएगा. काला धन और भ्रष्टाचार को लेकर देश की जनता चिंतित है. आज जो माहौल है, उसमें तो यही कहा जा सकता है कि जो भी काले धन और भ्रष्टाचार से नहीं लड़ेगा, उसे इसका समर्थक मान लिया जाएगा. जब 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया तो सरकार ने कहा कि सब कुछ नियम-क़ानून के दायरे में हुआ है. कपिल सिब्बल ने अपनी सारी बुद्धि सरकार को बचाने में लगा दी. परिणाम क्या हुआ? ए राजा, कनीमोई और कंपनियों के मालिक जेल में हैं और सरकार कठघरे में है. सरकार के पास विदेशों में काला धन जमा कराने वालों की लिस्ट है, लेकिन वह उसे सार्वजनिक नहीं कर रही है. ऐसे में तो लोग यही समझेंगे कि सरकार काले धन के गुनाहगारों को बचा रही है. साथ ही सरकार ने स्विट्जरलैंड के साथ यह शर्मनाक समझौता करके एक और गलती की है. सुप्रीम कोर्ट पर जनता का भरोसा है. देखना यह है कि सरकार की इस भूल को सुप्रीम कोर्ट कैसे सुधारती है और काले धन को वापस लेकर आती है.

जब भारत-स्विट्जरलैंड समझौता बतौर क़ानून लागू हो जाएगा, उसकेबाद भारत सरकार जिस भी बैंक खाते के बारे में जानकारी लेना चाहे, वह मिल सकती है. मतलब यह क़ानून उन्हीं खातों पर लागू होगा, जो इस क़ानून के लागू होने के बाद खोले जाएंगे. अब सवाल यही है कि जब इस क़ानून के दायरे में पहले से चल रहे बैंक खाते नहीं आएंगे, तब इस क़ानून का भारत के लिए क्या मतलब है. इस क़रार से भारत को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुक़सान होगा, क्योंकि अब हमने पुराने खातों के बारे में जानकारी लेने का अधिकार ही खो दिया है. अब जब जांच एजेंसियां पुराने खातों के बारे में कोई जानकारी लेना चाहेंगी तो स्विट्जरलैंड की सरकार यह क़रार दिखा देगी और कहेगी कि यह खाता क़ानून लागू होने से पहले का है, हम कोई जानकारी नहीं देंगे.

manish@chauthiduniya.com

वनाधिकार क़ानून के तहत अब किसी भी वन समुदाय को उसकी मर्ज़ी के बग़ैर वन क्षेत्र से हटाया नहीं जा सकता.

अन्ना का प्रस्तावित आमरण अनशन

सरकारी दमन से निपटने की तैयारी क्या है

फोटो- प्रभात पाण्डेय

डॉ. सुनीलम

अन्ना ने मज़बूत लोकपाल बिल पेश न किए जाने की स्थिति में आगामी 16 अगस्त से आमरण अनशन की घोषणा की है. सरकार ने अनशन न करने देने का मन बना रखा है. बाबा रामदेव और उनके साथी आंदोलनकारियों को लाठी के दम पर खदेड़ कर सरकार ने साफ़ कर दिया है कि उसे अन्ना और उनके समर्थकों को खदेड़ने में कोई वक़्त नहीं लगेगा. सरकार से निपटने के लिए अन्ना और उनके समर्थकों की क्या तैयारी है, यह पूरा देश जानना चाहता है. अब तक उन्होंने केवल समर्थकों से सड़कों पर निकलने की अपील मात्र की है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेकर सड़क पर निकलने भर से आंदोलन सफल होने वाला नहीं है. विश्लेषकों का मानना है कि अन्ना की सफलता राजधानी क्षेत्र, एनसीआर से मिलने वाले समर्थन पर निर्भर करेगी. यदि दिल्ली और आसपास के इलाक़ों से लाखों की संख्या में आम नागरिक 16 अगस्त को राजधानी के लिए निकल पड़ें तो जल्दी नतीजे निकलने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन यह मानने वालों की कमी नहीं है कि सरकार दिल्ली की सीमाओं को सील कर अन्ना समर्थकों को जंतर-मंतर पर आने से रोक सकती है.

यदि सरकार जंतर-मंतर पर धारा 144 लगा दे और राजघाट जैसा कोई विकल्प न दे, तब अन्ना क्या करेंगे? सरकार शांति भंग होने की आशंका की आड़ में अन्ना के दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी भी लगा सकती है. ऐसी स्थिति में यदि अन्ना दिल्ली के बाहर अनशन शुरू करते हैं, तब उसका असर सरकार पर क्या पड़ेगा, यह आकलन अभी करना जल्दबाज़ी होगी. कम से कम रामदेव का हरिद्वार का अनशन तो यही बताता है कि दिल्ली से हटते ही आंदोलन की ताक़त कमज़ोर दिखलाई देने लगती है. यह तो तय है कि आंदोलन देश के कोने-कोने में चलेगा. अन्ना और उनके समर्थकों की तैयारी पहले से अधिक है. इसलिए कहा जा सकता है कि आंदोलन अधिक संगठित एवं सुनियोजित होगा, लेकिन अभी तक अन्ना ने आंदोलन चलाने के लिए किसी भी संगठन की घोषणा नहीं की है. वह इसे अभियान के तौर पर चलाना चाहते हैं, जिसमें देश का हर नागरिक भागीदारी कर सके. लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि जे पी और वी पी ने जब आंदोलन चलाए थे, तब उनके पास पार्टियों का संगठन था, इसके बावजूद भ्रष्टाचार को रोक पाने के संदर्भ में देश का आम नागरिक दोनों को विफल मानता है. ऐसी स्थिति में अन्ना बिना संगठन के क्या कुछ कर पाएंगे, यह विचारणीय प्रश्न है. सरकार आंदोलनों के धैर्य की परीक्षा लेती है. वह आंदोलन को विफल करने के लिए दमन का सहारा लेती है और उसे विभाजित करने की कोशिश भी करती है. सरकार यदि अन्ना के साथ दोनों रणनीतियां अपना कर भी विफल हो जाती है तो उसका प्रयास आंदोलनकारियों के बीच अपने लोगों की घुसपैठ कराकर हिंसा फैलाने का होगा. यदि अन्ना का अनशन लंबा खिंचता है और देश के नागरिकों को यह लगने लगता है कि अन्ना की जान खतरे में है, तब पूरे आंदोलन का भावना प्रधान हो जाना तय है. इस स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार देश भर में या कुछ स्थानों पर हिंसा फैलाने का षड्यंत्र कर सकती है, जिसकी आड़ में उसे अधिक दमन करने का मौक़ा मिलेगा और कहा जा सकेगा कि चौरीचौरा के आंदोलन के दौरान हिंसा फैलने के बाद यदि गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले सकते हैं तो अन्ना को भी देश हित में आंदोलन वापस ले लेना चाहिए.

संसद का सत्र शुरू होने और बिल पेश किए जाने के बाद सरकार सबसे पहले तो यह साबित करने की कोशिश करेगी कि मज़बूत लोकपाल बिल लाया गया है. सरकार के हर क़दम को उचित बताने वाले बुद्धिजीवी एनईसी के माध्यम से अपने तिकड़म शुरू कर चुके हैं. अख़बारों में इन बुद्धिजीवियों के लेख भी लगातार प्रकाशित हो रहे हैं. सरकार की रणनीति यह बताने की होगी कि अन्ना के साथ नागरिक समाज नहीं है. सोनिया टीम के माध्यम से सरकार यह बताएगी कि नागरिक समाज बंटा हुआ है. सरकार की रणनीति मीडिया और घुसपैठियों के माध्यम से अन्ना और रामदेव को आमने-सामने खड़ा करने की रही है. बीच में एक-दूसरे के ख़िलाफ़ तल्ख बयान देकर दोनों यदाकदा सरकार के षड्यंत्र में फंसते दिखाई दिए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने की इच्छा रखने वाला आम नागरिक चाहता है कि दोनों एक-दूसरे का साथ दें. जब अन्ना ने अनशन किया, तब कई लोगों ने कहा कि रामदेव को ख़त्म करने के लिए यह सरकारी प्रयास है, लेकिन जब रामदेव को चार मंत्री लेने पहुंच गए, तब लोगों को लगा कि जन लोकपाल बिल के लिए कमेटी बनाकर सरकार घिर चुकी है, इस कारण उसकी कोशिश बाबा को साथ लेने की है. बाबा के मंच पर ऋतंभरा-आरएसएस के आने से बाबा की लोकप्रियता एकदम सिकुड़ गई, लेकिन पुलिसिया दमन ने बाबा को फिर दम दे दिया. अगर रामदेव और उनके समर्थकों ने असली सत्याग्रही के तौर पर मुक़ाबला किया होता तो बाज़ी पलट सकती थी. सरकार द्वारा हरिद्वार पहुंचाए जाने के बाद बाबा के अस्पताल पहुंचने पर जल्दबाजी में अनशन समाप्त कर देने से बाबा की छवि पर असर पड़ा है.

अन्ना और उनके समर्थकों की तैयारी पहले से अधिक है. इसलिए कहा जा सकता है कि आंदोलन अधिक संगठित एवं सुनियोजित होगा, लेकिन अभी तक अन्ना ने आंदोलन चलाने के लिए किसी भी संगठन की घोषणा नहीं की है. वह इसे अभियान के तौर पर चलाना चाहते हैं, जिसमें देश का हर नागरिक भागीदारी कर सके.

सरकार की रणनीति लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को बदनाम करने की थी, लेकिन टीम अन्ना बिना दाग़दार हुए इससे उबर गई. अब सरकार की कोशिश बाबा को बदनाम करने की है. उम्मीद करनी चाहिए कि वह जल्द ही इस षड्यंत्र से निपटने में कामयाब होंगे. अन्ना और बाबा दोनों यदि तय कर लें कि वे एक- दूसरे को पूरा साथ देंगे और किसी के उकसावे में नहीं आएंगे तो दोनों मिलकर सरकार से मुक़ाबला कर सकते हैं. दोनों आंदोलन आम लोगों के इर्द-गिर्द थे, लेकिन दोनों की टीमें मीडिया ने बना दीं. यदि ये दोनों टीमें एक साथ काम करना शुरू कर दें और देश भर के जनांदोलनों के नेतृत्व से मिलकर एक सामूहिक नेतृत्व पेश करें तो 16 अगस्त से होने वाले आंदोलन में नई ऊर्जा दिखाई पड़ेगी. सवाल यह है कि 16 अगस्त के आंदोलन को यदि सरकार कुचलने का मन बनाती है तो देश में क्या स्थिति बनेगी? किसी भी पुलिसिया कार्रवाई से अन्ना के आंदोलन को ताक़त मिलना तय है, क्योंकि अब तक अन्ना के साथ आंख मिचौली खेल रहीं तमाम पार्टियां पुलिस दमन के ख़िलाफ़ बोलने के लिए उसी तरह मजबूर होंगी, जैसे रामदेव पर कार्रवाई के बाद हुई थीं. किंतु-परंतु के साथ सत्तारूढ़ दल के नेताओं को भी उस दमन की निंदा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था.

देश भर में आंदोलनकारियों की जमात में अधिकतर धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग शामिल हैं. आज धीरे-धीरे पूरा वातावरण कांग्रेस-यूपीए के ख़िलाफ़ होता चला जा रहा है. भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखने वालों के लिए तात्कालिक मुद्दा कांग्रेस मुक्त केंद्र सरकार हो सकता है. यदि भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर आंदोलन ज़ोर पकड़ता है तो अगले आम चुनाव समय से पूर्व कराने की स्थिति बन सकती है. आंदोलनकारी अब तक जो रुख़ सार्वजनिक करते रहे हैं, उससे साफ़ है कि फ़िलहाल वे चुनाव के चक्कर में नहीं हैं, उनकी रुचि सत्ता परिवर्तन में नहीं है. इस मायने में अब तक यह आंदोलन जे पी आंदोलन से अलग है. हालांकि शुरुआती दौर में जे पी आंदोलन सत्ता परिवर्तन का नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी थोपे जाने के बाद आंदोलन की दिशा यूं बदली कि संपूर्ण क्रांति का सपना देख रहे जे पी को भी सत्ता परिवर्तन की बात खुलकर कहनी पड़ी और जनता पार्टी के गठन में ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह करना पड़ा. जब सत्ता परिवर्तन की बात होती है, तब आम आदमी को लगता है कि कौन से दल दूध के धुले हैं. भारतीय राजनीति दो ध्रुवों में सिमट चुकी हैं, पहला कांग्रेस-यूपीए और दूसरा भाजपा-एनडीए है, जिनके प्रति आंदोलनकारियों की झिझक किसी से छिपी नहीं है. कांग्रेस भ्रष्टाचार के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए सांप्रदायिकता का कार्ड चलाने की रणनीति बनाए हुए है, इसीलिए वह दोनों आंदोलनों के पीछे आरएसएस का हाथ बता रही है. यदि आंदोलनकारी इस षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे तो वे मज़बूती के साथ सरकार का मुक़ाबला करने और सत्ता परिवर्तन में अवश्य कामयाब होंगे. जहां तक भ्रष्टाचार ख़त्म करने का सवाल है तो पूरा देश मानता है कि केवल जन लोकपाल बिल भ्रष्टाचार ख़त्म करने में कामयाब नहीं होगा, लेकिन इस बिल को लागू करने वाली सरकार यदि दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति रखे तो वह भ्रष्टाचारियों पर एक सीमा तक अंकुश लगाने में कामयाब हो सकती है. जिस तरह दहेज प्रथा केवल क़ानून से नहीं रोकी जा सकी, अनुसूचित जाति-जनजातियों पर अत्याचार नहीं रोका जा सका, उसी तरह केवल क़ानून बनाकर भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं किया जा सकता. अन्ना-रामदेव एवं उनके समर्थक आंदोलनकारियों को सामाजिक स्तर पर भ्रष्टाचारियों पर दबाव बनाने और उनका सामाजिक बहिष्कार करने के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा.

(लेखक पूर्व विधायक एवं किसान संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुलिस की तानाशाही और वन गूजरों की जीत

रजनीश

देश में वनाधिकार क़ानून लागू होने के बावजूद वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके मूल स्थान से भगाने के प्रयास किए जाते रहते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. पिछले दिनों ऐसा ही एक मामला सामने आया. राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच के वन गूजर नूर जमाल की गिरफ्तारी के विरोध में वन गूजरों और टांगिया गांव की महिलाओं ने बीते 29 जून को सहारनपुर की बेहट तहसील अंतर्गत आने वाले थाना बिहारीगढ़ का घेराव कर पुलिस को उसे बिना शर्त रिहा करने को मजबूर कर दिया. जानकारी के अनुसार, बीते 28 जून को उत्तराखंड स्थित राजाजी नेशनल पार्क अंतर्गत आने वाली मोहंड रेंज की झूठी तहरीर पर उत्तर प्रदेश के थाना बिहारीगढ़ की पुलिस ने वन गूजर समुदाय के तीन लोगों नूर जमाल, जहूर हसन एवं इरशाद के ख़िलाफ़ धारा 332, 186 और 427 के तहत मुक़दमा दर्ज कर नूर जमाल को गिरफ्तार कर लिया था.

इससे पूर्व 24 जून को जब ये तीनों लोग पार्क क्षेत्र में बसे अपने डेरे पर जा रहे थे, तब मोहंड रेंज के रेंजर महावीर सिंह नेगी ने रास्ते में इन्हें रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी. इरशाद अपनी जिस मोटरसाइकिल पर जा रहा था, उसे छीन लिया गया और धमकी दी गई कि अगर जंगल क्षेत्र छोड़कर बाहर नहीं गए तो गोली से उड़ा दिए जाओगे. मामला उत्तराखंड के बुग्गावाला क्षेत्र का होने के कारण रेंजर के ख़िलाफ़ थाना बुग्गावाला में उन्होंने तहरीर दी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. इधर रेंजर महावीर नेगी ने थाना बिहारीगढ़ के थानाध्यक्ष दिगंबर सिंह से साठगांठ करके महिला वनकर्मी बबलेश की ओर से रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके आधार पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस नूर जमाल को घर से उठाकर थाने ले आई. नूर जमाल की गिरफ्तारी को लेकर पार्क क्षेत्र में बसे वनगूजर और वनटांगिया समुदाय के लोगों में आक्रोश फैल गया.

इसके बाद राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच के बैनर तले राज्यस्तरीय वनाधिकार निगरानी समिति की विशेष आमंत्रित सदस्य रोमा, मंच के सदस्य रजनीश, हरी सिंह, विपिन गैरोला, प्रद्युम्न के साथ दोनों वन समुदायों की महिलाओं ज़ैनब एवं सीता आदि की अगुवाई में 500 से अधिक लोगों ने थाना बिहारीगढ़ का घेराव कर लिया. महिलाओं ने थाना कार्यालय के दोनों दरवाज़े बंद कर पुलिसकर्मियों को यह कहकर क़ैद कर लिया कि जब तक नूर जमाल को बाइज़्ज़त रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक पुलिसकर्मियों को भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा. थाने का बरामदा एक जनसभा स्थल में तब्दील हो गया और वहां रखी मेज़ को मंच बनाकर भाषण दिए जाने लगे. पुलिस मूकदर्शक बनी यह सब देखती रही. किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वह दमन से उपजे इस जन विरोध का सामना कर सके. थानाध्यक्ष ने मामला अपने हाथ से निकलता देख पड़ोसी थाना फतेहपुर के थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी बेहट को बुला लिया. प्रदर्शनकारी महिलाओं ने क्षेत्राधिकारी को घटना और उसके वनाधिकार क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया से जुड़े होने की जानकारी दी तो उन्होंने मामले की सत्यता को समझ कर स्वीकार किया कि थानाध्यक्ष ने एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. उन्हें बताया गया कि वनाधिकार क़ानून के तहत अब किसी भी वन समुदाय को उसकी मर्ज़ी के बग़ैर वन क्षेत्र से हटाया नहीं जा सकता. इस बारे में नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा वनगूजरों के पक्ष में 2007 में वनाधिकार क़ानून को संज्ञान में लेते हुए आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन पार्क प्रशासन द्वारा 2008 में जहूर हसन और नूर जमाल के डेरों को लूटकर आग के हवाले कर दिया गया. पार्क प्रशासन लगातार तरह-तरह के हथकंडे अपना कर वन गूजरों को वन क्षेत्र से भगाने की कोशिशें करता रहता है. रेंजर द्वारा महिला से दिलवाई गई तहरीर भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है. उन्होंने सारी बात समझते हुए न सिर्फ़ नूर जमाल को बिना शर्त बाइज़्ज़त रिहा किया, बल्कि वन गूजरों की ओर से रेंजर महावीर नेगी के ख़िलाफ़ दी गई तहरीर लेते हुए उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया. इसके बाद सभी लोग नूर जमाल को लेकर मोहंड रेंज कार्यालय पहुंचे. यहां लोगों के आने की ख़बर पाकर कर्मचारी पहले से ही भाग खड़े हुए, लेकिन लोगों ने रेंज कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ज़बरदस्त नारेबाज़ी की और दीवारों पर लिखकर चेतावनी दी कि अगर पार्क प्रशासन द्वारा यहां बसे वन गूजर और टांगिया समुदायों का उत्पीड़न नहीं रोका गया तो पार्क निदेशक रसैली सहित सभी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ ग्राम समितियों की ओर से वनाधिकार क़ानून 2006 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

उत्तर प्रदेश सरकार एक ओर वनाधिकार क़ानून के क्रियान्वयन को अपना राजनीतिक एजेंडा मानकर तरह-तरह के आदेश-निर्देश जारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और वन विभाग सरकार की मंशा पर पलीता लगाने पर तुले हुए हैं. उत्तराखंड में भी इस क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया बाधित की जा रही है, जिसका उदाहरण बिहारीगढ़ की घटना है. राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन और उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश पुलिस की तानाशाही के ख़िलाफ़ महिलाओं के नेतृत्व में किए गए संघर्ष की यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण जीत थी.

feedback@chauthiduniya.com

विकास के नाम पर बिहार में सिर्फ़ सड़कें बनीं. ज़ाहिर तौर पर उनमें से ज़्यादातर सड़कें केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत बनी थीं.

विशेष राज्य का दर्जा

बिहार की ज़रूरत या फिर राजनीति

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

शशि शेखर

गन्ना बिहार की एक मुख्य फ़सल है और लाखों लोगों के जीवनयापन का साधन भी. नीतीश सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में घोषणा की कि गन्ने से इथेनॉल बनाने के लिए कंपनियों को बिहार आमंत्रित किया जाएगा. शुरुआत में कई बड़ी कंपनियों ने इसमें रुचि भी दिखाई. तब कहा गया था कि इससे बिहार की क़िस्मत बदल जाएगी. इस बात में दम भी था, क्योंकि ऐसा होने से बिहार चीनी और इथेनॉल के उत्पादन में अग्रणी राज्य बन जाता, लेकिन सरकार की इस पूरी क़वायद में केंद्र सरकार की एक नीति ने पेंच फंसा दिया. उसके मुताबिक़ गन्ने से इथेनॉल नहीं बनाया जा सकता. नतीजतन, बड़ी कंपनियों ने अपने हाथ खींच लिए. ज़ाहिर है, यह बिहार और वहां के लोगों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन बिहार के किसी भी राजनीतिक दल ने केंद्र सरकार से यह नियम बदलने की मांग नहीं की और न आंदोलन किया. बिहार के विकास की बात करने वाले नीतीश कुमार या उनकी पार्टी की ओर से भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया. अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन की बात कर रहे हैं. हालांकि बिहार बंटवारे को दस साल से ज़्यादा हो गए और बंटवारे के वक़्त से ही विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग राजनीतिक दल करते रहे हैं. ग़ौर करने की बात यह है कि जब राज्य का बंटवारा हुआ था, तब केंद्र में एनडीए और बिहार में राजद का शासन था, लेकिन तब एनडीए ने बिहार को न तो विशेष पैकेज दिया और न ही विशेष राज्य का दर्जा. जब एनडीए की सरकार गई, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सत्ता में आई. अब नीतीश कुमार विशेष पैकेज और विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं और बाक़ायदा इसके लिए हस्ताक्षर अभियान और आंदोलन तक छेड़ दिया गया है. सवा करोड़ बिहारियों के हस्ताक्षर प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की क़वायद की गई. जनता दल के नेता बीते 13 जुलाई को दिल्ली के जंतर–मंतर पर पहुंचे. विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर पार्टी का हस्ताक्षर अभियान महीनों से चल रहा था. जंतर–मंतर पर जद (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने केंद्र सरकार पर बिहार के ख़िलाफ़ साजिश करने की बात कही, भेदभाव करने का आरोप लगाया. शरद यादव ने केंद्र सरकार से चेतावनी के लहजे में कहा कि अगर बिहार पिछड़ा रहेगा तो पूरा देश पिछड़ जाएगा. बहरहाल, इस हस्ताक्षर अभियान और विशेष राज्य के दर्जे की मांग के पीछे की कहानी क्या है? आख़िर नीतीश कुमार को विशेष पैकेज की याद अपने दूसरे कार्यकाल में इतनी शिद्दत के साथ क्यों आ रही है? दरअसल, नीतीश कुमार अपने पहले कार्यकाल में सड़क और क़ानून व्यवस्था दुरस्त करने के नाम पर दूसरी बार सत्ता पा गए. विकास के नाम पर बिहार में सिर्फ़ सड़कें बनीं. ज़ाहिर तौर पर उनमें से ज़्यादातर सड़कें केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत बनी थीं. बिजली आज भी पटना को छोड़कर बिहार के बाक़ी ज़िलों के लिए दूर की कौड़ी बनी हुई है. जिस निवेश की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह असल में सिर्फ़ काग़ज़ों तक ही सीमित है. जहां कहीं भी छोटे–मोटे उद्योग लगाए जा रहे हैं, वहां भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर जन विरोध का सामना करना पड़ रहा है. मुजफ्फ़रपुर और फारबिसगंज में यही हुआ. फारबिसगंज में तो एक कारख़ाने का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग तक की गई. दरअसल बाढ़, बिजली, विकास, अपराध और भ्रष्टाचार से हारी हुई नीतीश सरकार अब अगले चुनावों (लोकसभा और विधानसभा) की तैयारी में जुट गई है और इसके लिए विशेष पैकेज, विशेष राज्य के दर्जे से अच्छा मुद्दा और क्या हो सकता था. असल में यह एक भावनात्मक मुद्दा है, जिसके सहारे जनता को बरगलाया जा सकता है. ख़ुद कुछ न कर पाने की स्थिति में सीधे–सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा सकता है. यह कहकर कि केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज के तहत पैसा नहीं दिया. अब इसे क्या कहा जाएगा, एक ओर तो बिहार सरकार केंद्र से पैसा पाने के लिए विशेष पैकेज मांग रही है, वहीं दूसरी ओर अपने विधायकों का वेतन–भत्ता कई गुना बढ़ा चुकी है. सवाल है कि आख़िर नीतीश कुमार बिहार के कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर ध्यान देने के बजाय जनता का ध्यान विशेष पैकेज और विशेष राज्य की ओर क्यों खींचना चाहते हैं?

shashishekhar@chauthiduniya.com

बिहार बंटवारे को दस साल से ज़्यादा हो गए और बंटवारे के वक़्त से ही विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग राजनीतिक दल करते रहे हैं. ग़ौर करने की बात यह है कि जब राज्य का बंटवारा हुआ था, तब केंद्र में एनडीए और बिहार में राजद का शासन था, लेकिन तब एनडीए ने बिहार को न तो विशेष पैकेज दिया और न ही विशेष राज्य का दर्जा.

आज उदयन होते तो क्या करते

नई पीढ़ी के पत्रकारों और पाठकों के लिए उदयन शर्मा को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों वर्ग आज पत्रकारिता के उस स्वरूप से रूबरू हो रहे हैं, जहां स्थापित मूल्यों में क्षरण देखने को मिल रहा है. उद्देश्य में भटकाव और विचलन की स्थिति है. युवा वर्ग के साथ ही वह पीढ़ी भी, जिसने कभी रविवार और उदयन शर्मा के धारदार लेखन को पढ़ा, देखा या उसके बारे में जाना है, पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नज़र नहीं आ रही है. ऐसे माहौल में स्वर्गीय उदयन शर्मा के 63वें जन्मदिन के मौक़े पर जब उनके साथ काम कर चुके पत्रकार अपनी राय, अपने अनुभव और मीडिया के सामने नई चुनौतियों के बारे में अपनी बात नई पीढ़ी के साथ साझा करते हैं तो पत्रकारिता के सुनहरे अतीत और वर्तमान हालत को समझने में मदद मिलती है. उदयन शर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से पिछले दस सालों से एक गोष्ठी का आयोजन किया जाता रहा है. इस बार भी 11 जुलाई को (उदयन शर्मा के जन्मदिन के मौक़े पर) दिल्ली में एक आयोजन हुआ, जिसमें दिग्गज पत्रकार, संपादक शामिल हुए. इस आयोजन का नाम था संवाद और विषय था भ्रष्टाचार का मुद्दा और मीडिया की भूमिका. दरअसल, यह विषय सामयिक था, साथ ही इसने ख़ुद मीडिया के लिए भी आत्मचिंतन का एक मौक़ा दिया. यह मौक़ा तब और अब की पत्रकारिता में फ़र्क़ को भी समझने का था.

इस सारी चर्चा से यह तो समझ में आता है कि वर्तमान समय के पत्रकार और संपादक पत्रकारिता की वर्तमान समस्याओं एवं चुनौतियों से चिंतित तो हैं, लेकिन यह दुःख भी होता है कि इन समस्याओं एवं चुनौतियों से निपटने के लिए वे कोई रोडमैप नहीं बना पाते हैं. सारी चिंताएं केवल चर्चा तक ही सीमित रह जाती हैं. ख़ुद को मुख्य धारा का मीडिया मानने वाले पत्रकार और संपादक भी केवल समस्याओं का ज़िक्र करके रह जाते हैं.

चर्चा की शुरुआत करते हुए चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारतीय ने कहा कि आज आचरण में जिस तरह का भटकाव है, विचलन है, वही भ्रष्टाचार है. आज वैचारिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक भ्रष्टाचार ही सभी तरह के भ्रष्टाचार का जनक है और ऐसे माहौल में मीडिया अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहा है. ज़ाहिर है, एक पत्रकार के रूप में स्टिंग ऑपरेशन, टेलीफोन पर बातचीत और घोटालों पर एक्सक्लूसिव स्टोरी के जरिए भ्रष्टाचार से नहीं लड़ा जा सकता है. इनका एक वक़्त था. इनका यह योगदान भी है कि आज देश में भ्रष्टाचार को लेकर इतनी जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अब इसका असर ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब जागरूकता अभियान चलाने का कोई मतलब नहीं रह गया है. जनता जागरूक हो चुकी है. अब भ्रष्टाचार से लड़ने का वक़्त आया है. इसलिए अगर भ्रष्टाचार एक आचरण है तो इसके लिए मीडिया को वैचारिक युद्ध ही करना पड़ेगा. मीडिया को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा. किसी चैनल या अख़बार को नहीं, बल्कि पूरे मीडिया को शक्तिशाली बनाना ज़रूरी है. इस मौक़े पर संतोष भारतीय पत्रकारिता से जुड़े चंद सवाल उठाते हैं. मसलन, वह पूछते हैं कि मीडिया ने इंवेस्टिगेशन करना बंद क्यों कर दिया है, ज़िम्मेदारी लेना बंद क्यों कर दिया है, ग़लती करने के बाद माफ़ी मांगना क्यों बंद कर दिया है, मीडिया के एजेंडे से ग़रीब, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक और वे सब जो आवाज़ नहीं उठा सकते, ग़ायब क्यों हो गए हैं? विडंबना यह है कि हमारे बीच के कई राजनीतिक संपादकों और कई राजनीतिक संवाददाताओं का चेहरा पार्टी कार्यकर्ताओं जैसा दिखने लगता है. कई लीडिंग नेशनल टीवी चैनल और पत्र–पत्रिकाएं राजनीतिक दलों के मुखपत्र की तरह बर्ताव करते हैं. ग़ौरतलब है कि संतोष भारतीय और उदयन शर्मा ने एक साथ रविवार में रहते हुए पत्रकारिता के नए प्रतिमान स्थापित किए थे. आज जब संतोष भारतीय यह कहते हैं कि अब तो हम (मीडिया) पर भी आरोप लग रहे हैं तो असल में यह बात पत्रकारिता के दो दौरों के उद्देश्य और सरोकारों के बीच के अंतर को ज़ाहिर करती है. स्टार इंडिया के सीईओ उदय शंकर ने मीडिया और समाज के बीच के सोशल कांट्रैक्ट का हवाला देते हुए कहा कि मीडिया को अपना काम करते समय इस सोशल कांट्रैक्ट का ख्याल रखना चाहिए. जबकि हिंदुस्तान हिंदी दैनिक के संपादक शशिशेखर ने मीडिया के कॉरपोरेटाइजेशन और इसकी वजह से आने वाली समस्याओं का ज़िक्र किया, साथ ही इस पेशे में नए एवं टैलेंटेड लोगों की कमी का भी ज़िक्र किया. पुण्य प्रसून वाजपेयी ने नई आर्थिक नीतियों को भ्रष्टाचार की वजह बताया और सीधे–सीधे यह कहकर प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़ा कर दिया कि आरटीआई के ज़रिए यह जानने की ज़रूरत है कि रोज़–रोज़ पीएमओ में उनसे मिलने कौन–कौन लोग आते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एस वाई कुरैशी ज़रूर मीडिया की पीठ थपथपाते हुए इसे अपना सहयोगी क़रार देते हैं, लेकिन यह सलाह भी देते हैं कि मीडिया को भी ख़ुद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, जबकि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी मीडिया के लिए सेल्फ रेगुलेशन की वकालत करती हैं. बहरहाल, इस सारी चर्चा से यह तो समझ में आता है कि वर्तमान समय के पत्रकार और संपादक पत्रकारिता की वर्तमान समस्याओं एवं चुनौतियों से चिंतित तो हैं, लेकिन यह दुःख भी होता है कि इन समस्याओं एवं चुनौतियों से निपटने के लिए वे कोई रोडमैप नहीं बना पाते हैं. सारी चिंताएं केवल चर्चा तक ही सीमित रह जाती हैं. ख़ुद को मुख्य धारा का मीडिया मानने वाले पत्रकार और संपादक भी केवल समस्याओं का ज़िक्र करके रह जाते हैं. वे यह नहीं बताते हैं कि आख़िर इन समस्याओं से निपटना कैसे है. जो लोग कुछ उपाय बताते भी हैं, उन पर अमल हो पाएगा, कहना मुश्किल है. मसलन, संतोष भारतीय कहते हैं कि एक एक्सक्लूसिव स्टोरी पर सभी मीडिया हाउसों को फॉलोअप स्टोरी करनी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार और शोषण के ख़िलाफ़ लड़ाई मज़बूत हो सके. ज़ाहिर है, यह एक नेक सलाह है, लेकिन क्या इस पर अमल भी हो पाएगा?

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की कि सांप्रदायिक हिंसा को उचित और सटीक शब्दों में परिभाषित किया जाए.

सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए क़ानून नहीं, इंसाफ़ की ज़रूरत

वसी अहमद नोमानी

भारत दुनिया का एक मज़बूत लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसने सभी महत्वपूर्ण धर्मों के मानने वालों को अपने यहां शरण दी. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय धार्मिक और आध्यात्मिक रहनुमाओं ने इस सरज़मीं को अपना आशियाना बनाया और पूरा जीवन मानवता के कल्याण, शांति और भाईचारे के लिए अर्पित कर दिया. लेकिन इसी सरज़मीं पर ऐसी मानसिकता वाले लोग भी मौजूद हैं, जिन्होंने इस मिट्टी की मोहब्बत की ख़ुशबू को अस्त-व्यस्त किया. इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सांप्रदायिक चेतना की रही. अक्सर भारत इस गंदी साज़िश से कांप उठता रहा है, लेकिन अपनापन, भाईचारे, प्रेम और एकता जैसे मानवीय तत्व हमेशा से इस देश की आत्मा में रचे-बसे रहे हैं, इसीलिए यह सरज़मीं पवित्रता की प्रतीक रही है और दूषित मानसिकता वालों को सज़ा देती रही है. भारत के इसी धर्मनिरपेक्ष भाईचारे और सहनशीलता की रक्षा के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद से क़ानून बनते रहे हैं. पिछले दो या तीन दशकों से ख़ामोशी के साथ और कभी दो टूक इस देश के पवित्र माहौल को बर्बाद करने के लिए क़दम उठाए जाते रहे हैं. परिणामस्वरूप यहां के जागरूक और बुद्धिमान लोगों ने साजिश करने वालों को सज़ा देने और उन्हें हतोत्साहित करने के लिए प्रभावी क़ानून बनाने की वकालत की है.

ऐसे ही प्रयासों के तहत सांप्रदायिक हिंसा निरोधक विधेयक 2005 (विरोध, कंट्रोल और पीड़ितों का पुनर्वास) के रूप में देश को एक सकारात्मक और प्रभावी क़ानून देने की योजना बनाई गई. इस विधेयक को सबसे पहले 5 दिसंबर, 2005 में राज्यसभा में पेश किया गया. कहा गया कि इस विधेयक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों को अधिकृत करना है कि वे यह क़ानून लागू करके देश में सांप्रदायिक सौहार्द क़ायम और मज़बूत रखने और ऐसा माहौल बनाए रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई करें, जिससे देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे, एकता और आंतरिक सुरक्षा का संरक्षण किया जा सके. साथ ही पीड़ितों का पुनर्वास और अन्य संबंधित मामलों को हल किया जा सके. यूपीए ने वर्ष 2004 के अपने चुनावी घोषणापत्र में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत यह वादा किया था कि ऐसा क़ानून बनाया जाएगा, जिसके द्वारा सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध जंग करने वालों के हाथों को मज़बूत किया जाएगा और फिर 2005 में वादे के अनुसार इस विधेयक को संसद में पेश कर दिया गया. इसके मसौदे को पढ़ने और उस पर विचार करने के बाद प्रसिद्ध विचारकों, क़ानूनविदों एवं स्वयंसेवकों, जो इसके लिए सक्रिय रहे हैं, ने इस विधेयक को ख़ारिज कर दिया और कहा कि उनके साथ केंद्र सरकार ने धोखा किया है. मांग की गई कि विधेयक में संशोधन किया जाए.

विरोधियों के आगे केंद्र सरकार ने घुटने टेके और विधेयक को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होम अफेयर्स को समीक्षा के लिए भेज दिया, लेकिन अफ़सोस की बात है कि जब कमेटी ने इस बिल को 6 दिसंबर, 2006 को संसद में पेश किया तो पर्याप्त संशोधन नहीं किए गए थे. 2005 से 2006 तक सिविल सोसायटी और सरकार के बीच कई बैठकें हुईं. गृहमंत्री, महत्वपूर्ण अधिकारियों और सांसदों से कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया. केंद्र सरकार ने इस विधेयक में लगभग 59 संशोधन करके केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेज दिया, जिसने अपनी ओर से इसकी पुष्टि कर दी. प्रत्यक्ष रूप से आंसू पोंछने के लिए कुछ क़दम उठाए गए, लेकिन सिविल सोसायटी के एक भी सुझाव को शामिल नहीं किया गया. अगर यह बिल पारित हो जाता और इसे क़ानून का रूप दे दिया जाता तो उन ताक़तों का मनोबल बढ़ता, जो माहौल को गंदा करके अपनी मंशा पूरी करने की ताक में रहते हैं. जबकि विधेयक का मक़सद भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को सुरक्षित और मज़बूत बनाना, सभी नागरिकों की सुरक्षा करना, इज़्ज़त-आबरू का सम्मान करना था. इस महान उद्देश्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी था कि केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे नियम और क़ानून तय करतीं, जिनसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और मानवीय मूल्यों की सुरक्षा सुनिश्चित होती और सरकार यह सब करने की अपनी जिम्मेदारी महसूस करती. केंद्र सरकार ने 2005 के सांप्रदायिक हिंसा निरोधक विधेयक में कुछ संशोधन किए और इसे ड्राफ्ट सांप्रदायिक हिंसा निरोधक विधेयक 2009 (विरोध, कंट्रोल और पीड़ितों का पुनर्वास) का नाम दे दिया. सरकार की इस निरर्थक कार्यवाही के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए विभिन्न मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने बीते एक अप्रैल को दिल्ली में एकत्र होकर दो टूक कहा कि सांप्रदायिक हिंसा निरोधक विधेयक 2009 (विरोध, कंट्रोल और पीड़ितों का पुनर्वास) अनुचित, अस्वीकार्य और काउंटर प्रोडक्टिव है. इन सबने सरकार से सख्ती से मांग की कि इस विधेयक की समीक्षा की जाए, क्योंकि तथाकथित 59 संशोधनों के बावजूद 2009 का विधेयक 2005 के विधेयक से भिन्न नहीं है, इसलिए जब तक महत्वपूर्ण संशोधन नहीं होते, 2009 का बिल अपने उद्देश्य प्राप्त करने में सफल नहीं होगा.

प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा कि दंगे की आशंका तब तक बरक़रार रहेगी, जब तक इसके विरोध के पर्याप्त प्रयास नहीं होंगे. जब तक सांप्रदायिक दंगे को तत्काल नियंत्रित करने का प्रभावी तरीक़ा नहीं अपनाया जाएगा, पीड़ितों एवं उत्तराधिकारियों के पुनर्वास के लिए भरपूर आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी, संपत्तियों की तबाही का मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा, दोषियों को चिन्हित करके मुक़दमा चलाकर सज़ा नहीं दी जाएगी और शासन-प्रशासन के जिम्मेदार लोगों को जेल भेजने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक 2009 का बिल भी किसी काम का नहीं होगा. प्रतिनिधियों की बात सुनकर केंद्र सरकार के कान खड़े हुए और फिर प्रस्तावों और मांगों पर ध्यान से विचार करने का काम शुरू हुआ. प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि यह बिल भी पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए कोई क़ानूनी व्यवस्था नहीं करता है. अगर अचानक दंगा हो जाए या फैल जाए या सप्ताह भर में नियंत्रित न हो पाए तो मानवाधिकार आयोग तक को भी कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रभावी तरीक़े से हस्तक्षेप करके पीड़ितों को न्याय दिला सके. अगर राज्य सरकार दंगा नियंत्रित न कर सके तो केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करके उसे भंग करा सके, इसकी भी कोई व्यवस्था इस बिल द्वारा नहीं की गई है. दूसरी ओर यह विधेयक पुलिस के हाथों को मज़बूत करता है. इस विधेयक द्वारा पुलिस को अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र को कम्युनिटी डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दे, बस उसका काम हो गया, क्योंकि ऐसा करने के बाद पुलिस को मनमानी करने का अधिकार मिल जाता है जैसा कि अब तक देखा गया है.

मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की कि सांप्रदायिक हिंसा को उचित और सटीक शब्दों में परिभाषित किया जाए, ताकि ऐसे अपराधों को आम दंडनीय अपराधों की श्रेणी से अलग करके इसकी अति का एहसास किया जा सके और इसके मुजरिमों का सामाजिक बहिष्कार हो और उनकी संपत्ति ज़ब्त कर ली जाए. राहत शिविरों को तब तक ख़त्म न किया जाए, जब तक पीड़ित अपने ठिकाने पर जाने की स्थिति में न हों. यह भी मांग की गई कि इस तरह की परिस्थितियों में तत्काल एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिए, घटना या अपराध की जांच विशेष जांच दल द्वारा हो. नामज़द अपराधियों, राजनीतिक नेताओं और पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विशेष अदालत में विशेष वकीलों, जो पीड़ितों को स्वीकार हों, द्वारा मुक़दमा चलाया जाए, सरकारी अधिकारियों के ख़िलाफ़ इस तरह के मुक़दमों के लिए अनुमति लेने की व्यवस्था को अनावश्यक घोषित किया जाए, पूरे देश में दंगा पीड़ितों को समान मुआवज़ा दिया जाए. इसके लिए धर्म, क्षेत्र, व्यक्तित्व और रुतबा आड़े नहीं आना चाहिए और न ही इसे आधार बनाना चाहिए. नुक़सान के अनुमान के लिए विशेष आयुक्त की सेवाएं ली जानी चाहिए, ताकि जांच और अनुमान के कामों में कोई अनुचित हस्तक्षेप न हो. इन तमाम प्रावधानों के बिना 2005 के विधेयक को 2009 के विधेयक के रूप में संसद में पेश नहीं किया जाना चाहिए. प्रतिनिधियों ने मांग की है कि जिस वर्ग के लोग धार्मिक योजना के तहत क़त्ल किए जाते हैं, उस वर्ग के सुझावों को शामिल किए बिना संसद में यह विधेयक पेश न किया जाए. देश की धर्मनिरपेक्ष ताक़तों, सिविल सोसायटी और राजनीतिक दलों ने भी कहा है कि सरकार जल्दी में विधेयक पेश न करे. पहले इसकी समीक्षा करे, ताकि कमियों को दूर किया जा सके और सभी को समान अधिकार दिलाए जा सकें. इस संयुक्त वक्तव्य पर मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों, विचारकों एवं बुद्धिजीवियों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, ताकि सरकार को मालूम हो सके कि पूरी मुस्लिम क़ौम प्रस्तावित सांप्रदायिक हिंसा निरोधक विधेयक 2009 (विरोध, कंट्रोल और पीड़ितों का पुनर्वास) को कमियों का एक बंद पिटारा समझती है. हस्ताक्षर करने वालों में सैय्यद हामिद, मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन, मौलाना अरशद मदनी, सैय्यद शहाबुद्दीन, डॉ. मोहम्मद मंज़ूर आलम, ज़फ़र सैफुल्लाह, असुद्दीन उवैसी, मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम एवं मौलाना एजाज़ अहमद असलम आदि शामिल हैं. जारी...

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... नया मंत्रिमंडल!

केमिस्ट बृजबाला के मुताबिक़, वर्ष 2009–10 के दौरान कुल 2804 जल नमूनों का परीक्षण उनकी लैब में किया गया, जो इंडिया मार्का हैंडपंपों के थे.

मैली हो गई पतित पावनी सरयू नदी

पानी में हानिकारक तत्वों की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है. शहर से सटे मसौधा ब्लॉक में भी पानी में नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि इंडिया मार्का हैंडपंपों की बोरिंग को और गहराई पर ले जाकर इन हानिकारक तत्वों से बचा जा सकता है, लेकिन यह ऐसा तरीक़ा है, जिसका इस्तेमाल नीतिगत निर्णय के बाद हो सकता है.

सियाराम यादव

अयोध्या–फ़ैज़ाबाद शहरों को अपने आंचल में समेट, युगों–युगों से लोगों को पुण्य अर्जन कराती सरयू नदी की कोख भी अब मैली हो चली है. सरयू का पवित्र जल तो दूषित हुआ ही, भूजल में भी हानिकारक रसायनों की मात्रा बढ़ती जा रही है. दोनों शहरों के क़रीब दो दर्जन इंडिया मार्का हैंडपंपों में नाइट्रेट, आयरन आदि तत्वों की अधिकता पाई गई है. पानी में कठोरता और खारापन भी ज़रूरत से ज़्यादा है. उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पेयजल स्रोतों (इंडिया मार्का हैंडपंप) के पानी की जांच के बाद ये परिणाम सामने आए हैं. अयोध्या में निर्माणाधीन कांशीराम शहरी ग़रीब आवासीय योजना का इलाक़ा भी जल प्रदूषण की चपेट में है. निगम के अधिशासी अभियंता राम नयन के मुताबिक़, कई नलों की जल परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव निकलने के बाद अब यहां अंडर ग्राउंड वाटर सप्लाई का काम चल रहा है. अभी भी हज़ारों लोग इंडिया मार्का हैंडपंपों का दूषित जल पीने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अफ़सरों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है.

निगम की केमिस्ट बृजबाला के मुताबिक़, वर्ष 2009–10 के दौरान कुल 2804 जल नमूनों का परीक्षण उनकी लैब में किया गया, जो इंडिया मार्का हैंडपंपों के थे. इनमें से 106 नमूनों में घातक रसायन पाए गए. इसी तरह वर्ष 2010–11 में क़रीब ढाई हज़ार परीक्षणों में तीन दर्जन से अधिक नमूने दोषयुक्त निकले. ऐसे नमूनों की संख्या शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा रही. मुकेरी टोला, कंधारी बाज़ार, हैदरगंज, कजियाना, कांशीराम आवासीय योजना, जैसिंहपुर मंदिर एवं पठान टोलिया जैसी बस्तियों के पेयजल में नाइट्रेट, आयरन, कठोरता और खारापन की शिकायत पाई गई. कंधारी बाज़ार और जैसिंहपुर के पानी के नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा 70.8 प्रतिशत पाई गई. जबकि सामान्य स्थिति में यह मात्रा 45 प्रतिशत होती है. इसी तरह कजियाना के दो नमूनों में कठोरता सामान्य से अधिक मापी गई.

पानी में हानिकारक तत्वों की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है. शहर से सटे मसौधा ब्लॉक में भी पानी में नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि इंडिया मार्का हैंडपंपों की बोरिंग को और गहराई पर ले जाकर इन हानिकारक तत्वों से बचा जा सकता है, लेकिन यह ऐसा तरीक़ा है, जिसका इस्तेमाल नीतिगत निर्णय के बाद हो सकता है. अमूमन इंडिया मार्का हैंडपंपों की बोरिंग एक निश्चित गहराई तक की जाती है. इसे और गहराई तक ले जाने का निर्णय शासन स्तर पर ही संभव है. विगत कई वर्षों से शहरों में बढ़ती आबादी के दबाव और सीवेज के उचित निस्तारण के अभाव के चलते भूजल दूषित हो रहा है. फैक्ट्रियों से निकाली गंदगी, मलमूत्र और गंदे नालों से रिस–रिसकर नीचे जाते पानी ने भूजल को विषैला बनाने का काम किया है. अनियमित शहरी विकास ने अब धरती की कोख में भी अपनी पैठ बना ली है. कभी अमृत समान और जीवन का पर्याय रहा जल अब ख़तरा बनता जा रहा है. खेती के लिए इस्तेमाल हो रहे घातक रसायन भी जल को दूषित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं. ग़नीमत यह है कि अभी अयोध्या एवं फ़ैज़ाबाद ज़िले के भूजल में फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक तत्वों की मौजूदगी नहीं पाई गई है.

पेयजल शुद्धिकरण अभियान फ्लॉप

जल प्रदूषण को लेकर चिंताएं चारों तरफ़ हैं, लेकिन ईमानदारी से इस ओर कोई पहल होती नहीं दिख रही. यूनीसेफ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग एवं सर्व शिक्षा अभियान के भारी–भरकम बजट के सहारे स्कूलों के पेयजल को साफ़–सुथरा रखने की पहल हुई तो लेकिन सही ढंग से परवान नहीं चढ़ सकी. ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) द्वारा इस काम के लिए ज़िले भर की न्याय पंचायतों के प्रभारियों को प्रशिक्षित करके फील्ड किट दी गई और सिखाया गया कि किस तरह उन्हें इन किटों के सहारे पानी में मौजूद क्लोराइड, कठोरता, टर्बिडिटी (गंदलापन), अम्लीयता, आयरन, नाइट्रेट, फ्लोराइड एवं शेष बची क्लोरीन का परीक्षण करना है. लेकिन ट्रेनिंग के बाद आगे का कार्यक्रम थम गया. सैकड़ों जल परीक्षण फील्ड किटें डायट में पड़ी धूल खा रही हैं और अभियान टांय–टांय फिस्स हो गया. जल शोधन का दूसरा क़िस्सा इससे भी ज़्यादा निराशाजनक है. जल मणि योजना के तहत ज़िले के विभिन्न विद्यालयों में वाटर फ्यूरीफिकेशन सिस्टम लगना था. इसके लिए क़रीब सवा सौ किटें मंगवाई गईं. लगभग तीन दर्जन विद्यालयों में यह किट लगाई भी गई, लेकिन किट जहां–जहां लगी, वहां से कब उखड़ भी गई, यह न विद्यालयों को पता चला और न विभाग को. अब काग़ज़ी घोड़े दौड़ रहे हैं. रही परिणाम की बात, ऐसी हालत में उसे तो सिफ़र ही होना था.

feedback@chauthiduniya.com

पेयजल स्रोतों में रासायनिक अशुद्धियां स्वीकार्य मात्रा और स्वास्थ्य पर प्रभाव

अशुद्धि का विवरण	अधिकतम स्वीकार्य सीमा	वैकल्पिक स्रोत के अभाव में अनुमन्य सीमा	प्रभाव
गंदलापन अर्थात पारदर्शिता की माप (एनटीयू पैमाने पर)	5	10	पानी का घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाना.
पीएच	6.5–8.5	6.5–8.5	इससे अधिक होने पर पानी पाचन तंत्र, श्लेश्मिक झिल्ली और जलापूर्ति प्रणाली को प्रभावित करता है. पानी को कीटाणुरहित बनाने की क्लोरीन की क्षमता भी कम हो जाती है.
जल की कुल कठोरता सीएसीओ–3 के रूप में (मिलीग्राम/ली.)	300	600	जलापूर्ति प्रणाली में पपड़ी जम जाती है और घरेलू प्रयोग, खाना पकाने एवं कपड़े धोने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. साबुन का प्रयोग करने पर झाग नहीं बनता और जल का बॉयलिंग पॉइंट बढ़ जाता है.
आयरन एफई के रूप में (मिलीग्राम/ली.)	0.3	1.0	सीमा से अधिक होने पर रंग और स्वाद दोनों प्रभावित होते हैं. घरेलू प्रयोग (कपड़ों/ बर्तनों पर दाग़ लग जाते हैं) और जलापूर्ति प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.
क्लोराइड सीएल के रूप में (मिलीग्राम/ली.)	250	1000	सीमा से अधिक होने पर पानी का स्वाद अच्छा नहीं रह जाता.
अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन सीएल (मिलीग्राम/ली.)	0.2	.....	कीटाणुओं को प्रभावी रूप से नष्ट करने के लिए क्लोरीन की समुचित मात्रा ज़रूरी.
नाइट्रेट एनओ–3 के रूप में सीएल (मिलीग्राम/ली.)	45	45	नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा सामान्य तौर पर प्रदूषण की सूचक है. नाइट्रेट का स्तर अधिक होने पर बच्चों में मैथामेग्लोबीनिया या ब्लू बेबी बीमारी हो जाती है.
फ्लोराइड एफ के रूप में (मिलीग्राम/ली.)	1.0	1.5	क्लोराइड की उच्च सघनता से दांतों एवं हड्डियों को फ्लोरोसिस हो जाती है. 0.6 मिलीग्राम/लीटर से कम सघनता से दांत झरने की बीमारी हो जाती है.

घर बैठे मशरूम की खेती

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत काम करने वाले भारतीय बाग़वानी अनुसंधान संस्थान बंगलुरू ने घरेलू स्तर पर मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित करने का एक कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके तहत महिलाओं को घर बैठे उपभोग के लिए मशरूम मिलने के अलावा आय अर्जित करने का भी मौक़ा मिलता है. संस्थान की मशरूम प्रयोगशाला ने घरेलू स्तर पर मशरूम पैदा करने की ऐसी तकनीक विकसित की है, जिससे एक वर्ग फुट क्षेत्र में 5.5 फुट की ऊंचाई तक 1.5 से 2 किलोग्राम तक मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है.

मशरूम प्रति इकाई क्षेत्र में अधिकतम प्रोटीन देता है. इसे घर के किसी भी नमी वाले कोने में उगाया जा सकता है. महिलाएं इसे किचन गार्डन गतिविधि के रूप में अपना सकती हैं. वैसे भी देश की 50 प्रतिशत महिला आबादी कृषि से जुड़ी गतिविधियों में 90 प्रतिशत का योगदान करती है. घर में ही मशरूम की खेती करना महिलाओं की कार्यशैली और प्रबंध कौशल के सर्वथा अनुकूल है. शाकाहारी परिवारों की प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रोटीन से भरपूर मशरूम की खेती घर में बहुत आसानी के साथ की जा सकती है.

घर में मशरूम पैदा करना और परिवार के प्रत्येक सदस्य को 100 ग्राम मशरूम उपलब्ध कराने का मतलब है हृदय रोग के ख़तरे को कम करना, क्योंकि मशरूम में कोलेस्ट्रोल कम करने की क्षमता है. यह मधुमेह को नियंत्रित करता है और कैंसर रोगियों की कीमोथेरेपी के बाद होने वाले साइड इफेक्ट को भी कम करता है. यही नहीं, यह केलेट्रा लेने वाले एड्स रोगियों के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे एंटी हाइपरलिपिडेमिक प्रभाव कम होता है. घरेलू स्तर पर मशरूम की खेती के अलावा संस्थान द्वारा तैयार की गई व्यवसायिक मशरूम उत्पादन तकनीक के ज़रिए ओएस्टर, बटन, मिल्की, पैडी स्ट्रा, शिटेक और रेशी आदि किस्मों के मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है. दैनिक उपभोग के लिए पैदा की जाने वाली इन क़िस्मों के अलावा महिलाओं के सामने मशरूम का बीज तैयार करने का वैकल्पिक व्यवसाय भी है, क्योंकि बीज की कमी के कारण मशरूम का उत्पादन नहीं बढ़ पाता है और इसकी क़ीमत भी अधिक रहती है. मशरूम का बीज तैयार करने की तकनीक आसान है. महिलाओं को इसके लिए बहुत अधिक निवेश भी करने की जरूरत नहीं होती. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के अच्छे अवसर हैं, क्योंकि वहां मशरूम के बीजों की कमी रहती है.

भारतीय बाग़वानी अनुसंधान संस्थान बंगलुरु उत्पादकों के लिए नियमित रूप से मशरूम की खेती और इसके बीज तैयार करने के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है. मशरूम से बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करना भी महिलाओं के लिए एक अनुकूल व्यवसाय है. आज के समय में जबकि कामकाजी महिलाओं के लिए घर में तरह–तरह के व्यंजन तैयार करना संभव नहीं है, पोषक तत्वों से भरपूर मशरूम के व्यंजन बनाकर उनकी आपूर्ति करना एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है. मशरूम पाउडर, मशरूम पापड़ और मशरूम का अचार तैयार करने का काम कुटीर उद्योग स्तर पर किया जा सकता है. मशरूम सैंडविच, मशरूम चावल, मशरूम सूप और मशरूम करी आदि व्यंजन पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय हैं. संस्थान ने नारंगी रंग का ख़ूबसूरत मशरूम पैदा करने की तकनीक विकसित की है, जो गमले रखने वालों और पुष्प प्रेमियों के लिए एक आकर्षण है. मशरूम को प्रोत्साहित करने का एक लाभ यह भी है कि पैदावार के बाद इसकी बची–खुची सामग्री जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और जैविक खाद तैयार करने में सहायक सिद्ध होती है.

रीतेश सिंह
feedback@chauthiduniya.com

भारतीय रहस्यवाद के माध्यम से विश्व को एशिया का संदेश देकर उन्होंने भी अंग्रेजी समाज पर चोट की, लेकिन उनका धर्म वैश्विक था.

सरकार के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी समुदाय को सामाजिक अन्याय या असमानता का सामना न करना पड़े और सभी लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हों.

वर्ग तंत्र और यथास्थितिवाद

महावीर प्रसाद आर मोरारका

पांचवीं योजना वर्ग विभाजन की है. राष्ट्र को या समाज को कई वर्गों में विभक्त मान लिया जाता है और प्राय: हर एक वर्ग की अलग–अलग आय निर्धारित होती है. मान लीजिए, एक वर्ग निम्न कोटि के काम करने वाले मज़दूरों, कुलियों, भारवाहकों का है, उन्हें औसतन 70 रुपये माहवार मिलता है. दूसरा वर्ग प्रोफेसर, डॉक्टर इत्यादि लोगों का है, जिन्हें क़रीब 1000 रुपये माहवार मिलता है. आप कहेंगे कि भाई, यह प्रथा तो समाज में प्रचलित है. शायद आप ठीक कहते हैं. पर ऐसा है नहीं. कोई नियम या क़ानून नहीं बंधा हुआ है कि डॉक्टर को कुली से ज़्यादा वेतन मिले. पर फिर भी चूंकि डॉक्टर कम हैं, कुली ज़्यादा हैं, इस तरह से ऐसी स्थिति बन जाती है.

यह भी आवश्यक नहीं है कि श्रमजीवी व्यक्ति बुद्धिजीवी आदमी से कम का अधिकारी है. बहुधा देखने में आता है कि बुद्धिजीवियों में कुछ अत्यंत प्रतिभा संपन्न होते हैं, वे भी दरिद्रता में जकड़े रहते हैं, भूखों मरते हैं. जनता को उनकी महानता का ज्ञान उनके जीवनकाल में नहीं होता. पर श्रमजीवी ऐसे भी देखे जाते हैं, जो जीवन का सब पारिवारिक ख़र्च चलाकर काफ़ी बचा लेते हैं. मासिक आय के अनुपात से ही हिसाब नहीं लगेगा. सामाजिक परिस्थितियों की वजह से सभ्यता के तक़ाज़े के अनुसार उन उच्च श्रेणी वाले व्यक्तियों पर ख़र्च लदे हुए हैं. इसीलिए उन श्रमजीवियों के मुक़ाबले, जिनको ये व्यथाएं नहीं हैं, वे बुद्धिजीवी सर्वथा दरिद्र ही कहे जाएंगे. 1000 रुपये मासिक वेतन पाने वाला प्रोफेसर अपने परिवार और समाज के उत्तरदायित्व निभाने में 1050 रुपये मासिक ख़र्च करता है, लेकिन 70 रुपये कमाने वाला श्रमजीवी 50 रुपये मासिक ही ख़र्च करता है, क्योंकि उसके उत्तरदायित्व सीमित हैं और उसके परिवार के अन्य व्यक्ति भी कमाते हैं. ऐसी हालत में आप ग़रीब किसे कहेंगे? कल तक जो रियासतों के महाराजा थे, आज निश्चय ही वे अपने आपको ग़रीब महसूस करते हैं, क्योंकि अपने ख़र्चों को पूरा कर पाने में वे असमर्थता अनुभव करते हैं.

यह भी आवश्यक नहीं है कि जिस वर्ग के पास आय के सबसे ज़्यादा साधन हों या जो धनिक हों, वे शक्तिमान हों ही. माना कि रुपया बड़ी भारी ताक़त है, पर फिर भी एक करोड़पति सेठ को गांव के पुलिस कांस्टेबल से, जो कि साधारण श्रेणी का व्यक्ति है, डरना ही पड़ता है. जिन आदमियों को अधिकार है, वे धनिक हों, यह कोई आवश्यक नहीं है. मान–प्रतिष्ठा में भी धनिकों को अग्रगण्य माना ही जाए, यह ज़रूरी नहीं. आज के युग में एक साधारण सा प्राणी जिसके पास लोक–संग्रह है यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों का प्रिय है, वह ही प्रथम पूज्य है. भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इसलिए सर्वमान्य या प्रथम आराध्य नहीं हैं कि वह बड़े धनी हैं, पर वह इसलिए हैं कि उन्होंने जनता की सेवा करके उसका नया मार्गदर्शन कराया, उसका उत्थान किया है और कर रहे हैं. आज वह बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं. धनिकों की ताक़त के बारे में जब भी आप बात करते हैं तो यह सत्य है कि उनकी ताक़त सही अर्थ में ताक़त है. वे चाहे जिसको अपनी नौकरी से अलग कर सकते हैं, कोई दुकानदार या व्यापारी उन्हें पसंद न हो तो उसका व्यापार बंद करा सकते हैं. राजमार्ग पर एक डाकू बंदूक़ दिखाकर आपको सर्वस्व समर्पण करने पर बाध्य कर दें. पर यह सब असल अर्थ में ताक़त नहीं है, यह तो बल की धमकी है. असल अधिकार का रुपयों या धन से कोई सरोकार नहीं है. प्रधानमंत्री से लकर साधारण पुलिस कर्मचारी तक उन धनिकों से बड़े हैं, जिनको उनके हुक्म मानने ही पड़ते हैं. हां, तो इस श्रेणी विभाजन का वित्त–पोषण भी संतोषप्रद तो नहीं है.

छठी योजना है यथास्थितिवाद यानी जैसा है वैसे ही चलने दो. यह अभिप्राय रखने वाले व्यक्ति भी बहुत हैं. वे परिवर्तन से डरते हैं. जिस तरह से चल रहा है, उससे वे संतुष्ट तो कदापि नहीं हैं, पर उनको भय है कि परिवर्तन से हालत कहीं और भी न बिगड़ जाए. इसलिए वे कहते हैं, जैसे चलता है वैसे चलने दो. यह विशुद्ध पलायनवाद है. वे जानते हैं कि चलता है, वैसे चल नहीं सकता. सृष्टि का क्रम परिवर्तनशील है. परिवर्तन होगा ही. आप किसी चीज़ को वैसे का वैसे नहीं रख सकते. एक कमरा बंद कर दीजिए, झाड़ू बुहारी साफ़–सफ़ाई कुछ भी मत कीजिए, सार–संभाल रखने से, उपयोग में लाते रहने से जितना ह्रास होगा, उससे कहीं ज़्यादा वैसे का वैसा पड़ा रहने देने से होगा. तात्पर्य यह हुआ कि संसार की हर वस्तु क्रियाशील है, गतिशील है. उनकी क्रिया या गति का अवरोध किया नहीं जा सकता.

यथास्थितिवाद के हिमायती रूढ़िवादी धीरे–धीरे अकर्मण्य बन जाते हैं. अगर मानव कुछ क्रियाशील न रहे या कम क्रियाशील रहे तो नियम है कि उसके हिस्से की क्रिया किसी दूसरे को करनी पड़ेगी. परिणाम यही होता है कि कुछ आलसी धनिक धीरे–धीरे ज़्यादा धनी होते जाते हैं और बहुसंख्यक निर्धन धीरे–धीरे ज़्यादा निर्धन होते जाते हैं. वही ख़तरनाक परिस्थिति पैदा हो जाती है. 11वीं शताब्दी में सौराष्ट्र में सोमनाथ के मंदिर में लाखों की संख्या में रक्षक होते हुए भी कुल 25 हज़ार अश्वारोहियों को लेकर आए ग़ज़नी के सुल्तान ने मंदिर को ध्वंस कर दिया और करोड़ों की संपत्ति लूटकर ले गया. यह भारत में व्याप्त उस समय की अकर्मण्यता का ही दोष था. यह ऐसी मनोवृत्ति का ही परिणाम था कि भारत 200 वर्षों से अधिक विदेशियों की गुलामी या दासता में बंधा रहा. यदि राष्ट्र के क्रियाशील नेताओं ने और उनसे पहले सन् 1857 में बहादुर सैनिकों ने अकर्मण्यता को दूर फेंककर परिवर्तन करना होगा, का नारा न लगाया होता तो शायद कई शताब्दियों तक और आगे भारत गुलामी में ही जकड़ा रहता. यथास्थितिवाद निश्चय ही भयानक मनोवृत्ति है. यह प्रकृति के नियम के विपरीत है. चलता है वैसे ही चल नहीं सकता. परिवर्तन तो अवश्यंभावी है.

अब परिवर्तन कैसा हो, यही आपको–हमको सोचना, करना है. मान लो, एक घोड़ागाड़ी आप चला रहे हैं, घोड़ा बिदक गया, घबड़ाया हुआ ज़ोर से दौड़ने लगा. आगे बड़ा गड्ढा है. निश्चय ही वह उसमें गिर पड़ेगा और आपको जीवन के लाले पड़ जाएंगे. आप कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, जो लिखा होगा सो होगा. ऐसी परिस्थिति में हम कर ही क्या सकते हैं? बड़ी भूल की बात है, यह निष्क्रियता की मनोवृत्ति निश्चय ही गड्ढे में गिराकर प्राणांत कर देगी. आपको प्रयत्न करके घोड़े को शांत करना होगा या जब तक शांत नहीं होता, गाड़ी को उस गड्ढे के किनारे–किनारे चलाकर दुर्घटना बचानी होगी. व्यापार में भी यही परिस्थिति है. राष्ट्र को गड्ढे में पड़ने से बचाने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र का व्यापार जनहित की दृष्टि से चले. सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए, ऐसा अभिप्राय उन्हीं रूढ़िवादी लोगों का है. व्यापार में अगर सरकार हस्तक्षेप करने लगी है, तो व्यापार कैसे चले? इत्यादि, उन लोगों की शिकायतें हैं. दूसरे शब्दों में वे चाहते हैं कि हम किसी भी तरकीब से, उचित–अनुचित, वाजिब–ग़ैरवाजिब तरीक़े से धनोपार्जन करते रहें. बाक़ी प्रजा को चाहे पेट भर खाने को भी न मिले, पर सरकार हमें किसी प्रकार की बाधा न दे. यही तो है यथास्थितिवाद. क्या आप समझते हैं कि यह प्रणाली ठीक है? कदापि नहीं.

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

स्वामी विवेकानंद का संदेश किसे याद है

मेघनाद देसाई

रवींद्र नाथ टैगोर का 150वां जन्मदिन मनाने के बाद अब बारी है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाने की. दोनों बंगाल के थे, लेकिन भारत के संदर्भ में दोनों का विजन काफ़ी अलग था. शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद विवेकानंद काफ़ी प्रसिद्ध हो गए. कदाचित वह आधुनिक भारत के पहले व्यक्ति थे, जिन्हें वैश्विक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी. वह न केवल अच्छे वक्ता थे, बल्कि अच्छे रूप–रंग, अच्छी आवाज़ और गेरुआ वस्त्र के कारण पवित्र इंसान भी दिखते थे. अब यही गेरुआ वस्त्र स्वामियों की पोशाक बन गया है. दूसरी ओर टैगोर ब्रह्म समाज की परंपरा में पले थे. भारतीय रहस्यवाद के माध्यम से विश्व को एशिया का संदेश देकर उन्होंने भी अंग्रेजी समाज पर चोट की, लेकिन उनका धर्म वैश्विक था. सबसे बड़ी बात है कि वह संत नहीं थे, लेकिन टैगोर एक महान उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार, चित्रकार एवं संगीतकार थे.

उनकी अधिकांश कृतियां अब भुला दी गई हैं. टैगोर को अब पश्चिमी देशों में नहीं पढ़ा जाता है. यही नहीं, इस महान साहित्यकार की कृतियों को भारत के लोग भी नहीं पढ़ते हैं. यदि किसी भारतीय से टैगोर के बारे में पूछें तो वह केवल भुनभुनाएगा, जवाब कुछ नहीं देगा. साथ ही उसे यह अफ़सोस भी नहीं होगा कि वह इस महान व्यक्ति के बारे में नहीं जानता है. विवेकानंद को भी कोई ज़्यादा नहीं पढ़ता है. विवेकानंद की संपूर्ण कृतियों का जो संकलन है, न तो उसकी छपाई अच्छी है और न उसे बेहतर ढंग से संपादित किया गया है. उनके अनुयायी उनकी पूजा तो करते हैं, परंतु उनके मूल्यों को नहीं समझते. वे सामान्यत: विवेकानंद को नहीं पढ़ते हैं. विवेकानंद आधुनिक भारत के उन लोगों में से हैं, जिन्हें हिंदूवादी भी उतना ही स्वीकार करते हैं, जितना धर्मनिरपेक्ष लोग. दोनों संभवत: इसलिए ऐसा करते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी उन्हें नहीं पढ़ा है. विवेकानंद आधुनिक भारतीय इतिहास के केंद्र में रहे हैं. विवेकानंद गीता की व्याख्या की वजह से नहीं, बल्कि आधुनिक भारतीय समाज का परीक्षण करने की वजह से आकर्षण के केंद्र में रहे हैं. उन्होंने 1894 में अपने एक भारतीय मित्र को लिखा कि धर्म का काम सामाजिक नियम बनाना नहीं है और न लोगों के बीच विभेद करना, लेकिन फिर भी धर्म की अनुमति से आर्थिक स्थितियों ने ही सामाजिक नियम बनाए हैं और सामाजिक मामलों में धर्म ने जो हस्तक्षेप किया, वह इसकी एक भयानक भूल थी.

वह मिशन ऑफ वेदांता में लिखते हैं कि उन्हें अपने भारतीय अनुयायियों से कठोर सत्य कहना है. वह कहते हैं कि अगर कोई अंग्रेज किसी भारतीय की हत्या कर देता है या उसके साथ ग़लत व्यवहार करता है तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है. उसके लिए ज़िम्मेदार अंग्रेज नहीं, बल्कि भारतीय हैं. हम भारतीय ही अपने राष्ट्र और ख़ुद की दुर्दशा के लिए ज़िम्मेदार हैं. हमारे तानाशाह पूर्वजों ने आम जन को तब तक पददलित किया, जब तक कि वे असहाय नहीं हो गए, जब तक कि ग़रीब लोग इस बात को भूले नहीं कि वे भी इंसान हैं.

जब विवेकानंद को ध्यान से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके धर्म संबंधी विचार थोड़े जटिल हैं. यह भारतीय जीवन का केंद्रीय तत्व है. भारत की राष्ट्र रूपी इमारत की बुनियाद स्वामी विवेकानंद के इन्हीं विचारों ने रखी है, लेकिन वह यह भी कहते हैं कि धर्म सामाजिक सुधार का शत्रु है. भारत जातीयता का दंश झेल रहा है, पर इसे स्वीकार नहीं करता है. स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर ब्राह्मणों के पास आनुवांशिक आधार पर ही सीखने की योग्यता अछूतों से अधिक है तो फिर ब्राह्मणों की शिक्षा पर धन मत ख़र्च करो, सारा धन अछूतों की शिक्षा पर ख़र्च करो, उन्हीं को इसकी ज़रूरत है. विवेकानंद का ब्राह्मण विरोधी विचार काफ़ी मज़बूत है. जैसा कि वह भारत में मुसलमानों के आगमन के बारे में लिखते हैं कि भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण इस कारण संभव हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों ने भारतीयों को सांस्कृतिक एकता प्रदान नहीं की. हज़ारों वर्षों तक इन्होंने लोगों के लिए ख़ज़ाना नहीं खोला और सभी आक्रमणकारी भारत को अपने पैरों तले रौंदते रहे. 20वीं सदी के मध्य में राजनीतिक हिंदूवाद रूढ़िवादी हो गया और जातिवाद की समाप्ति, जिसे सुधार का मुख्य आधार होना चाहिए था, को ऐसे ही छोड़ दिया गया. हम लोग अभी तक इसकी क़ीमत चुका रहे हैं. हर दिन दलित महिलाओं और पुरुषों के ऊपर हो रहे अत्याचार की ख़बर आती है. स्वामी लोग अब इस देश में सिर्फ़ पूजे जाते हैं. न तो उन्हें पढ़ा जाता है और न गंभीरता से लिया जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

लोकतंत्र के नाज़ी पहरुए

फारबिसगंज गोलीकांड की घटना से पता चलता है कि बिहार में सुशासन की आड़ में किस तरह का खेल चल रहा है. एक तरफ़ तो नीतीश कुमार राज्य के विकास की बात करते नहीं अघा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ़ फारबिसगंज जैसी घटनाएं बताती हैं कि उनके दावे कितने खोखले हैं. बिहार की पुलिस आज भी औपनिवेशिक मानसिकता वाली है. ऐसे दर्जनों मामले मिल जाएंगे, जिनसे पुलिस की छवि ख़राब हुई. पुलिस का यह बर्ताव चिंता का विषय है. जनता ने 15 साल लालू प्रसाद यादव पर भरोसा किया, लेकिन जब ठान लिया तो उन्हें भी सत्ता से बेदख़ल कर दिया. अब यही हाल नीतीश का न हो.

–हर्षवर्द्धन कुमार, *पटना, बिहार.*

जल संचयन ज़रूरी

क़रीब डेढ़ अरब की आबादी वाले इस देश में लगभग 20 करोड़ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता, जबकि 80 करोड़ लोग प्रदूषित जल पीने को मजबूर हैं. यह स्थिति बेहद गंभीर है. देश के साढ़े छह लाख गांवों में कहने के लिए 50 लाख से अधिक तालाब हैं, लेकिन उनकी हालत बेहद जर्जर है. हालांकि सरकार उनके संरक्षण पर लाखों रुपये ख़र्च कर रही है. शहरीकरण ने तालाबों को लील लिया है. कई राज्यों में उनका अस्तित्व लगभग ख़त्म हो गया है. तालाब होने से वर्षा जल का संचयन होता है और फिर यह पानी पीने और अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ ही यह भूजल स्तर को भी बरक़रार रखता है. देश के अनेक राज्यों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिससे जलसंकट पैदा हो गया है. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 120 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन कई जगह लोगों को पानी की यह मात्रा नहीं मिल पा रही है. इसलिए ज़रूरी है कि जल संचयन को एक मिशन के रूप में लेना चाहिए.

–**रामेंद्र सिंह चौहान,** *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

अल्प धनराशि

बिहार सरकार ने महादलितों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भूमि ख़रीद हेतु 20 हज़ार रुपये प्रति परिवार देने का निर्णय किया है. यह एक सराहनीय क़दम है, लेकिन 20 हज़ार रुपये में मौजूदा समय में ज़मीन नहीं मिल सकती. सरकार यह जानती है कि पिछले एक दशक में ज़मीन की क़ीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है. एक दशक पूर्व इंदिरा आवास के लिए 20 हज़ार रुपये आवंटित होते थे. उस दौर में हज़ारों इंदिरा आवास अर्द्धनिर्मित रह गए थे. इस योजना की भी यही हालत होगी.

–**प्रताप नारायण सिंह,** *बेगूसराय, बिहार.*

तर्कसंगत लेख

आलेख–अन्ना को अन्ना ही रहने दो में लेखक ने बड़ा सटीक विश्लेषण किया है. लेखक ने अन्ना को जयप्रकाश नारायण और गांधी क्यों न बनाया जाए, पर तर्कसंगत कारण दिए हैं. गांधी और जय प्रकाश के कार्यों का समय, उद्देश्य एवं तरीक़ा अन्ना से अलग था. हज़ारे सोशल एक्टिविस्ट न होकर मुख्य रूप से समाज सुधारक हैं और उनके गांव रालेगण में किए गए कार्यों से पता चलता है कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र में हुए उनके आंदोलनों की वजह से सरकार ने कई बार मंत्रियों को उनके पदों से हटाया है.

–**डॉ. विजय उपाध्याय,** *खामला, महाराष्ट्र.*

मुसलमानों की उपेक्षा

सामाजिक सरोकार और राजनीतिक विचारधारा को पोषित करने में चौथी दुनिया ने अपना अलग मुक़ाम हासिल कर लिया. आलेख–मुस्लिम समाज का दर्द के माध्यम से आपने इस समाज की घोर उपेक्षा के प्रति जो चिंता व्यक्त की, वह वाजिब है.

–**अंजु अग्निहोत्री,** *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

चवन्नी चली गई

एक चवन्नी चली नहीं और एक चवन्नी चली गई
इंद्रप्रस्थ की शान कभी थी, न जाने कौन गली गई
न काले पर हाथ डाल पाए, न उजलों को हथकड़ी पड़ी
सधी नहीं बात अनशन से, बेचारी जनता छली गई
हमीं तो सीना सिपर हुए थे दिलाने आज़ादी इस वतन को
हमारी ही छातियों पे देखो कि मूंग अब तक दली गई
स्वास्थ्य, रक्षा कि अर्थ अपना, हर इक में ख़ामी भरी हुई
चरित्र ही को ग्रहण लगा है, यह कैसी कालिख मली गई
बना न राशनकार्ड अपना, न पाया प्रमाण जन्म का,
शिकारियों के जो मुंह तलक गर न मांस, हड्डी, नली गई
जो गाड़ी पटरी पे लाना है तो नियम बने सख्त, यह ज़रूरी
इक इंक़लाब और लाना होगा जो बात अब भी टली गई.

–**मंसूर अली हाशमी,** *रतलाम, मध्य प्रदेश.*

राजनेताओं की अगंभीरता

एक बार फिर मुंबई सीरियल बम धमाकों से दहल गई. कई लोग मारे गए और कितने ही जख्मी हो गए. सबसे दु:खद बात यह रही कि हमारे राजनेता ऐसे नाज़ुक वक़्त में भी सिर्फ़ अपनी सियासत चमकाने में लगे रहे. वे आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होने के बजाय सियासी रोटियां सेंकने में किसी से पीछे नहीं रहना चाहते. यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां के सियासी दल कोई हल तलाशने के बजाय समस्याओं को और ज़्यादा उलझाने में यक़ीन रखते हैं.

–**असलम ख़ान,** *दिल्ली.*

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में है

संतोष भारतीय

मंत्रिमंडल में हुए व्यापक फेरबदल से जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ. उल्टा यह संदेश गया है कि सरकार या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में है. उसके सामने कोई रोडमैप नहीं है. देश को चलाने के लिए किस तरह के लोग ज़रूरी हैं और पार्टी को चुनाव में जिताने के लिए किस तरह के लोग चाहिए, यह भी कांग्रेस के सामने कुछ साफ़ नहीं है. इस फेरबदल से यही संदेश गया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड लोगों की पार्टी है, वह कोई फ़ैसला नहीं कर सकती. कांग्रेस में जेनरेशन वार चल रही है कि नए लोग सत्ता संभालें और पुराने लोग सत्ता छोड़ें. पुराने लोगों ने सत्ता छोड़ने से इंकार कर दिया है. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 50 से 60 साल के ऊपर के लोग लगभग एक राय होकर एक तरह से काम कर रहे हैं. नीचे के लोगों के बीच कोई एक राय नहीं है. वे सब राहुल गांधी या सोनिया गांधी के ऊपर निर्भर हैं. सोनिया गांधी अपने पुत्र को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं. यह उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन जब नौजवानों की बात होती है तो जिस तरह देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति है, उसी तरह कांग्रेस का पहला नौजवान राहुल गांधी है. जब नौजवानों को सत्ता देने की बात होती है तो इसका मतलब सीधा–सीधा यही निकलता है कि पार्टी का पहला नौजवान प्रधानमंत्री बने.

प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की सर्वशक्तिमान नेता हैं. अफ़सोस इस बात का है कि देश की बुनियादी समस्याओं या बुनियादी सवालों को लेकर इनके बीच गंभीरता से कोई बात शायद नहीं हुई. अगर हुई होती तो समस्या यहां तक नहीं पहुंचती. या तो सोनिया गांधी समस्याओं को समझती नहीं हैं, समझती हैं तो मनमोहन सिंह से बात नहीं करती हैं और अगर वह बात करती हैं तो मनमोहन सिंह उनकी बात मानते नहीं हैं. ये तीन स्थितियां हैं. तीनों स्थितियों का अगर आप विश्लेषण करें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि इस देश का दर्द, इस देश की तक़लीफ लगातार बढ़ रही है और उस तक़लीफ को दूर करने का कोई नक्शा, न तो देश के प्रधानमंत्री के पास है और न कांग्रेस या सोनिया गांधी के पास.

इस फेरबदल में जयराम रमेश को पर्यावरण मंत्रालय से निकालने के पीछे प्रधानमंत्री का हाथ रहा. प्रधानमंत्री उन सारे लोगों को निकालना चाहते थे, जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के क़रीबी हैं, लेकिन सोनिया गांधी इसे नहीं मान रही थीं. जयराम रमेश कुछ बयान सही देते थे और कई अति उत्साह में दे देते थे. वह सिर्फ़ बयान देते थे, पर एक्शन कुछ नहीं होता था. जयराम रमेश सोनिया गांधी के सलाहकार थे. वह सोनिया गांधी से भी ज़्यादा राहुल गांधी के सलाहकार हो गए थे. यह मनमोहन सिंह के लिए तक़लीफदेह था कि एक व्यक्ति बयान देकर मुश्किलें तो बढ़ा रहा है, पर हल नहीं निकाल रहा है. अगर कहें तो श्री जयराम रमेश भी एक सुपर कंफ्यूज्ड व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी वाहवाही के लिए टेलीविजन चैनलों के साथ डील की, उन्हें पैसे दिलवाए और उनके रिपोर्टरों को साथ लेकर समुद्र की सैर कराई. इस सारी यात्रा का नतीजा क्या निकला? अगर उस तरीक़े से, जैसे अमिताभ बच्चन गुजरात के ब्रांड अंबेसडर बनकर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तब तो सही है. लेकिन एक मंत्री मॉडल बनकर जागरूकता अभियान में शामिल हो जाए, एक टेलीविजन चैनल के कैमरे को 24 घंटे साथ लेकर चले, तो यह बहुत ग़लत है और सरकार के मंत्री को यह सब शोभा नहीं देता.

अगर उनको यह काम करना भी था तो सारे टीवी चैनलों को बुलाते और कहते कि मैं यह करने जा रहा हूं, आप सब लोग आएं. देश के करोड़ों लोग टीवी देखते हैं, लेकिन उन्होंने एक चैनल को प्राथमिकता दी. ज़ाहिर है, पैसा भी दिया होगा या कहीं से पैसे कमाने का रास्ता खोल दिया होगा. अब जयराम रमेश ज़िंदगी में कभी गांव नहीं गए. जयराम रमेश का गांव से कोई रिश्ता नहीं है. जयराम रमेश ग्रामीण विकास मंत्री बना दिए गए. अब जब उन्होंने कोई नतीजा पर्यावरण मंत्री रहते हुए नहीं दिखाया तो ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए वह क्या रास्ता दिखाएंगे या गांव का क्या विकास करेंगे? सिवाय इसके कि वह यह बयान दें कि हम जो पैसा देते हैं, राज्य सरकारें उन पैसों का ग़लत इस्तेमाल करती हैं. हम मनरेगा जैसी योजनाएं चलाते हैं, राज्य सरकारें यह करती हैं. कुल मिलाकार वह शायद यहां भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरह उन राज्य सरकारों, जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी करेंगे. दु:ख की बात है कि न सिर्फ़ ग्रामीण विकास मंत्रालय, जहां दो सालों में दो मंत्रियों को बदला गया, अब जयराम तीसरे मंत्री हैं. सरकार इस देश के साथ बेवकूफ़ी भरे प्रयोग कर रही है. आप उस शख़्स से गणेश की मूर्ति बनाने के लिए कह रहे हैं, जिसे मूर्ति बनाना नहीं आता, वह उसे गणेश बनाते–बनाते बंदर बनाए दे रहा है. यह इस सरकार की हालत है.

अब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को ही देखें. सलमान ख़ुर्शीद को क़ानून मंत्री बनाकर अल्पसंख्यक मंत्रालय की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी दे दी गई. इसके क्या मायने हैं? सवाल यहां सिर्फ़ मुसलमानों का या उनकी भलाई का नहीं है, सवाल काम करने के तरीक़े का है. देश में एक सिस्टम है. एक प्रधानमंत्री होता है, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है और फिर एक राज्य मंत्री होता है. लेकिन क्या सरकार के पास इतने लोग नहीं हैं कि वह इस देश के एक अरब लोगों की भलाई के लिए कम से कम एक विभाग में एक मंत्री दे सके. क्या पार्लियामेंट में ऐसे लोग नहीं हैं? होना तो यह चाहिए था कि काम का विभाजन कर लोगों को ज़्यादा ज़िम्मेदारी दी जाए और उनके बीच सामंजस्य स्थापित हो.

देश को बनाने का नज़रिया मनरेगा के रूप में सामने आया कि हम ग्रामीण लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन इसके साथ ही पूरी की पूरी पंचायत तक आपने भ्रष्टाचार पहुंचा दिया. आपके पास कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है कि पंचायत में होने वाला भ्रष्टाचार, जो मनरेगा के तहत हो रहा है, को आप रोक सकें. क्योंकि आप सोचते हैं कि जब आप यहां एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ का घपला कर रहे हैं तो इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है कि वहां कोई एक लाख का घपला कर रहा है. पर भ्रष्टाचार की कड़ी जुड़ जाती है. अफ़सोस की बात है कि जो होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा. होना यह चाहिए था कि आप लघु या कुटीर उद्योगों में काम आने वाली वस्तुओं, ऐसी क़रीब नौ सौ के आसपास वस्तुएं हैं, जिनमें सुई, धागा, साबुन, जूता और बटन आदि हैं, उन पर सरकार बैन लगा दे कि ये चीजें सिर्फ़ स्मॉल स्केल सेक्टर में बनेंगी, इसमें वह बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों को न आने दे. बड़ी कंपनियां बनाएं, पर इंटरनेशनल मार्केट के लिए, देश के मार्केट के लिए नहीं. आप स्कूल–कॉलेज के साथ इस तरह की चीजें बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोलें. वहां से जो लड़के–लड़कियां निकलेंगे, वे बेरोज़गार नहीं होंगे. पर सरकार में जब कल्पनाशक्ति न हो, इच्छाशक्ति न हो और जब इस देश को पहले रूस और अब अमेरिका के हाथों गिरवी रखने की कसम खा रखी हो, तो फिर कोई क्या कर सकता है?

अब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को ही देखें. सलमान ख़ुर्शीद को क़ानून मंत्री बनाकर अल्पसंख्यक मंत्रालय की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी दे दी गई. इसके क्या मायने हैं? सवाल यहां सिर्फ़ मुसलमानों का या उनकी भलाई का नहीं है, सवाल काम करने के तरीक़े का है. देश में एक सिस्टम है. एक प्रधानमंत्री होता है, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है और फिर एक राज्य मंत्री होता है. लेकिन क्या सरकार के पास इतने लोग नहीं हैं कि वह इस देश के एक अरब लोगों की भलाई के लिए कम से कम एक विभाग में एक मंत्री दे सके. क्या पार्लियामेंट में ऐसे लोग नहीं हैं? होना तो यह चाहिए था कि काम का विभाजन कर लोगों को ज़्यादा ज़िम्मेदारी दी जाए और उनके बीच सामंजस्य स्थापित हो. कांग्रेस अल्पसंख्यकों में से किसी को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि कोई नेतृत्व खड़ा करना नहीं चाहता. कांग्रेस के पास कोई दलित नेता नहीं है, न कोई ऐसा मंत्री है. एक मुकुल वासनिक हैं, जो दलितों के लिए कम, समाज के लिए कम और धनवानों के लिए ज़्यादा काम करते हैं. इनके पास न कोई पिछड़ा है. वंचितों, दलितों, आर्थिक रूप से कमज़ोर, पिछड़ों को नेतृत्व देने की कोई योजना यूपीए के पास नहीं है. मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वह तो इससे भी घटिया टीम है. इस देश की जनता एक तरफ़ छूट गई है. उसके लिए सोचने वाले ख़त्म हो गए हैं या जो सोच सकते हैं, वे सामने नहीं आ पा रहे हैं या उन्हें मौक़ा नहीं मिल रहा है. आज भारत सरकार में जितने मंत्री हैं या जितने मंत्री अटल जी के समय में थे, उनके पास इस मुल्क को अच्छा बनाने का कोई सपना न तब था और न अब है. इनके सामने कोई नक्शा नहीं है, जिससे लोग निराशा से बचें, कोई सपना देखें और सोचें कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारी ज़िंदगी में ख़ुशहाली आएगी. न प्रधानमंत्री, न सोनिया गांधी, न उधर आडवाणी, न सुषमा स्वराज. ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन का वायरस सबके बीच फैल गया है, जो देश के बारे में नहीं, सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के मायने

सौमित्र मोहन

राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा शब्द है, जिसका इस्तेमाल आजकल आम तौर पर किया जाता है. प्राय: यह शत्रु देश के आक्रमण से सुरक्षा से संबंधित होता है अथवा उन हथियारबंद आतंकवादियों से सुरक्षा से, जो राष्ट्र के प्रभुत्व को चुनौती देते हैं या राष्ट्रीय एकता–अखंडता को नुक़सान पहुंचाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिप्राय केवल इसी से नहीं है, बल्कि इसे और अधिक वृहद अर्थों में समझने की आवश्यकता है. राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन तीन शब्दों से बना है. इस पर चर्चा करने से पूर्व इन तीनों शब्दों का अर्थ समझना अच्छा होगा. इसमें प्रथम शब्द है राष्ट्रीय, जिसका मतलब है जो राष्ट्र से संबंधित हो. भारत के संदर्भ में प्राय: इसे राष्ट्र–राज्य के बजाय राज्य–राष्ट्र कहा गया है. यह भारतीय समाज की अनेकता की ओर संकेत करता है और इस तथ्य की ओर भी संकेत करता है कि भारत के राज्य यूरोप के राज्यों की तरह के राष्ट्र नहीं रहे हैं, बल्कि उनसे भिन्न रहे हैं. बहु–सांस्कृतिक और बहु–राष्ट्र राज्य होने के बाद भी भारतीय समाज के कुछ हिस्से भारत राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं.

हिंदू सांस्कृतिक एकता का विचार जो भारतीय एकता को धर्म, संस्कृति एवं क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है, उस सूत्र को कमज़ोर करता है जो विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और नस्लों वाले भारत को एकता प्रदान करता है. यह विचारधारा समाज के एक बड़े भाग को राष्ट्रीय एकता से विमुख करती है. ब्रिटिश भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ, लेकिन यह सिद्धांत अंग्रेज सरकार की नीतियों का ही परिणाम था. विभिन्न संस्कृतियों और प्रजातियों के बीच विरोध और असंतोष होता है, लेकिन जब वे अपने को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती हैं और अलगाववादी आंदोलन चलाती हैं तो राष्ट्र की सुरक्षा ख़तरे में पड़ जाती है. इसे भी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन का हिस्सा मानना है. दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है सुरक्षा. सुरक्षा से अभिप्राय केवल सीमा की सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय एकता और स्वायत्तता की सुरक्षा से नहीं है. इसका अर्थ काफी व्यापक है. सुरक्षा का मतलब है राष्ट्रीय जीवन से संबंधित सभी प्रकार की सुरक्षा. राष्ट्र को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सभी प्रकार से सुरक्षित होना चाहिए.

तीसरा और अंतिम शब्द है प्रबंधन. कोई संगठन अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करता है. इसका संबंध उस संगठन के प्रशासन और परिचालन से होता है. संसाधनों के उपयोग की इस प्रक्रिया को ही प्रबंधन कहते हैं. अब अगर इन तीनों शब्दों को एक साथ रखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन का मतलब है राष्ट्रीय संसाधनों का समुचित उपयोग करके राष्ट्र को सभी संदर्भों में प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना. इस समय भारत एक साथ कई मोर्चों पर सुरक्षा संबंधी ख़तरों का सामना कर रहा है. इसे डर न केवल बाह्य शत्रुओं से है, बल्कि आंतरिक शत्रुओं से भी है. कश्मीर में छद्म युद्ध, सीमा पर आक्रमण यथा कारगिल युद्ध, आतंकवाद, परमाणु आक्रमण का ख़तरा, सीमा पार से आ रहे घुसपैठियों का दबाव, मादक पदार्थों की तस्करी, धार्मिक कट्टरपंथ, वैश्विक बाज़ार में आई अस्थिरता से उत्पन्न आर्थिक असुरक्षा, पर्यावरण संबंधी ख़तरा, मीडिया द्वारा किए जा रहे सांस्कृतिक आक्रमण आदि ऐसी समस्याएं हैं, जो भारत की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं.

ग़रीबी, कमज़ोर आर्थिक आधार, बेरोजगारी, संकुचित क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद और कमजोर संस्थागत संरचना आदि ने राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है. अगर हम वास्तविक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत बनाना चाहते हैं तो हमें इन समस्याओं के समाधान के लिए काम करना होगा, अन्यथा भारत की सुरक्षा ख़तरे में पड़ सकती है. बाह्य ख़तरों की तरफ़ ध्यान देने से पहले हमें देश की आंतरिक व्यवस्था सही करनी चाहिए. भारत सॉफ्ट स्टेट के रूप में जाना जाता है. गुन्नार मीर्डल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में भारत को सॉफ्ट स्टेट कहा था. सबसे पहले हमें इस छवि से बाहर आना है. यह नकारात्मक छवि इसलिए है, क्योंकि कई मोर्चों पर हमें सही नेतृत्व नहीं मिला और हम नाकामयाब रहे. इस कारण हमारी राजनीति और अर्थव्यवस्था पंगु हो गई. जर्जर विधायिका और अनिश्चय की स्थिति में रहने वाली कार्यपालिका यानी एक प्रकार से पूरी सरकार की अकर्मण्यता के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

सुरक्षा से अभिप्राय केवल सीमा की सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय एकता और स्वायत्तता की सुरक्षा से नहीं है. इसका अर्थ काफ़ी व्यापक है. सुरक्षा का मतलब है राष्ट्रीय जीवन से संबंधित सभी प्रकार की सुरक्षा. राष्ट्र को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सभी प्रकार से सुरक्षित होना चाहिए.

भारत के सामने सबसे पहला काम एक ऐसी प्रभावी संस्थागत संरचना का निर्माण करना है, जो राष्ट्रीय मामलों का सही प्रबंधन करे. ऐसी संस्थागत संरचना ही लंबे समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लाभप्रद होगी. ऐसा तर्क दिया जाता है कि ढांचागत संरचना और उत्तरदायी सरकार का इस्तेमाल तभी होगा, जब जागरूक, ज़िम्मेदार, चौकस और सहभागी नागरिक समाज हो. यदि इस तरह का नागरिक समाज है तो फिर मानव संसाधन में अधिकाधिक निवेश की आवश्यकता होती है. इसका मतलब है कि सभी लोगों को अच्छा भोजन मिले, अच्छे कपड़े उपलब्ध हों और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था हो. वरना भूखे और बेरोज़गार लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा बन जाएंगे. कौटिल्य ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया है. अत: भारत को अपने संसाधनों का लोगों के बीच सही वितरण करके और सभी नागरिकों की प्रतिष्ठा की रक्षा करके यह दिखाना है कि वह किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करता है.

यह सही है कि अलग–अलग समुदायों को प्राप्त प्रतिष्ठा में हो रहे पक्षपात के कारण भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. अत: सत्ता में बैठे लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी को समान रूप से न्याय मिले और विकास की दौड़ में कोई समुदाय इतना पिछड़ न जाए कि देश को चलाना मुश्किल हो जाए. प्रसिद्ध दार्शनिक राल्स ने जिसे वितरण न्याय कहा है, उसे लागू करने का प्रयास करना चाहिए. सरकार के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी समुदाय को सामाजिक अन्याय या असमानता का सामना न करना पड़े और सभी लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हों. अगर समाज में असमानता रही और सभी को न्याय नहीं मिला तो विद्रोह हो सकता है, जिसके कारण राष्ट्र खंडित हो सकता है, जैसा कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में हुआ. इसी संदर्भ में मैकियावेली का एक कथन है, सरकार को न केवल न्याय करना चाहिए, बल्कि उसे न्यायपूर्ण दिखना भी चाहिए. इसके साथ ही तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या पर क़ाबू पाने की भी आवश्यकता है, ताकि उपलब्ध संसाधनों के साथ सामंजस्य बैठाया जा सके. दोनों के बीच सामंजस्य का अभाव समाज में अस्थिरता और विद्रोह उत्पन्न करता है, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है. हमें अच्छी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, जिसका आधार सशक्त उद्योग और कृषि हो.

(लेखक आईएएस अधिकारी हैं. आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं और इनका सरकार के विचारों से कोई संबंध नहीं है)

feedback@chauthiduniya.com

एफसीसी प्रमुख चावोसकी का कहना था कि इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां किसी भी ऐसे ट्रैफिक को नहीं रोक सकतीं, जो क़ानूनन सही हो.

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

आपकी समस्याएं और सुझाव

आपके पत्र हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. इस अंक में हम उन पाठकों के पत्र शामिल कर रहे हैं, जिन्होंने बताया है कि आरटीआई के इस्तेमाल में उन्हें किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सूचना अधिकार क़ानून को लेकर उनके अनुभव क्या हैं. इसके अलावा इस अंक में मनरेगा योजना और जॉब कार्ड से संबंधित एक आवेदन भी प्रकाशित किया जा रहा है, ताकि आप इसका इस्तेमाल समाज के ग़रीब तबक़े के हित में करके भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारने की एक कोशिश कर सकें. आशा है, हमने इस अंक में जो सलाह/सुझाव दिए हैं, आप उनका इस्तेमाल करते हुए ज़ंग लगी सरकारी व्यवस्था को अपने सवालों से साफ़ करने की कोशिश करेंगे यानी आरटीआई आवेदन दाख़िल करके अपनी और आम आदमी की परेशानियों के बारे में ज़रूर सूचना मांगेंगे.

आपके पत्र

आरटीआई कार्यकर्ता बनना चाहता हूं

मैं सेवानिवृत्त अभियंता हूं और आरटीआई कार्यकर्ता बनना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए. इससे संबंधित जानकारी व पुस्तिका इत्यादि हो तो कृपया उपलब्ध कराएं. मैं इस क़ानून का इस्तेमाल करना चाहता हूं, सूचना सार्वजनिक करने की इच्छा रखता हूं.

–हरि नारायण दास, *हजारीबाग़, बिहार.*

यह ख़ुशी की बात है कि आप आरटीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं. आप इस क़ानून से संबंधित जानकारियां चौथी दुनिया के इस साप्ताहिक कॉलम से प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा आप चौथी दुनिया की वेबसाइट से भी आरटीआई के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं.

रेलवे अधिकारियों की सुस्ती

मैंने समस्तीपुर रेलवे की परिसंपत्तियों पर अवैध क़ब्ज़े के संबंध में समस्तीपुर मंडल से आरटीआई के तहत सवाल पूछे थे, लेकिन कोई भी सूचना नहीं मिली. मैंने इसके बारे में शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

–राजन कुमार पांडेय/अजय कुमार सिन्हा, *समस्तीपुर, बिहार.*

सूचना न मिलने की स्थिति में आपको इस क़ानून के तहत प्रथम अपील करनी चाहिए. अगर उससे भी बात न बने तो द्वितीय अपील करनी चाहिए.

जानकारी कैसे मांगें

विभिन्न विभागों से सूचना मांगने पर कई समस्याएं आती हैं. बेसिक शिक्षा विभाग, ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग से सूचना कैसे मांगी जाए, सूचना शुल्क कैसे और कितना जमा किया जाएं, इसके बारे में जानकारी दें.

–अब्दुल क़ादिर, *गोंडा, उत्तर प्रदेश*

चौथी दुनिया के इस नियमित कॉलम में हम आरटीआई से जुड़ी हर सूचना मसलन, सूचना शुल्क, शुल्क भुगतान के तरीके और आवेदन के प्रारूप आदि प्रकाशित कर चुके हैं और आगे भी प्रकाशित करते रहेंगे. जहां तक हेल्पलाइन नंबर की बात है तो स्थानीय कार्यालय से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं. विशेष और पूर्व में प्रकाशित जानकारी आप चौथी दुनिया की वेबसाइट www.chauthiduniya.com ***पर देख सकते हैं.***

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप
(मनरेगा एवं जॉब कार्ड)

दिनांक.....
सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
.....ब्लॉक के ग्राम.....के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:-

1. उपरोक्त गांव से एनआरईजीए (नरेगा) के तहत जॉब कार्ड बनाने के लिए अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? इसकी सूची निम्नलिखित विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं:-
क. आवेदक का नाम एवं पता.
ख. आवेदन संख्या.
ग. आवेदन की तारीख़.
घ. आवेदन पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण (जॉब कार्ड बना/जॉब कार्ड नहीं बना/विचाराधीन).
ड. यदि जॉब कार्ड नहीं बना तो उसका कारण बताएं.
च. यदि बना तो किस तारीख़ को?

2. जिन लोगों को जॉब कार्ड दिया गया है, उनमें से कितने लोगों ने काम के लिए आवेदन किया? उसकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं:
क. आवेदक का नाम एवं पता.
ख. आवेदन करने की तारीख़.
ग. दिए गए कार्य का नाम.
घ. कार्य दिए जाने की तारीख़.
ड. कार्य के लिए भुगतान की गई राशि एवं भुगतान की तारीख़
च. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां उनके भुगतान से संबंधित विवरण दर्ज हैं.
छ. यदि काम नहीं दिया गया है तो क्यों?
ज. क्या उन्हें बेरोज़गारी भत्ता दिया जा रहा है?

3. उपरोक्त गांव से एनआरईजीए के तहत रोज़गार के लिए आवेदन करने वाले जिन आवेदकों को बेरोज़गारी भत्ता दिया गया अथवा दिया जा रहा है, उनकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं:-
क. आवेदक का नाम एवं पता.
ख. आवेदन करने की तारीख़.
ग. बेरोज़गारी भत्ता दिए जाने की तारीख़.
ड. बतौर बेरोज़गारी भत्ता भुगतान की गई राशि और भुगतान की तारीख़.
च. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां उनके भुगतान से संबंधित विवरण दर्ज हैं.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....

ज़रा हट के

आप कंजूस तो नहीं हैं

यदि किसी लड़की या लड़के का नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है तो आप जान जाइए कि वह बहुत रहस्यमय है. ऐसे लोग अपनी चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखते हैं. ऐसे लोग बहुमुखी प्रतिभा के मालिक होते हैं. बहुत ज़्यादा बात करने वाले ये लोग आलोचना भी झेलते हैं. अपने प्यार के प्रति सचेत रहने वाले ये लोग कुछ शक्की मिज़ाज के भी होते हैं, इसके पीछे इनकी भावना सिर्फ़ इतनी होती है कि ये अपने प्रेम को किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन उनका यही तरीक़ा दूसरे लोगों के लिए सिरदर्द का कारण बन जाता है. सेक्स के प्रति ख़ासी दिलचस्पी होती है इनकी. ये क्रोधी स्वभाव के होते हैं. अपनी मेहनत के बल पर ये सब कुछ पा लेते हैं. ये सेल्फ मेड इंसान होते हैं. पैसा और रुतबा हासिल करने वाले ये लोग अपनी चीज़ आसानी से किसी को नहीं देते. ये कंजूस होते हैं, ये दिखावा भी काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें पार्टी-समारोह में जाना पसंद है. हालांकि ये दिल के ख़राब नहीं होते, लेकिन इनका तेज़ स्वभाव इन्हें ख़राब बना देता है. यह सब हम नहीं कह रहे, यह तो इनके नाम के प्रथम अक्षर का गणित कहता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यहां भेदभाव नहीं चलेगा

अमेरिका ने एक ऐसे कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार हो. इस संबंध में फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन (एफसीसी) के प्रमुख जुलिअस जेना चावोसकी ने कहा है कि एक स्वतंत्र और सबको सरल तरीक़े से उपलब्ध होने वाले इंटरनेट की ज़रूरत है. यह पहली बार है कि इस मुद्दे पर ख़ुद एफसीसी के प्रमुख ने अपना पक्ष रखा है. उन्होंने नेटवर्क की निष्पक्षता को लागू करने के लिए दो नए क़ानूनों की पेशकश की है. नए क़ानून लागू होने के बाद इंटरनेट कंपनियों को निष्पक्ष नेटवर्क के सिद्धांत के तहत काम करना होगा. एटलांटिक के दोनों तरफ़ के नेटवर्क इसी बात को लेकर बहस करते रहे हैं कि इंटरनेट की सुविधा दो तरह की होनी चाहिए. जो इसके लिए पैसे दे सकते हैं, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर, जो इसके लिए ख़र्च नहीं कर सकते.

दरअसल, कंपनियां वीडियो फाइलों के ट्रांसफ़र जैसी प्रक्रियाओं को रोकने का काम करती हैं, क्योंकि इससे उनके बैंडविथ पर असर पड़ता है, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगी. गूगल और यूट्यूब जैसी इंटरनेट कंपनियों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं, जो इससे ख़ुश नहीं होंगी. एफसीसी प्रमुख चावोसकी का कहना था कि इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां किसी भी ऐसे ट्रैफिक को नहीं रोक सकतीं, जो क़ानूनन सही हो. दूसरी बात यह कि उन्हें पारदर्शी होना होगा. चावोसकी का कहना था कि इस पूरी प्रक्रिया में एफसीसी को एक स्मार्ट पुलिस की भूमिका निभानी होगी. उन्होंने कहा कि यह सरकार द्वारा इंटरनेट के नियंत्रण का विषय नहीं है, बल्कि यह उस रास्ते के लिए उचित नियम बनाने की बात है, जिन्हें वे कंपनियां ख़ुद पर लागू करें, जो इंटरनेट के उपयोग का नियंत्रण करती हैं.

राशिफल

मेष — 21 मार्च से 20 अप्रैल

इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी मामलों को लेकर ख़र्चे बढ़ेंगे. नए स्थानों की यात्रा सफल रहेगी. परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए विशेष प्रयासों की ज़रूरत होगी. कोई अच्छी ख़बर सुनने को मिल सकती है. मेहनत से पीछे न हटें.

वृष — 21 अप्रैल से 20 मई

परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. नाक, कान और गले से संबंधित समस्याओं के प्रति सावधान रहें. यात्रा सामान्य रहेगी. दूसरों को कटु वचन मत बोलें, इससे आपसी संबंध बिगड़ सकते हैं.

मिथुन — 21 मई से 20 जून

सप्ताह के मध्य में आर्थिक स्थिति सुधरेगी. अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो कोई निराशा भी हाथ लग सकती है. परिवार से ख़ुशी और सहयोग की प्राप्ति होगी. वाहन सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना होने की आशंका है.

कर्क — 21 जून से 20 जुलाई

कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा. पेट संबंधी कोई बीमारी आपको तकलीफ़ दे सकती है. आय के नए स्रोत बनेंगे. यात्रा आपके तनाव को कम करेगी. ईश्वर के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास बनाए रखें, सफलता के रास्ते आसान होते जाएंगे. कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है.

सिंह — 21 जुलाई से 20 अगस्त

कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जिनसे आप बाहर आना चाहते हैं, मगर नहीं आ पा रहे हैं. इस सप्ताह आपकी यह समस्या हल हो जाएगी. परिवार का कोई सदस्य आपकी सहायता करेगा. कार्यक्षेत्र का माहौल पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा.

कन्या — 21 अगस्त से 20 सितंबर

अपने भीतर की आवाज़ सुनें, इससे आप अपना लक्ष्य जल्दी पूरा कर पाएंगे. यात्रा पर ख़र्च बढ़ेगा. छुट्टियां बिताना मज़ेदार साबित होगा. यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग बन रहे हैं.

तुला — 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. काफ़ी समय से लंबित पड़े हुए कार्य पूरे हो जाएंगे. सेहत के प्रति लापरवाह रवैया समस्याएं पैदा सकता है. आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा.

वृश्चिक — 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

नफ़ा-नुक़सान की परवाह किए बिना आप अपने काम पर यथोचित ध्यान देंगे. बच्चों एवं रिश्तेदारों पर ख़र्चे बढ़ेंगे. विश्वास ही आपके जीवन को बेहतर बना सकता है. पारिवारिक आयोजन आपको प्रसन्नता प्रदान करेंगे.

धनु — 21 नवंबर से 20 दिसंबर

आप प्रॉपर्टी ख़रीदने की योजना बना सकते हैं. जिनसे आप प्यार करते हैं, वे इस बात से बहुत ख़ुश होंगे. पार्टनरशिप और कम्युनिकेशन में आपकी क्षमता बढ़ेगी, व्यवसाय में भी अच्छा फ़ायदा होगा.

मकर — 21 दिसंबर से 20 जनवरी

आपका मन जिस बात के लिए तैयार नहीं है, उसे भूल जाना ही बेहतर होगा. किसी अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग मिलेगा, जो आपकी सफलता के लिए अनुकूल होगा. किसी महिला की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है.

कुंभ — 21 जनवरी से 20 फरवरी

आपको काफ़ी बुद्धिमानी से काम लेना होगा. आपके नए प्रोजेक्ट परिणाम देने में कुछ और समय लेंगे. यात्रा के दौरान कोई महिला चिंता का कारण बन सकती है. हो सके तो यात्रा को स्थगित कर दें, यही बेहतर होगा.

मीन — 21 फरवरी से 20 मार्च

वाणी पर नियंत्रण बनाएं रखें. व्यवसायिक मामलों में वास्तविकता को ध्यान में रखने की ज़रूरत है. इस सप्ताह आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ उतार-चढ़ाव महसूस करेंगे. किसी परिवारीजन का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है. ईश्वर पर भरोसा रखें.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

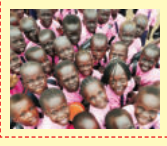

दक्षिण सूडान को स्वतंत्र किया जाए या नहीं, इसका फ़ैसला वहां की जनता को ही करना था, न कि शीर्ष पर बैठे राजनेताओं को.

दक्षिणी सूडान

एक नए देश का स्वागत कीजिए

अफ्रीका के नक्शे में कुछ परिवर्तन हुआ है. सूडान के विभाजन के साथ ही इस महादेश में स्वतंत्र देशों की संख्या 55 हो गई है. दक्षिणी सूडान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई है. इसके साथ ही 6 जनवरी, 2005 को हुए समग्र शांति समझौते के तहत चल रही वार्ताओं का दौर समाप्त हो गया और अंत हो गया वर्षों से चल रहे उस ख़ूनी संघर्ष का, जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. आंकड़े बताते हैं कि इस संघर्ष में तक़रीबन 25 लाख लोगों की जानें गईं और लगभग 50 लाख लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा, लेकिन इन तमाम लोगों की कुर्बानी आख़िरकार रंग लाई और 9 जुलाई, 2011 को दक्षिणी सूडान के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ. सल्वा कीर मयर्दित ने दक्षिणी सूडान के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. साथ ही रीक मछार को उप राष्ट्रपति बनाया गया. पूरा राष्ट्र ख़ुशी से झूम उठा, जब डॉ. जॉन गरांग मसोलियम में राष्ट्रपति सल्वा कीर ने दक्षिणी सूडान की स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा की. इस तरह दक्षिणी सूडान के रूप में दुनिया का 193वां देश अस्तित्व में आ गया. हालांकि दक्षिणी सूडान के लोगों के लिए तो यह ख़ुशी का क्षण है कि वे आज़ाद हो गए हैं, पर उत्तरी सूडान से संपदा का समझौता उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होगा. नया देश बनने के बाद फ़िलहाल दक्षिणी सूडान दुनिया के सबसे ग़रीब देशों में गिना जाएगा, लेकिन संतोष की बात यह है कि सबसे ज़्यादा तेल के कुएं यहीं पर हैं. इसलिए यह माना जा रहा है कि उत्तरी सूडान इन तेल के कुंओं पर नज़रें टिकाए रखेगा और ज़रूरत पड़ने पर दक्षिणी सूडान से संघर्ष भी करेगा.

जनमत संग्रह से आज़ादी

दक्षिण सूडान को स्वतंत्र किया जाए या नहीं, इसका फ़ैसला वहां की जनता को ही करना था, न कि शीर्ष पर बैठे राजनेताओं को. इसके लिए वहां जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें वहां के लोगों को या तो स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान करना था अथवा सूडान के साथ रहने के पक्ष में. 9 से 15 जनवरी तक चले इस जनमत संग्रह से यह स्पष्ट हो गया कि जनता स्वतंत्र राष्ट्र चाहती है, क्योंकि 98.83 प्रतिशत लोगों ने दक्षिणी सूडान को अलग राष्ट्र बनाने के पक्ष में मतदान किया था. इसके बाद नए राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया और तेज़ हो गई, जिस पर 9 जुलाई, 2011 को अंतिम रूप से मुहर लगा दी गई.

जश्न का माहौल

फ़िलहाल दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा में जश्न का माहौल है. दक्षिणी सूडान दुनिया का सबसे नया देश बन गया है. इस ख़ुशी में बीती 9 जुलाई को राजधानी जुबा में स्वतंत्रता समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने भी हिस्सा लिया. दरअसल, दक्षिणी सूडान को सबसे पहले सूडान ने अपने पड़ोसी देश के रूप में मान्यता दी है. इस बाबत 2005 में सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच शांति समझौता हुआ था. इसके बाद दक्षिणी सूडान को एक देश के रूप में मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो अब जाकर पूरी हुई है. दक्षिणी सूडान को अब एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिल गई है. एक जनवरी, 1956 को सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई थी, दोनों देशों ने फ़िलहाल उसी सीमा रेखा को मंजूर कर लिया है. इसी दिन ब्रिटेन ने सूडान को आज़ाद किया था. आंकड़े बताते हैं कि दक्षिणी और उत्तरी सूडान के बीच दशकों तक चले गृह युद्ध में 25 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई. संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, दक्षिणी सूडान दुनिया का 193वां और अफ़्रीका का 55वां देश होगा.

क्या है स्थिति

दक्षिण सूडान के स्वतंत्र होने के बाद यह प्रश्न उठ रहा है कि जिस आधार पर यह देश आज़ाद हुआ, क्या वे सारे मुद्दे समाप्त हो गए? ऐसा लगता तो नहीं है. वहां ग़रीबी है, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है. वहां 7 में से 1 बच्चे की मौत 5 साल की उम्र से पहले हो जाती है. 6 से लेकर 13 वर्ष के आधे बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं. प्रत्येक 7 में से एक गर्भवती महिला की मौत हो जाती है. 84 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं, केवल 6 प्रतिशत बच्चियां स्कूल जा पाती हैं और अपनी शिक्षा पूरी कर पाती हैं. विश्व में सबसे अधिक मातृत्व मृत्यु दर यहीं है.

क्या है समस्याएं

दक्षिणी सूडान इस आधार पर स्वतंत्रता की मांग कर रहा था कि उसकी संस्कृति अलग है और उत्तरी सूडान वाले उसके साथ भेदभाव करते हैं, यह स्थिति अभी भी बरक़रार है. दक्षिणी सूडान के उत्तरी और दक्षिणी इलाक़ों में वही स्थिति है, जो पूर्व में उत्तरी और दक्षिणी सूडान के बीच थी. दक्षिणी सूडान के उत्तरी और दक्षिणी भाग के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक असमानता है. सत्ता का केंद्र उत्तर में होगा. ऐसे में विवाद पुन: उत्पन्न हो सकता है. सूडान के साथ भी विवाद समाप्त नहीं हुआ है. सीमा की समस्या, कर्ज का बंटवारा, तेल का बंटवारा आदि कई मुद्दे अभी शेष हैं. साथ ही दक्षिणी सूडान के समक्ष लंबे गृह युद्ध के कारण फैली ग़रीबी और बेरोज़गारी आदि से निपटने की भी समस्या है. सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति बदतर है. इन सभी चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ेगा. नए राष्ट्र को सावधान रहने की आवश्यकता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिर हो सकती है हिंसा

सूडान के राष्ट्रपति ओमर अल बशीर ने अपने देश के बंटवारे पर दु:ख जताते हुए कहा कि शांति हासिल करने के लिए यह वाजिब क़ीमत है. साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि विवादित अबेई सीमा क्षेत्र को लेकर फिर से हिंसा शुरू हो सकती है. दक्षिणी सूडान का जन्म पिछले कई दशकों से चल रहे गृह युद्ध के बाद हुआ. बशीर ने कहा कि वह सूडान की एकता को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें दक्षिण में रहने वाले लोगों की भावनाओं का सम्मान करना पड़ा. ऐसा नहीं किया जाता तो एक बार फिर से हिंसा शुरू होने का डर था. बशीर ने स्पष्ट किया कि यदि विवादित क्षेत्रों, ख़ासकर अबेई सीमा क्षेत्र पर हुए समझौतों पर अमल नहीं हुआ तो फिर से ख़ूनख़राबा हो सकता है. अबेई उत्तरी सूडान का हिस्सा है और दक्षिण में उसका विलय तभी हो सकता है, यदि आने वाले दिनों में वहां रहने वाले बंजारे, अरब कबीले जनमत संग्रह के ज़रिए इसकी स्वीकृति देते हैं, लेकिन ऐसा होना फ़िलहाल संभव नहीं दिखता.

नाम	दक्षिण सूडान
राजधानी	जुबा
राष्ट्रपति	सल्वा कीर मयर्दित
उप राष्ट्रपति	रीक मछार
लेजिसलेचर	लेजिसलेटिव असेंबली
समग्र शांति समझौता	6 जनवरी, 2005
स्वायत्तता	9 जुलाई, 2005
स्वतंत्रता	9 जुलाई, 2011
आधिकारिक भाषा	अंग्रेजी
अन्य भाषाएं	कोलोकूल अरबीक, जुबा अरबीक, पीडगीन
क्षेत्रफल	6,19,745 वर्ग किमी.
जनसंख्या	82,60,490 (2008 की जनगणना के अनुसार)
करेंसी	सूडानीज पाउंड

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

बाबा से विदा लेकर शामा और बाला साहब ने एक तांगे में बैठकर प्रस्थान किया. वे रात को नौ बजे चितली पहुंचे और मारुति मंदिर में उन्होंने डेरा जमाया.

बाबा का मुक्तिदान

बाबा ने शामा (माधवराव देशपांडे) को बुलाया और मिरीकर के साथ चितली जाने के लिए कहा. शामा बाला साहब मिरीकर के पास आया और उसे बताया कि बाबा की आज्ञानुसार वह उसके साथ चितली जाएगा. मिरीकर ने जवाब दिया, तुम्हें साथ चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे असुविधा होगी.

सरदार काका साहब मिरीकर का बेटा बाला साहब मिरीकर कोपर गांव का मामलतदार था. वह दौरे पर चितली गांव जा रहा था. रास्ते में वह बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आया. मस्जिद में जाकर उसने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया. बाबा और बाला साहब के बीच कुशल क्षेम की और इतर बातें होती रहीं. बाबा ने उसे चेतावनी देने के स्वर में कहा, क्या तुम हमारी द्वारकामाई को जानते हो? कुछ समझ न सकने के कारण बाला साहब मिरीकर चुप रह गया. बाबा आगे कहते गए, यही (मस्जिद) हमारी द्वारकामाई है, जहां तुम बैठे हो. यह ख़तरों और चिंताओं को दूर करके उन बच्चों की रक्षा करती है, जो इसकी गोद में बैठते हैं. इस मस्जिद की अधिष्ठात्री देवी द्वारकामाई बहुत दयालु हैं. यह सरल हृदय भक्तों की माता हैं और संकट में उनकी रक्षा करती हैं. इसकी गोद में जो एक बार बैठ जाता है, उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं. जो इसकी छाया में विश्राम करता है, उसे आनंद मिलता है. जब बाला साहब मस्जिद से जाने लगा तो बाबा ने उसे भभूत दी और अपना हाथ उसके सिर पर रखा. उन्होंने फिर कहा, क्या तुम लंबा बाबा यानी सर्प को जानते हो? उन्होंने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी कसी और उसे दाहिनी कुहनी के नज़दीक लाते हुए मुट्ठी खोलकर हथेली को सांप के फन की तरह हिलाते हुए कहा, वह बहुत भयानक है, पर द्वारकामाई के बच्चों का वह क्या बिगाड़ सकता है? जब मस्जिद की अधिष्ठात्री देवी द्वारकामाई रक्षा करती हैं, तब सांप क्या कर सकता है? जितने लोग वहां उपस्थित थे, वे बाबा के इस काम और मिरीकर के संदर्भ में कही गई बात को जानने के लिए आतुर हो गए, किंतु इस विषय में बाबा से पूछने का साहस किसी को नहीं हुआ. बाला साहब मिरीकर ने बाबा को प्रणाम किया और जाने लगा. बाबा ने शामा (माधवराव देशपांडे) को बुलाया और मिरीकर के साथ चितली जाने के लिए कहा. शामा बाला साहब मिरीकर के पास आया और उसे बताया कि बाबा की आज्ञानुसार वह उसके साथ चितली जाएगा. मिरीकर ने जवाब दिया, तुम्हें साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे असुविधा होगी. शामा ने वापस आकर बाबा को मामलतदार मिरीकर की बात बताई. बाबा बोले, ठीक है, मत जाओ. हमारा तात्पर्य अच्छाई करने का है और अच्छा करेंगे. जो कुछ नियति में है, वह होगा ही.

इसी बीच बाला साहब ने फिर से सोचा और शामा को साथ चलने के लिए कहा. फिर बाबा से विदा लेकर शामा और बाला साहब ने एक तांगे में बैठकर प्रस्थान किया. वे रात को नौ बजे चितली पहुंचे और मारुति मंदिर में उन्होंने डेरा जमाया. उस समय दफ्तर में काम करने वाले नहीं आए थे, इसलिए चटाई पर बैठकर बाला साहब अख़बार पढ़ने लगा. उसका उपरना (चादर) उसकी कमर से नीचे फैला हुआ था. उसके एक हिस्से में चुपचाप आकर एक सांप कुंडली मारकर बैठ गया. उसे किसी ने नहीं देखा. वह सरसराहट की आवाज़ करता हुआ सरकने लगा. उसकी सरसराहट की आवाज़ चपरासी ने सुनी और तुरंत लालटेन लिए हुए वहां पहुंचा. सांप को देखकर वह सांप-सांप चिल्लाने लगा. बाला साहब डर से कांपने लगा. शामा भी आश्चर्यचकित रह गया. वहां उपस्थित लोग और शामा डंडे एवं लाठियां ले आए. सांप बाला साहब की कमर से सरक कर नीचे ज़मीन पर आया और मार डाला गया. इस तरह साई बाबा की भविष्यवाणी और चेतावनी सच हुई और संकट टल गया. बाबा के प्रति बाला साहब मिरीकर की आस्था और गहरी हो गई.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ ख़ाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

पूजन और साई बाबा

मूर्ति पूजा, कर्म बंधन, कर्म मार्ग, कर्म फल और पुनर्जन्म पर बाबा की पूर्ण आस्था थी. वह गुरु भक्ति के प्रबल समर्थक थे, ध्यान योग में प्रति पल निमग्न रहते थे. उन्होंने स्वयं बारह वर्ष तक तपस्या की थी और तपस्या के प्रबल पक्षपाती थे. वेदांत के तो वह मूर्तिमान स्वरूप ही थे. चराचर सृष्टि बाबा के वश में थी. वह सर्वत्र एक ही आत्मा के दर्शन करते थे. प्रकृति तो चैतन्य के अधीन रहती है, इसीलिए उन्होंने पानी से दीये जला दिए. संसार के समस्त प्राणी बाबा के अनुशासन में थे. हिंदू धर्म में अग्नि की बड़ी महिमा बताई गई है. ऋग्वेद तो अग्निमीले पुरोहितं...से ही प्रारंभ होता है. बाबा अग्नि के उपासक अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, इसीलिए वह रात-दिन धूनी जलाए रखते थे. वह साधक और सिद्ध की स्थिति को पार करके सुजान बन गए थे. भगवान शंकर की भांति बाबा भी भाग्यरेखा मिटाकर अपने भक्तों के संकट दूर कर देते थे. उन्होंने शिरडी में भूमिगत तपस्थली में अपने गुरु वेंकुश स्वामी के सानिध्य में बारह वर्ष तक कठिन तपस्या की थी. बाबा ने लोगों का मन धर्म के वास्तविक तत्व में लगाने के लिए कई चमत्कार भी किए. वह तो स्वयं मायापति त्रिलोकीनाथ भगवान थे. उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था. अपने निवास के लिए उन्होंने जीर्णशीर्ण पुरानी मस्जिद को चुना, पर उसका नाम रखा द्वारका माई मस्जिद. यह भी बाबा की लीला ही थी कि वह मस्जिद बिल्कुल मंदिर जैसी बन गई, वहां धूनी जलने लगी, श्री हरि की पूजा-आरती की जाने लगी, शंख बजाए जाने लगे, कीर्तन होने लगा, बाबा की अमृतवाणी गूंजने लगी और कृष्णाष्टमी एवं रामनवमी के त्योहार मनाए जाने लगे. बाबा का हर काम हिंदू संस्कृति के अनुसार होता था. उनकी हर बात उपदेशपूर्ण होती थी.

बाबा सदैव अपने भक्तों का ध्यान रखते और उनके दुःखों-कष्टों का निवारण करते थे. बाबा अंतर्यामी थे. वह बहिर्यामी तो हैं ही. हम भगवान को अपने से बाहर देखने का प्रयास करते हैं, पर अपने भीतर झांककर, ध्यान लगाकर अपने अंतर्यामी परमात्मा को भूलकर भी नहीं देखते. मनुष्य जीवन की असफलता का मूल कारण यही है. भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति. अर्थात हे अर्जुन, परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं. बाबा ऐसे ही अंतर्यामी थे. इसीलिए जब कभी कोई बाबा से मिलने आता था, तब वह बिना बताए ही उसका नाम और आने का प्रयोजन जान लेते थे. अंतर्यामी होने के कारण वह सर्वज्ञ थे. बाबा गुरु और गुरुभक्ति के पक्षपाती थे. उनका मत था कि सद्गुरु द्वारा मार्गदर्शन के बिना क़दम-क़दम पर भटक जाने का भय बना रहता है. वह जानते थे कि राखैं गुरु जो कोप विधाता. इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं तात्या कोते पाटिल की मौत को अपने ऊपर लेकर उसके प्राण बचाए. बाबा की इन्हीं महिमाओं की वजह से उन्हें लोग पूजते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री साई महिमा

श्री साई राम परम सत्य, प्रकाश रूप, परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता, सच्चिदानंद स्वरूप, परम पुरूष योगीराज, दयालु देवाधिदेव हैं, उनको बार-बार नमस्कार.

प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था. उन्हें मुंशी प्रेमचंद और नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है.

अनंत विजय

साहित्य की क्लियोपेट्राएं

विश्व राजनीति के पटल पर क्लियोपेट्रा एक ऐसा नाम है, जिसने अपनी ख़ूबसूरती और अपने शरीर का इस्तेमाल अपने करियर को बढ़ाने में बेहतरीन तरीक़े से किया. उसने सेक्स पॉवर को पहचानते हुए खुलकर उसका उपयोग किया और उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाकर बुलंदी पर जा पहुंची. उसने सत्ता और शक्ति हासिल करने के लिए अपने भाई से ही विवाह किया और मिस्र की सत्ता हासिल की, लेकिन भाई से मनमुटाव के चलते उसे देश छोड़कर निर्वासित होना पड़ा. निर्वासन के बाद उसने सीजर को अपनी ख़ूबसूरती के जाल में फंसाया और न केवल उसके साथ सत्ता का सुख हासिल किया, बल्कि कई सालों तक तानाशाह की तरह जीवन जिया. जब सीजर की हत्या कर दी गई तो क्लियोपेट्रा ने पूर्वी रोम के मॉर्क एंटोनी को अपने सम्मोहन के जाल में फंसाकर अकूत संपत्ति हासिल की. क्लियोपेट्रा बहुत ख़ूबसूरत नहीं थी, लेकिन वह इस बात को जानती थी कि किस तरह अपने शरीर का इस्तेमाल करके मर्दों को गुलाम बनाया जा सकता है. उसे उस हुनर का पता था, जिसके बल पर वह बड़े-बड़े लोगों को अपने मोहजाल में फंसा सकती थी. साफ़ है कि क्लियोपेट्रा ने सेक्स और अपने शरीर को एक कमॉडिटी की तरह अपने हक़ में सत्ता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया. उसने सेक्स को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा भी बना दिया था. विश्व परिदृश्य में सिर्फ़ क्लियोपेट्रा ही नहीं, बल्कि कई और महिलाएं हैं, जिन्होंने महिला होने का ज़बरदस्त रूप से फ़ायदा उठाया और अपनी देह का इस्तेमाल करके सफलता हासिल की. रूस की महान साम्राज्ञी कैथरीन ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने पति का क़त्ल किया और फिर अपने आशिक़ के साथ देश पर लगभग तीस सालों तक शासन किया. उसने भी सेक्स और सेक्सुअल पॉवर को सत्ता से जोड़कर अपनी स्थिति मज़बूत की. उसके कितने आशिक़ थे या फिर उसने अपने कितने सुरक्षा गार्डों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, यह कहना बेहद कठिन है. कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि अपने प्रेमी से शारीरिक संबंध बनाने के पहले वह नियमित तौर पर अपने एक सुरक्षाकर्मी को चुनती थी और उसके साथ एकांत में काफ़ी देर तक रोमांस करने के बाद अपने प्रेमी के पास पहुंच कर सेक्स करती थी. इस तरह उसने कई सुरक्षाकर्मियों के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लिया था, जिसकी काट नामुमकिन थी. इस तरह की महिलाओं की सूची और लंबी हो सकती है.

ऐसा नहीं है कि इस तरह की महिलाएं, जो अपनी देह को सत्ता हासिल करने का ज़रिया बनाती हैं, सिर्फ़ विदेशों या पश्चिमी देशों में हैं. इस तरह के कई उदाहरण हमारे देश में भी मिल जाएंगे, लेकिन हमारे यहां सेक्स या फिर इस तरह के संबंधों पर बातें तो ख़ूब की जाती हैं, लेकिन उसके बारे में लिखना गुनाह माना जाता है. हमारे राजनेताओं और उनकी महिला मित्रों के बारे में राजनीतिक गलियारे में ख़ूब चर्चा होती है, लेकिन इस संदर्भ में सार्वजनिक रूप से कोई बहस नहीं होती. हमारे यहां समझा जाता है कि यह उनका व्यक्तिगत जीवन है, जिसमें झांकना उनकी निजता के अधिकार का हनन होगा. लेकिन उस वक़्त हम भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति का जीवन ही सार्वजनिक हो गया है, उसका निजी कुछ नहीं रह जाता. गांधी जी भी कहा करते थे कि सार्वजनिक जीवन व्यतीत करने वालों का निजी कुछ भी नहीं रह जाता. ख़ैर, यह एक अलग विषय है, जिस पर विस्तार से बहस की जा सकती है. राजनीति के अलावा अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो यहां भी आपको कई क्लियोपेट्रा मिल जाएंगी, जिन्होंने अपनी देह का इस्तेमाल साहित्य में अपने करियर को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में बख़ूबी किया. यहां मैं भी किसी एक या दो का नाम लेकर नाहक़ विवाद खड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन साहित्यिक हलके में लोग इस तरह की क्लियोपेट्राओं को बख़ूबी जानते हैं. हिंदी साहित्य में देह मुक्ति आंदोलन के प्रणेता हंस के यशस्वी संपादक राजेंद्र यादव तो इन क्लियोरेट्राओं से घिरे ही रहे हैं, कई को तो उन्होंने बढ़ावा भी दिया है (क्षमा सहित यह बात कह रहा हूं, लेकिन पूरा साहित्य जगत उन नामों से वाकिफ है).

मैं यह नहीं कह रहा कि राजेंद्र जी साहित्य के सीजर हैं, लेकिन उनके दरबार में समय-समय पर इस तरह की एक-दो महिला लेखिकाएं हमेशा से रही हैं. कई ने तो, जिनमें कुछ प्रतिभा थी, आगे चलकर लेखन में ख़ूब पैसा और यश दोनों कमाया, लेकिन जिनमें प्रतिभा नहीं, सिर्फ़ महत्वाकांक्षा थी, वे कुछ समय के लिए हिंदी साहित्य के आकाश पर धूमकेतु की तरह चमक कर ग़ायब हो गईं. किसी के एक-दो संग्रह आए तो किसी को कोई छोटा-मोटा पुरस्कार मिल गया. उनके साहित्य के आकाश पर चमकने के साहित्येत्तर कारण रहे हैं. इन वजहों को राजेंद्र जी चाहें तो खोल सकते हैं और साहित्य की क्लियोपेट्राओं के नाम भी बता सकते हैं, बता देना भी चाहिए. लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्थितियों और नामों को काल्पनिक रूप देकर वास्तविकता को छुपा दिया, उसके बाद उनसे तो यह उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती है कि वह हिंदी साहित्य की क्लियोपेट्राओं के नाम उजागर करें, जानते वह सब कुछ हैं. राजेंद्र यादव के बाद लोगों की उम्मीद अशोक वाजपेयी से भी हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर अशोक जी की जो छवि है, उसमें उनसे यह अपेक्षा करना बेमानी है कि वह हिंदी की इन क्लियोपेट्राओं के नाम लेंगे. अपनी बेबाक बयानी के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति विभूति नारायण राय जिस तरह से छिनाल विवाद में अपना हाथ जला चुके हैं, उसके बाद तो उनसे इन स्त्रियों के मामले में कुछ भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है.

हिंदी साहित्यिक परिदृश्य में अब काफ़ी बदलाव देखा जा सकता है. कई लेखिकाएं तो खुले तौर पर दैहिक उदारवाद की बात करती हैं. बातचीत में जो बिंदासपन और खुलापन है, वह उनके स्वभाव में भी देखा जा सकता है. उनके लिए सेक्स अब टैबू नहीं है. देह उनके लिए भी उसी तरह उपभोग की वस्तु है, जिस तरह से मर्दों के लिए. अपने पुरुष मित्रों के साथ सेक्स संबंध बनाने में उन्हें न तो कोई एतराज़ होता है और न झिझक. लेकिन पैसा और यश कमाने के लिए जिस तरह से शरीर का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, वह चिंता की बात है. हमारे यहां क्लियोपेट्रा अब एक नाम नहीं रही, बल्कि यह एक प्रवृत्ति के तौर पर स्थापित हो चुकी है. एक संज्ञा के प्रवृत्ति में बदलने की जो प्रक्रिया है, वह चिंता की बात है. कई नवोदित लेखिकाएं इस राह पर चलकर शॉर्टकट में सफलता हासिल करना चाहती हैं, जो साहित्य के लिए चिंता की बात है, लेकिन उन लेखिकाओं को शॉर्टकट में सफलता की राह दिखाने के लिए कई कवि मित्र सदैव तत्पर रहते हैं. उन्हें तो तलाश रहती है बस मौक़े की. मेरा यह कहने का मतलब क़तई नहीं है कि साहित्य में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए सभी लेखिकाएं अपने शरीर का इस्तेमाल करती हैं और न ही मैं स्त्रियों या लेखिकाओं को अपमानित करने के लिए यह लेख लिख रहा हूं. मेरी मंशा उन लेखिकाओं को हतोत्साहित करने की है, जो बग़ैर किसी प्रतिभा के सिर्फ़ अपनी देह के बूते हिंदी साहित्य का सारा आकाश छेकना चाहती हैं.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

जन्मदिवस 31 जुलाई पर विशेष

प्रेमचंद के सपनों का भारत

सरोज ख़ान बातिश

मुंशी प्रेमचंद के सपनों का भारत निश्चित ही गांधी के सपनों का भारत था. गांधी ने आज़ाद भारत का बड़ा तल्ख़ तजुर्बा किया. प्रेमचंद इस मायने में भाग्यशाली थे कि उन्होंने आज़ाद भारत का दु:ख और पराभव नहीं देखा. बेकल उत्साही के एक गीत का यह मुखड़ा प्रेमचंद के सपनों के भारत को सजीव करता है:

स्टेशनों पे पानी पिलाने लगे अछूत,
हां, पनघटों पे थोड़ा-बहुत भेदभाव है.

प्रेमचंद समन्वयवादी भारत को देखना चाहते थे, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक होकर अपने लिए केवल आरक्षण की मांग करता हुआ न दिखे. वह व्यक्ति को जगाना चाहते थे, उसकी ख़ुद्दारी को ज़िंदा रखना चाहते थे. उन्हें समान भारतीय नागरिकता में विश्वास था. बेहतर तो यह होगा कि प्रेमचंद के सपनों के भारत को समझने के लिए हम उनकी एक सबसे छोटी कहानी राष्ट्र का सेवक देखें. हमारे लिए यह भी एक आश्चर्य का विषय हो सकता है कि गोदान जैसी भारी-भरकम रचना करने वाला लेखक अपनी बात एक कहानी के रूप में केवल कुछ पंक्तियों में भी व्यक्त कर सकता है.

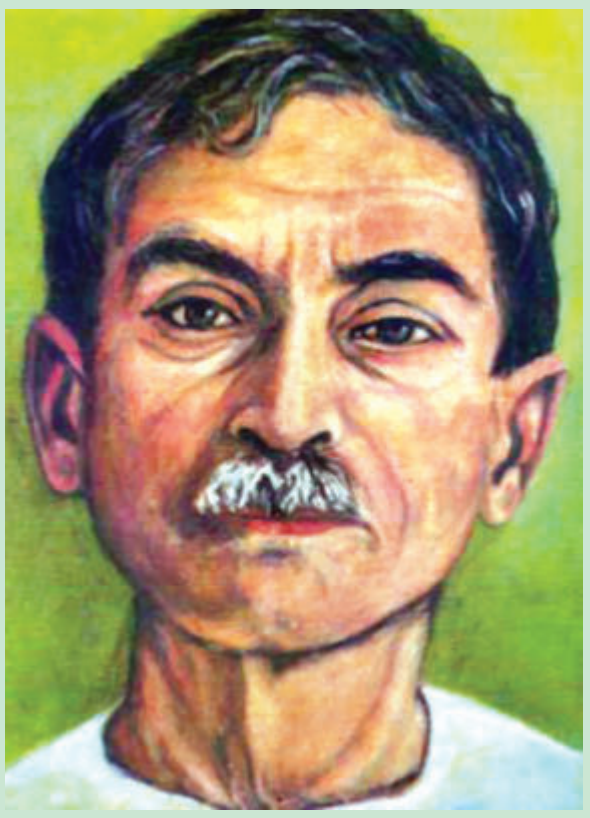

प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था. उन्हें मुंशी प्रेमचंद और नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है. उनका जन्म 31 जुलाई, 1880 को वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था. आठ अक्टूबर, 1936 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया. उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि सबसे आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है. यह बात उनके साहित्य में उजागर हुई. उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी थी. उन्होंने कई महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन भार संभाला और छह साल तक माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया. इसके बाद उन्होंने बनारस से अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया. इसके अलावा उन्होंने जागरण नामक एक साप्ताहिक और निकाला. उन्होंने लखनऊ में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की. वर्ष 1934 में प्रदर्शित मज़दूर नामक फिल्म की कथा लिखी और कांट्रेक्ट की साल भर की अवधि पूरी किए बिना दो महीने का वेतन छोड़कर बनारस आ गए, क्योंकि मुंबई का माहौल उन्हें रास नहीं आया. प्रेमचंद ने क़रीब तीन सौ कहानियां, कई उपन्यास और कई लेख लिखे. उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे और अनुवाद कार्य किया. प्रेमचंद की कई साहित्यिक कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ. गोदान उनकी कालजयी रचना है. कफ़न उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्र का सेवक

राष्ट्र के सेवक ने कहा कि देश की मुक्ति का एक ही उपाय है और वह है नीचों से भाईचारे का सुलूक, पतितों के साथ बराबरी का बर्ताव. दुनिया में सभी भाई हैं, कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं. दुनिया ने जयकार की. कितनी विशाल दृष्टि है, कितना भावुक हृदय. उनकी सुंदर लड़की इंदिरा ने सुना और चिंता के सागर में डूब गई. राष्ट्र के सेवक ने नीची जाति के नौजवानों को गले लगाया. दुनिया ने कहा, यह फ़रिश्ता है, पैग़ंबर है, राष्ट्र की नैया का खेवैया है. इंदिरा ने देखा तो उसका चेहरा चमकने लगा. राष्ट्र का सेवक नीची जाति के नौजवानों को मंदिर में ले गया, देवता के दर्शन कराए और कहा कि हमारा देवता ग़रीबी में है, ज़िल्लत में है, पस्ती में है. दुनिया ने कहा, कैसे शुद्ध अंत:करण का आदमी है, कैसा ज्ञानी! इंदिरा ने देखा और मुस्कराई. इंदिरा राष्ट्र के सेवक के पास जाकर बोली, श्रद्धेय पिता जी, मैं मोहन से ब्याह करना चाहती हूं. राष्ट्र के सेवक ने प्यार की नज़रों से देखकर पूछा, मोहन कौन है? इंदिरा ने उत्साह भरे स्वर में कहा, मोहन वही नौजवान है, जिसे आपने गले लगाया, जिसे आप मंदिर में ले गए, जो सच्चा बहादुर और नेक है. राष्ट्र के सेवक ने प्रलय की आंखों से उसकी ओर देखा और मुंह फेर लिया.

किताब मिली

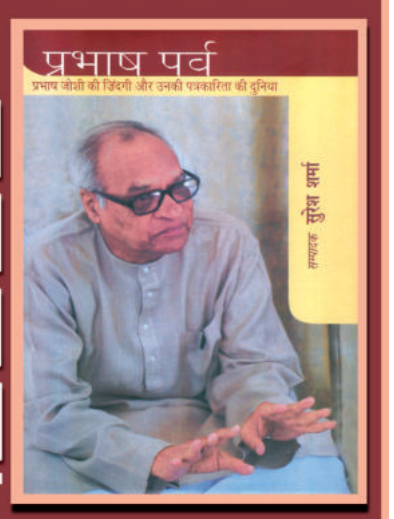

पुस्तक का नाम
प्रभाष पर्व
लेखक
सुरेश शर्मा
प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन
मूल्य
600 रुपये

इस किताब में दिवंगत पत्रकार प्रभाष जोशी की ज़िंदगी और उनकी पत्रकारिता के बारे में जानकारी दी गई है.

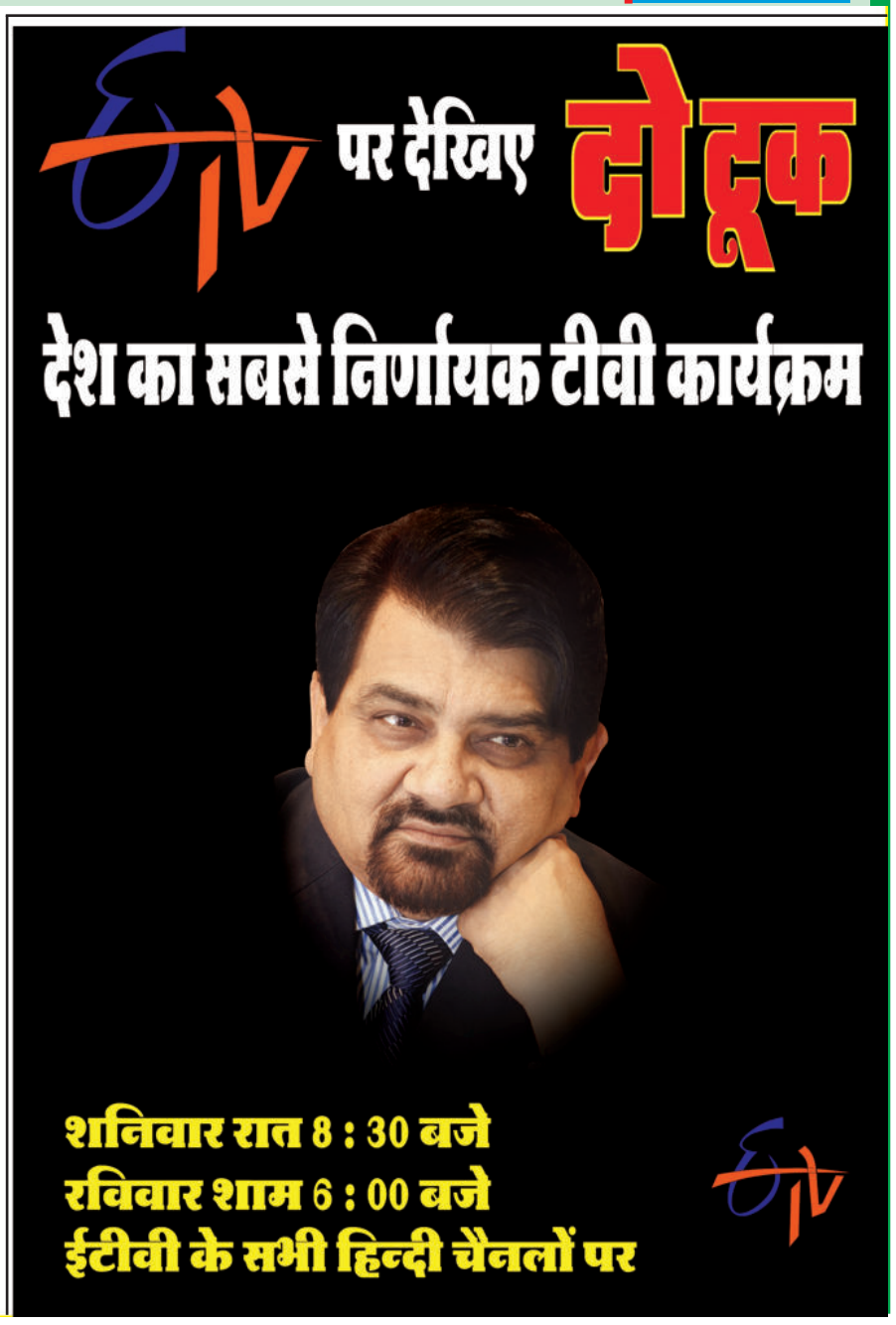

नोकिया 700 यानी नोकिया जेटा में 3.2 इंच का कैप्टिव टचस्क्रीन लगा होगा. इसके साथ ही इसमें 5 मेगा पिक्सल कैमरा और एक गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर भी मौजूद होगा.

अब उड़िए आसमान में

जेटपैक को न्यूजीलैंड की कंपनी मार्टिन एयरक्राफ्ट ने तैयार किया है. ख़ास बात यह है कि इस जेटपैक के सहारे उड़ने के लिए न तो किसी ख़ास ट्रेनिंग की जरूरत है और न पायलट के लाइसेंस की.

गए वे दिन, जब खुली हवा में अपनी सवारी के ज़रिए उड़ान भरना केवल दिग्गज धनकुबेरों के वश की बात होती थी, क्योंकि अब पंछियों की तरह खुली हवा में उड़ने के लिए करोड़ों नहीं, बल्कि मात्र 45 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ेगी. दरअसल, न्यूजीलैंड और अमेरिका में सफलता हासिल करने के बाद निजी मशीन जेटपैक भारतीय बाज़ार में आने को तैयार है. जेटपैक को न्यूजीलैंड की कंपनी मार्टिन एयरक्राफ्ट ने तैयार किया है. ख़ास बात यह है कि इस जेटपैक के सहारे उड़ने के लिए न तो किसी ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत है और न पायलट के लाइसेंस की. जेटपैक के सहारे एक बार में केवल एक व्यक्ति ही आसमान की सैर कर सकता है. रक्षा क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हवाई निगरानी, तेज़ी से कार्रवाई करने और सैनिकों को एक पोत से दूसरे पोत पर पहुंचाने में हो सकता है. जेटपैक के ज़रिए व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और क़रीब 30 मिनट तक हवा में रह सकता है. हाल में दिल्ली में आयोजित होमलैंड सिक्योरिटी इंडसेक एक्सपो में इसका प्रदर्शन किया गया था. लोग निजी इस्तेमाल के लिए भी इसे ख़रीद सकते हैं. इसमें सभी ज़रूरी सुरक्षा उपाय हैं और आपात स्थिति के लिए पैराशूट भी लगा हुआ है.

नोकिया का नया हैंडसेट

फिनलैंड की हैंडसेट निर्माता कंपनी नोकिया को भारत में फ़िलहाल कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह अब भी भारतीय ग्राहकों के बीच सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय ब्रांड है. कंपनी बाज़ार में अपना एक और बेहतरीन मोबाइल हैंडसेट उतारने जा रही है–नोकिया 700, जिसे एक और नाम दिया गया है, नोकिया जेटा. कंपनी ने इसे स्मार्ट फोन की श्रेणी में उतारने का मन बनाया है. नोकिया 700 यानी नोकिया जेटा में 3.2 इंच का कैप्टिव टचस्क्रीन लगा होगा. इसके साथ ही इसमें 5 मेगा पिक्सल कैमरा और एक गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर भी मौजूद होगा. संभव है कि यह ख़ास फोन कंपनी आगामी सितंबर महीने में लांच करे. कंपनी ने अपने सभी नए हैंडसेट्स में मोबाइल मनी एप्लीकेशन की सुविधा देने का ऐलान किया है, जिसकी मदद से आसानी से मोबाइल फोन के जरिए मनी ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा. कंपनी ने अपने नए हैंडसेट एक्स 1–01 में यह सुविधा उपलब्ध करा दी है. इस सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आपके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की तरफ़ से भी मोबाइल मनी की सुविधा दी जा रही हो. मोबाइल मनी के ज़रिए बिलों का भुगतान, मनी ट्रांसफर, प्रीपेड सिम टॉपअप समेत कई अन्य सेवाओं का फ़ायदा उठाया जा सकता है.

कपड़ा धुलना हुआ आसान

मशीन में लगा वेरियोसॉफ्ट ड्रम सिस्टम रेशम जैसे मुलायम कपड़ों को हल्के तरीक़े से धुलता है तो ज्यादा मिट्टी लगे कपड़ों को यूनिक ड्रॉप शेप के स्ट्रक्चर से कड़ाई से धुलाई करते हुए दाग़ हटाता है.

इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली जर्मनी की कंपनी सीमंस ने अपनी आईक्यू सीरीज की वाशिंग मशीन अपग्रेड की है. इसके तहत कंपनी ने तीन नए मॉडल बाज़ार में उतारे हैं. आईक्यू सीरीज की नई वाशिंग मशीनों में डब्ल्यूएम 12 ई 360 इन, डब्ल्यूएम 12 एस 468 एमई और डब्ल्यूएम 14 एस 790 जीसी ज़्यादा वज़न का भार लेते हुए एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों की धुलाई को आसान बनाती हैं. इस सीरीज की मशीनों में ज़्यादा वज़न के कपड़े एक साथ धोए जा सकते हैं. इन मशीनों में दी गई ख़ास वेरियोपरफेक्ट तकनीक दो तरह के विकल्प उपलब्ध कराती है. पहला है स्पीडप परफेक्ट मोड, जिसमें एक ख़ास वज़न के कपड़ों को धुलने में साठ प्रतिशत कम वक़्त लगता है. दूसरा विकल्प है इकोपरफेक्ट मोड, जिससे तीस प्रतिशत ऊर्जा की बचत होती है. इसका इलाबोरेट सेंसर सिस्टम सुनिश्चित करता है कि एक तय मात्रा के कपड़ों को धुलने के लिए उचित मात्रा में ही पानी का इस्तेमाल हो रहा हो. मशीन में लगा वेरियोसॉफ्ट ड्रम सिस्टम रेशम जैसे मुलायम कपड़ों को हल्के तरीक़े से धुलता है तो ज़्यादा मिट्टी लगे कपड़ों को यूनिक ड्रॉप शेप के स्ट्रक्चर से कड़ाई से धुलाई करते हुए दाग़ हटाता है. घिसने की आवाज़ को कम करने के लिए इसमें एंटी वाइब्रेशन साइडवॉल भी लगे हैं.

सुपर बास मल्टी मीडिया हेडसेट

जेब्रोनिक्स ने जेडईबी-3100 एचएमवी हेडसेट को 20 हर्ट्ज से 25000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्षमता के साथ उतारा है. यह इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इससे गाने सुनते या कॉल करते समय बेहतरीन साउंड क्वॉलिटी मिले. अब उपभोक्ताओं के पास उच्च आवाज़ और बास टोन के बीच बेहतरीन संतुलन बनाते हुए सुनने का आनंददायक एहसास लेने का मौक़ा है.

जेब्रोनिक्स ब्रांड के तहत कंप्यूटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान, संचार उपकरणों से जुड़े उत्पाद एवं एसेसरीज की आपूर्ति करने वाली भारत की अग्रणी कंपनी टॉप नॉच इंफोट्रॉनिक्स ने सुपर बास मल्टी मीडिया हेडसेट जेडईबी–3100 एचएमवी लांच किया है. जेब्रोनिक्स अपने ग्राहकों को सुपर बास मल्टी मीडिया हेडसेट के ज़रिए बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस मुहैया कराती है. 1.8 मीटर लंबे केबल के साथ लगा रिमोट कंट्रोल इसका इस्तेमाल और आसान बना देता है. हेडसेट में मुलायम सतह और केबल की अतिरिक्त लंबाई जैसी ख़ूबियां हैं. जेब्रोनिक्स ने जेडईबी–3100 एचएमवी हेडसेट को 20 हर्ट्ज से 25000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्षमता के साथ उतारा है. यह इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इससे गाने सुनते या कॉल करते समय बेहतरीन साउंड क्वॉलिटी मिले. अब उपभोक्ताओं के पास उच्च आवाज़ और बास टोन के बीच बेहतरीन संतुलन बनाते हुए सुनने का आनंददायक एहसास लेने का मौक़ा है. इसके अंदर बिल्ट इन माइक्रोफोन है, जिससे उपभोक्ता सफ़र के दौरान हैंड्स फ्री कॉल का मज़ा भी वास्तविक आवाज़ के साथ उठा सकते हैं.

जेब्रोनिक्स मल्टी मीडिया हेडसेट बेकार की आवाज़ को अलग कर देता है यानी यह आपके कानों तक हल्ला–गुल्ला नहीं पहुंचने देता है. इससे आपकी सुनने की क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है. जेडईबी–3100 एचएमवी में है उच्च तकनीक और बेहतरीन ब्लैक और रेड डिजाइन. जेडईबी–3100 एचएमवी का एडवांस्ट ईयरमफ जहां कान को आराम देता है, वहीं बेहतरीन साउंड क्वालिटी भी. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह 3.5 एमएम ऑडियो जैक वाले किसी भी डिवाइस के साथ इस्तेमाल हो सके. जेब्रोनिक्स जेडईबी–3100 एचएमवी हेडसेट देश भर में सभी अग्रणी रिटेल स्टोरों पर 525 रुपये में उपलब्ध है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नई नवेली स्विफ्ट

भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने लोकप्रिय मॉडल स्विफ्ट को नए अंदाज़ में लांच करने की घोषणा तो बहुत पहले कर दी थी, लेकिन अब वह वक़्त है, जब आप नई नवेली स्विफ्ट को सड़कों पर दौड़ते हुए देखेंगे. नई स्विफ्ट पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जनों में उपलब्ध है. इसमें एक ख़ास तरीक़े की प्लास्टिक से बने फ्यूल टैंक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे गाड़ी का वज़न कम हो गया है. यही वजह है कि नई स्विफ्ट पुरानी स्विफ्ट से बेहतर माइलेज देगी. स्विफ्ट का मौजूदा पेट्रोल वर्जन 17.9 किलोमीटर का माइलेज देता है, वहीं नई स्विफ्ट में एक लीटर में तक़रीबन 20 किलोमीटर का सफ़र तय किया जा सकेगा. इसी तरह मौजूदा स्विफ्ट का डीजल वर्जन 21 किलोमीटर का माइलेज देता है, जबकि नई स्विफ्ट का डीजल वर्जन एक लीटर में 24 किलोमीटर का सफ़र तय करता है. नई स्विफ्ट को ज़्यादा लंबा बनाया गया है. बाज़ार में मौजूद स्विफ्ट के अलग-अलग मॉडलों की क़ीमत 3.9 से लेकर 5.5 लाख रुपये के बीच है. नई स्विफ्ट की क़ीमत में 15,000 से लेकर 25,000 रुपये तक की बढ़ोत्तरी की गई है.

स्विफ्ट का मौजूदा पेट्रोल वर्जन 17.9 किलोमीटर का माइलेज देता है, वहीं नई स्विफ्ट में एक लीटर में तक़रीबन 20 किलोमीटर का सफ़र तय किया जा सकेगा.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

कप्तान धोनी ड्रा करने के फ़ैसले को सही ठहराते हुए कह रहे थे कि खेलने का फ़ैसला जोखिम वाला होता, क्योंकि अगर हम हारते तो पूरी सीरीज़ की जीत ख़तरे में पड़ जाती.

इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल

कब कौन सा मैच

दिन	तारीख़	टीम-1	बनाम	टीम-2	मैदान	समय
पहला टेस्ट	21 जुलाई, 2011	भारत	बनाम	इंग्लैंड	लॉर्ड्स	3.30 बजे
दूसरा टेस्ट	29 जुलाई, 2011	भारत	बनाम	इंग्लैंड	ट्रेंड बिज	3.30 बजे
तीसरा टेस्ट	10 अगस्त, 2011	भारत	बनाम	इंग्लैंड	एजबैरटन	3.30 बजे
चौथा टेस्ट	18 अगस्त, 2011	भारत	बनाम	इंग्लैंड	ब्रिट इंश्योरंस ओवल	3.30 बजे
टी-20	31 अगस्त, 2011	भारत	बनाम	इंग्लैंड	ओल्ड ट्रेफोर्ड	12.30 बजे
पहला वनडे	3 सितंबर, 2011	भारत	बनाम	इंग्लैंड	इमीरेट्स डरहम आईसीजी	2.45 बजे
दूसरा वनडे	6 सितंबर, 2011	भारत	बनाम	इंग्लैंड	रोज बॉल	6.30 बजे
तीसरा वनडे	8 सितंबर, 2011	भारत	बनाम	इंग्लैंड	ब्रिट इंश्योरंस ओवल	6.30 बजे
चौथा वनडे	11 सितंबर, 2011	भारत	बनाम	इंग्लैंड	लॉर्ड्स	2.45 बजे
चौथा वनडे	15 सितंबर, 2011	भारत	बनाम	इंग्लैंड	कार्डिफ	6.30 बजे

टेस्ट सीरीज भारत-वेस्टइंडीज

जीते हैं, पर शान से नहीं

राजेश एस कुमार

वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर फ़तह तो हासिल कर ली, लेकिन कई मायने में इस जीत को काफ़ी फीकी कहा जा सकता है. फीकी इसलिए, क्योंकि जिस मुक़ाम और रैंकिंग पर टीम इंडिया आज खड़ी है, उस जगह पर इस टीम से कंप्रोमाइज करने की उम्मीद शायद किसी को नहीं थी. वेस्टइंडीज के आख़िरी टेस्ट मैच में धोनी ने जिस तरह 90 गेंदों में 86 रन बनाने को बड़ी चुनौती मानते हुए मैच को ड्रा के अंजाम तक पहुंचाया, वह कहीं न कहीं इस बात की तरफ़ इशारा करता है कि टीम इंडिया में अभी भी वर्ल्ड चैंपियन वाला कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हुआ है. अजीब बात है, एक तरफ़ हम वर्ल्ड चैंपियन होने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ़ हम इतना जोखिम भी नहीं ले सकते कि 90 गेंदों में 86 रन बनाने के लिए अपने खिलाड़ियों को मैदान पर उतारें. या फिर इसे यूं कहें कि धोनी को आधी से ज़्यादा टीम पर इतना भी भरोसा नहीं था कि वह इस लक्ष्य को पा सकेगी. इसलिए जल्दी-जल्दी में सीरीज अपने नाम करने के चक्कर में धोनी ने मैच ड्रा करा दिया. टी-20 के दौर में अगर 15 ओवरों में 86 रन भी बनाने का माद्दा आपमें नहीं है तो फिर आपको किस आधार पर वर्ल्ड चैंपियन का ख़िताब हासिल है. निश्चित तौर पर धोनी के इस फ़ैसले से क्रिकेट प्रेमियों को निराशा हुई होगी.

मैच के आख़िरी दिन वेस्टइंडीज़ ने अपनी दूसरी पारी में छह विकेट पर 224 रनों से आगे खेलना शुरू किया था और चंद्रपाल ने अपना शतक पूरा किया, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के ख़िताब से भी नवाज़ा गया, लेकिन अगर भारत ने पूरा मैच खेला होता तो मैन ऑफ द मैच का दावेदार भारत भी हो सकता था. इसके साथ ही जीत का स्वाद भी बढ़ सकता था, लेकिन धोनी को शायद अपने रिकॉर्ड की चिंता ज़्यादा थी. वह अपनी कप्तानी में जीत का औसत कम नहीं करना चाहते थे. वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 204 रन बनाने के बाद दूसरी पारी में 322 रन बनाए थे. भारत की दूसरी पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और अभिनव मुकुंद को पहली ही गेंद पर एडवर्डन ने पगबाधा आउट कर दिया. इसके बाद राहुल द्रविड़ और मुरली विजय ने पारी को संभाला. विजय ने 45 रन बनाए, वहीं द्रविड़ 34 बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे. विजय के आउट होने के बाद रन गति तेज़ करने के लिए रैना को भेजा गया, लेकिन वह 8 रन

बनाकर ही आउट हो गए. द्रविड़ और लक्ष्मण टिक कर खेल रहे थे, उसी दौरान मैच को ड्रा मान लेने का फ़ैसला किया गया. नतीजतन, भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेला गया तीसरा और आख़िरी टेस्ट मैच बिना किसी हार-जीत के समाप्त हो गया. अगर भारतीय गेंदबाज़ चाहते तो इस मैच का नतीजा निकल सकता था, लेकिन भारतीय कप्तान में जीत का वह जज्बा और आत्मविश्वास ही नहीं दिख रहा था, जिससे लगे कि वह सीरीज पर पूरी तरह क़ब्ज़ा करना चाहते हैं. वहीं वेस्टइंडीज की तरफ़ से चंद्रपाल और क्रिक ने अपनी टीम को हार से बचा लिया. दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 161 रनों की भागीदारी निभाई.

भारत के तेज़ गेंदबाज़ ईशांत शर्मा को उनके ज़बर्दस्त प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया. ईशांत ने आख़िरी टेस्ट में छह विकेट लिए, जबकि पूरी सीरीज़ में उन्होंने 23 विकेट लिए. कप्तान धोनी ड्रा करने के फ़ैसले को सही ठहराते हुए कह रहे थे कि खेलने का फ़ैसला जोखिम वाला होता, क्योंकि अगर हम हारते तो पूरी सीरीज़ की जीत ख़तरे में पड़ जाती. इसलिए हमने ड्रा करने का फ़ैसला स्वीकार किया. अगर धोनी ख़ुद क्रीज पर आते, उन्होंने द्रविड़ का साथ होता और उनके बाद भी कई बल्लेबाज़ अगर मान लिया जाए कि औसतन 10-15 रन भी बनाते तो क्या मैच जीता नहीं जा सकता था. इस बात पर धोनी को मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि टेस्ट में जीत के ऐसे मौक़े कम ही आते हैं. ड्रा करना कोई शान की बात नहीं होती है और न ही ड्रा करने का तरीक़ा इतनी आसान परिस्थितियों में लिया जाता है. ड्रा तो कप्तान को उस समय करना चाहिए, जब उसे लगे कि मैच जीतना अब नामुमकिन सा है.

इस आख़िरी टेस्ट मैच में कोई भी इस बात से इत्तेफ़ाक़ नहीं रखता होगा कि केवल तीन विकेट खोने के बाद 90 गेंदों में 86 रनों का लक्ष्य पाने के लिए आपकी लगभग पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठी है और जीत के लिए आप आगे बढ़ने के बजाय ड्रा करने का फ़ैसला कर लें. ड्रा करने का फ़ैसला तो ज़्यादातर हारने वाली टीम लेती हैं. इसका मतलब यह मान लेना चाहिए कि धोनी कहीं न कहीं हार के मानसिक दबाव में होंगे और उन्होंने जीतने की सोची ही नहीं. यहां पर धोनी को वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से सबक़ लेना चाहिए. अगर आपको बादशाहत क़ायम रखनी है तो विपक्षी टीम को पूरी तरह से रौंदना होगा, लेकिन जो जीत धोनी ने वेस्टइंडीज पर हासिल की है, उसमें वह बात नहीं दिखाई देती. इस जीत के लिए तो यही कहा जा सकता है कि जीते तो मगर शान से नहीं.

rajeshy@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 25 जुलाई-31 जुलाई 2011

दीपिका को आरक्षण में सैफ अली ख़ान का साथ मिला है, जिनके साथ वह लव आज कल में काम कर चुकी हैं. दोनों की जोड़ी को उसमें बेहद सराहा गया था.

हिट शो के लिए तरसते शो मैन-5

आशुतोष क्यों नहीं खेल रहे जी जान से

सुषमा गुप्ता

आशुतोष गोवारिकर की अगली फिल्म कौन सी होगी. ख़बर आ रही है कि वह भगवान बुद्ध पर काम कर रहे हैं और बुद्ध के रोल के लिए वह एक्टर की तलाश में हैं. बीच-बीच में यह ख़बर भी आई कि वह अक्षय कुमार के साथ एक्शन फिल्म बनाना चाहते हैं. उनकी पिछली दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही हैं और उन्हें एक हिट की तलाश है. हालांकि वह कहते हैं कि उन्हें हिट और फ्लॉप से फ़र्क़ नहीं पड़ता, लेकिन ख़बरों पर यकीन करें तो आज आशुतोष गोवारिकर के साथ कोई बड़ा अभिनेता काम करने से कतरा रहा है. ख़बर यह भी है कि शाहरुख़ उन्हें स्वदेस के बाद साफ़ मना कर चुके हैं. कोई दस साल पहले लगान के साथ जिसने भारतीय फिल्मोद्योग को ग्लोबल बनाने में अहम योगदान किया, जिस फिल्मकार के साथ हर बड़ा सितारा काम करना चाहता था, लोग अब उससे कतरा क्यों रहे हैं?

बात 90 के दशक के शुरुआती सालों की है. रामायण और महाभारत के बाद टेलीविज़न हर घर में पहुंच चुका था, उस वक़्त के विज्ञापनों में कुछ चेहरे बेहद आम थे. उन्हीं में से एक थे आशुतोष गोवारिकर. कई फिल्मों में अभिनय करने के बाद आशुतोष ने पर्दे के पीछे का रुख़ किया. 1993 में उन्होंने पहली फिल्म बनाई पहला नशा. दीपक तिजोरी, रवीना टंडन और पूजा भट्ट के साथ बनाई गई यह फिल्म हॉलीवुड की फिल्म बॉडी डबल से प्रेरित थी. फिल्म का वही हश्र हुआ, जो उस दौर की हॉलीवुड से कहानी चुराई फिल्मों का होता था यानी फ्लॉप, लेकिन आशुतोष ने हिम्मत नहीं हारी और दो साल बाद रोमांटिक आमिर खान को एक्शन हीरो बनाकर ले आए अपनी अगली फिल्म बाज़ी में. 1995 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में आमिर के साथ थीं उस दौर की हॉट अभिनेत्री ममता कुलकर्णी. फिल्म हिट नहीं हुई, लेकिन आमिर को इस फिल्म ने एक अलग ही पहचान दी. उनके अभिनय की रेंज लोगों को नज़र आई. एक तरफ़ उन्होंने एक्शन सीन काफ़ी अच्छे किए तो दूसरी तरफ महिला गेटअप में आइटम सांग गाया, जिसमें आमिर को काफ़ी पसंद किया गया. इस फिल्म से आशुतोष गोवारिकर ने यह संदेश दे दिया कि वह संभावनाओं से परिपूर्ण फिल्मकार हैं.

वर्ष 2000. आमिर ख़ान के करियर का ख़राब वक़्त. दो साल से उनकी कोई हिट नहीं आई थी. उनकी पिछली तीन फिल्में मन, अर्थ (1947) और मेला बुरी तरह फ्लॉप हो गई थीं. अपने पैर जमाए रखने के लिए आमिर को हिट की दरकार थी और इस बार उन्होंने भरोसा किया था अब तक नाकामयाब रहे निर्देशक आशुतोष गोवारिकर पर. वह आशुतोष के साथ लगान नामक ऐसी फिल्म बना रहे थे, जिसका विषय (क्रिकेट) कभी भी हिट नहीं रहा और कहानी भी गांव की थी, जिसे हिंदी सिनेमा कब का भुला चुका था. गोवारिकर एक ऐसे विषय पर काम कर रहे थे, जिस पर जावेद अख्तर ने आमिर को फिल्म न बनाने की सलाह दी थी, लेकिन आमिर को जावेद अख्तर से ज़्यादा भरोसा आशुतोष की कहानी पर था, क्योंकि यह फिल्म की कहानी ही थी, जिसने आमिर को निर्माता बनने के लिए प्रेरित किया था. फिल्म बनी. लगान. सुपर-डुपर हिट हुई और ऑस्कर के आख़िरी पांच में पहुंची. हर लिहाज़ से यह फिल्म अद्भुत थी और इसने हिंदी फिल्मोद्योग के सारे फॉर्मूले तोड़ दिए. फिल्म की अभूतपूर्व कामयाबी ने आशुतोष गोवारिकर को इंडस्ट्री के सबसे सफल निर्देशकों की कतार में ला खड़ा किया. आशुतोष ने अगली फिल्म पर काम शुरू किया. इस बार उनके साथ आमिर नहीं, बल्कि शाहरुख़ थे. फिल्म का नाम था स्वदेस, जो विदेशों में बसे भारतीयों की वापसी पर आधारित थी. फिल्म का विषय शानदार था. कलाकारों ने बेहतरीन काम किया. फिल्म के हीरो शाहरुख़ और संगीतकार ए आर रहमान ने अपने करियर का उत्कृष्ट काम किया, लेकिन फिल्म चल नहीं पाई. लगान में जो बात फिल्म को सबसे शानदार बना रही थी, वह थी उसकी पटकथा. उस पर आशुतोष ने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन इस बार अच्छा विषय होने के बाद भी पटकथा दमदार नहीं थी. इसमें उतार-चढ़ाव कम था. इसका ख़ामियाज़ा फिल्म को उठाना पड़ा. इसमें कोई दो राय नहीं कि शाहरुख़ ने फिल्म में अपने करियर का सबसे उत्कृष्ट काम किया, लेकिन दर्शकों को सुपरस्टार शाहरुख देखने की आदत थी और आशुतोष ने इसमें उन्हें एक कलाकार बना दिया. शायद यह बात दर्शकों को पच नहीं पाई. हालांकि आलोचकों को फिल्म काफ़ी पसंद आई.

स्वदेस के बाद आशुतोष की अगली फिल्म थी 2008 में रिलीज़ हुई जोधा अकबर. जोधा अकबर के ज़रिए आशुतोष एक बार फिर अतीत में गए और भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक अकबर की प्रेम कहानी को केंद्र में रखकर यह फिल्म बनाई. हालांकि दोनों के प्रेम को लेकर विवाद भी हुआ, क्योंकि कई इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं कि जोधा नामक कोई राजपूत महिला अकबर की रानी बनी, लेकिन फिल्म अपने शानदार सेट्स, उम्दा संगीत और बेजोड़ अभिनय से हिट साबित हुई. हालांकि पीरियड फिल्म होने के बाद भी यह लगान जैसा प्रभाव नहीं जमा पाई. पटकथा में और कसावट की गुंजाइश थी. अगले ही साल आशुतोष गोवारिकर एक और प्रयोगधर्मी फिल्म लेकर आए प्रियंका चोपड़ा और हरमन बावेजा के साथ व्हाट्स योर राशि. फिल्म को रोमांटिक कॉमेडी बताया गया, लेकिन इसमें न तो रोमांस दिखा और न कॉमेडी. फिल्म बुरी तरह नाकामयाब हुई. इस फ्लॉप के बाद आशुतोष अपनी अगली फिल्म अगले साल ही लेकर आ गए खेले हम जी जान से. यह पीरियड फिल्म थी, जो 1930 में हुए चिटगांव विद्रोह पर आधारित थी. पीरियड फिल्मों में आशुतोष कभी असफल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार वह पिट गए. फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई. यह फिल्म सिनेमा कम और डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा बन गई थी. पटकथा कमज़ोर थी. दरअसल आशुतोष ने अपने करियर के शुरुआती दौर में ही लगान जैसी फिल्म बना डाली, जिससे दर्शकों की अपेक्षाएं उनसे काफ़ी बढ़ गईं. उनकी हर रिलीज़ से दर्शकों को लगान जैसी अपेक्षा होती है. ऐसा नहीं है कि आशुतोष लगान जैसी फिल्म दोबारा नहीं बना सकते, पर इसके लिए वक़्त और मेहनत दोनों ही बहुत ज़्यादा ख़र्च करने की दरकार है. आमिर ने आशुतोष को कई बार लौटाया और स्क्रिप्ट सुधारने को कहा, जिसके चलते उन्होंने कई बार स्क्रिप्ट बदली और इसमें अच्छा ख़ासा वक़्त दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट में उतना वक़्त नहीं दिया. उनकी हर रिलीज़ के बीच का अंतराल घटता गया, जिसका असर फिल्म की गुणवत्ता पर पड़ा. यह बात भी समझ से परे है कि जिस आमिर और आशुतोष की जोड़ी ने लगान को ऑस्कर तक पहुंचाया, उन्होंने दोबारा उनके साथ काम क्यों नहीं किया? उनसे कई बार यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही सदाबहार जवाब दिया कि कहानी जब वैसी होगी तो वह आमिर के साथ दोबारा फिल्म बनाएंगे. लेकिन स्वदेस हो या जोधा अकबर, दोनों फिल्मों का लीड रोल अगर शाहरुख़ या रितिक की जगह आमिर निभाते तो कोई विशेष फ़र्क़ नहीं पड़ता. आशुतोष की पकड़ पीरियड ड्रामा पर अच्छी है, लेकिन उतनी ही ज़रूरी है बेहतर स्क्रिप्ट. खेले हम जी जान से और व्हाट्स योर राशि में संगीत भी वैसा नहीं था, जैसा जोधा अकबर या फिर लगान में था. आशुतोष को यह समझना पड़ेगा कि बड़ी फिल्में जल्दी नहीं बनतीं, वे हमेशा वक़्त और काफ़ी मेहनत की मांग करती हैं.

feedback@chauthiduniya.com

आरक्षण में दीपिका

प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण दीपिका पादुकोण के करियर के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है. इस फिल्म को लेकर दीपिका ख़ुद भी बहुत उत्साहित हैं. उनके शब्दों में, आरक्षण अपने आप में बहस का एक विषय है और वह पहली बार ऐसी फिल्म में काम कर रही हैं और पूर्वी आनंद जैसा किरदार निभा रही हैं. पूर्वी इंडिपेंडेंट है, लेकिन वह फैमिली ओरिएंटेड है. वह अपने पिता से बहुत प्यार करती है और उनका बेहद सम्मान करती है. अचानक उसके जीवन में ऐसा मोड़ आता है, जब वह अपने दोस्तों दीपक एवं सुशांत और अपने पिता के बीच उलझ जाती है. उसे समझ में नहीं आता कि वह किसका पक्ष ले. ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म आरक्षण में दीपिका भारतीय ग्रामीण परिधानों में सबका दिल जीतने आ रही हैं. किरदारों के मामले में हमेशा जोखिम उठाने वाली दीपिका आरक्षण से पहले आशुतोष गोवारिकर की फिल्म खेलें हम जी जान से में एक क्रांतिकारी महिला की भूमिका निभा चुकी हैं, लेकिन आरक्षण की पूर्वी और खेलें हम जी जान से की कल्पना की तुलना करना उचित नहीं होगा. दीपिका के अनुसार, पूर्वी में देसी टच है, खासकर भाषा के मामले में. आरक्षण की शूटिंग के दौरान भाषा उनके लिए मुश्किल साबित हुई. इसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाली हिंदी का इस्तेमाल किया गया है. पूर्वी शुद्ध हिंदी बोलती है. इसलिए हिंदी पर उन्हें काफी काम करना पड़ा. प्रकाश झा उन्हें चूल्हे-चौके तक भी खींचकर ले गए, लेकिन यह भी उनके लिए पहली बार नहीं था. दीपिका को आरक्षण में सैफ अली खान का साथ मिला है, जिनके साथ वह लव आज कल में काम कर चुकी हैं. दोनों की जोड़ी को उसमें बेहद सराहा गया था. गौरतलब है कि आरक्षण की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म कुछ लोगों की कहानी है. भोपाल में आरक्षण की शूटिंग के दौरान दीपिका फिल्मकार प्रकाश झा को प्रभावित करने में सफल हो गईं. प्रकाश झा उनकी तारीफ में कहते हैं, दीपिका बहुत समझदार हैं. वह चीजों को बहुत जल्दी समझ लेती हैं. दीपिका कहती हैं, प्रकाश झा फिल्म देखने के बाद बहुत खुश हुए. उन्होंने मुझे फोन किया और मेरे काम की तारीफ की. उन्होंने कहा कि आपने मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम किया है. प्रकाश झा के साथ काम करना उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस रहा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सोनल की वापसी

जन्नत जैसी सफल फिल्म देने के बाद कहीं गायब हो गई थीं सोनल चौहान, लेकिन उनकी एक छोटी सी झलक फिर से फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप में देखने को मिली है. ऐसे में उनके फैंस का उनसे सवाल करना जायज है कि जन्नत के बाद वह कहां गायब हो गई थीं? सोनल कहती हैं कि फिल्म जन्नत उन्हें समय से पहले ही मिल गई थी, उस वक्त उनकी पढ़ाई चल रही थी. जन्नत रिलीज होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. इसके साथ ही उन्होंने एम एफ हुसैन के बेटे की एक हिंदी फिल्म में काम किया और दो दक्षिणभाषी फिल्में भी कीं, लेकिन एम एफ हुसैन के बेटे वाली फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो पाई. यदि यह फिल्म रिलीज हो गई होती तो उन्हें इस तरह के सवालों का सामना नहीं करना पड़ता. दक्षिण की फिल्में हिंदीभाषी क्षेत्रों में नहीं आईं, इसलिए लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं चला. फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप कैसे मिली? सोनम कहती हैं कि वह पुरी जगन्नाथ के साथ हमेशा से काम करना चाहती थीं. उन्होंने दक्षिण भारत में उनकी कई फिल्में देखी हैं. इस बीच अमिताभ बच्चन का फोन आया कि क्या यह फिल्म करना चाहती हो तो वह कुछ बोल ही नहीं पाईं. अब भला अमित जी के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा. फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो हंस-हंसकर बुरा हाल हो गया. इसमें उन्होंने कालेज गोइंग गर्ल का कैरेक्टर निभाया है. वह चुलबुली हैं, अपने माता-पिता की इज्जत करती हैं और स्ट्रांग माइडेड हैं, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में आइटम नंबर नहीं किया और कम से कम दो साल तक आइटम नंबर नहीं करना चाहतीं. सोनम कहती हैं कि अमित जी के सामने वह बहुत नर्वस थीं, लेकिन उन्होंने उनका डर दूर कर दिया. वह साधारण तरीके से सबके बीच रहते हैं. हेमा जी की सुंदरता का तो जवाब नहीं था. पहले दिन तो वह उन्हें एकटक देखे जा रही थीं. तब उन्होंने यूनिट वालों से पूछा कि यह लड़की कौन है, जो मुझे घूरे जा रही है. बाद में जब सोनल उनसे मिलीं तो वह खूब हंसी. सोनल बताती हैं कि वह दो फिल्में और कर रही हैं, जिनके नाम अभी तय नहीं हुए हैं.

फिल्म प्रीव्यू

खाप

उत्तर भारत में खाप पंचायतों की मनमानी और उनके तुगलकी फैसले जल्द ही रुपहले पर्दे पर भी नज़र आएंगे. खाप नाम से एक फिल्म सितंबर महीने तक रिलीज होने वाली है. फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं अजय सिन्हा. पिछले एक साल से लगातार खाप पंचायतों के तुगलकी फरमान सुर्खियों में थे. हर ऐसे फैसलों की निंदा हो रही थी, जिनमें किसी को जान से मार देने के आदेश दिए गए थे. अजय सिन्हा ने सोचा कि क्यों न इस विषय पर एक फिल्म बनाई जाए. खाप पंचायतों पर फिल्म बनाने के लिए उन्होंने चंडीगढ़ का दौरा किया, पंचायतों पर काम कर रहे लोगों से मुलाकात करके पूरी स्थिति को समझा. मुख्य भूमिका में ओम पुरी और नवोदित अभिनेत्री युविका चौधरी हैं. फिल्म में दिखाया गया है कि खाप पंचायतें, जो खासकर हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, किस तरह एक गोत्र में विवाह का विरोध करती हैं. अजय ने कहा, हम कास्मोपोलिटन शहरों में रहते हैं, इसलिए खाप पंचायतों की क्रूरता के बारे में सोच भी नहीं सकते. फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मनाली, चंडीगढ़ और मुंबई समेत महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में की गई. फिल्म में गोविंद नामदेव, मनोज पाहवा, अनुराधा पटेल और मोहनीश बहल ने भी भूमिकाएं निभाई हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 25 जुलाई-31 जुलाई 2011

www.chauthiduniya.com

एक बार फिर चाहिए !

वामपंथ और समाजवाद

मार्क्सवादी सोच का राजनीतिक अनुवाद भारत में नहीं हो पाया. इसका कारण यह था कि वामपंथ की राजनीति में जातिगत व्यवस्था, धर्म के आधार पर व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है. वामपंथी आंदोलन धन पर भी आधारित नहीं रहा. यह मज़दूरों, मध्यम वर्ग के लोगों का चेहरा है.

अंजीव पाडेय

भारतीय लोकतंत्र में एक दौर चला था, खिचड़ी सरकारों का. खिचड़ी इसलिए क्योंकि बाद में गठबंधन शब्द अधिक गरिमामय और प्रतिष्ठित या यूं कहें टिकाऊ हो गया. तो खिचड़ी सरकारों के दौर में मीडिया के ही प्रबुद्ध वर्ग ने आवाज़ उठाई थी देश में द्विदलीय प्रणाली की. ख़ैर, द्विदलीय प्रणाली तो नहीं हो सकी लेकिन यूपीए और एनडीए नामक दो सशक्त गठबंधन ज़रूर बन गए, जिसमें तमाम छोटी पार्टियां समाहित हो गईं. इन तमाम पार्टियों के अपने निहित स्वार्थ हैं. एक का नेतृत्व कमोबेश पूरी तरह कांग्रेस और दूसरी का पूरी तरह भाजपा के हाथ में आ गया. अब हम कह सकते हैं कि अब हमारा लोकतंत्र द्विदलीय सिद्धांत की राह पर चल पड़ा है. जो किसी के साथ नहीं हैं, उनके पीछे सीबीआई है. लेकिन इसका अभी तो आगाज़ है और आगाज़ की ख़ामियां हमें अंजाम दिखा रही हैं. भले ही वामपंथ का क़िला ढह गया हो, लेकिन देश की हालिया घटनाएं अब हमें एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या फिर एक बार हमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे सशक्त समाजवादी हस्ताक्षर और ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे सशक्त वामपंथी हस्ताक्षर की आवश्यकता है. महाराष्ट्र में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है. जब समूचा देश साम्राज्यवाद की अंधी दौड़ में शामिल हो चुका है तो मुंबई का उसका केंद्र बनना स्वाभाविक है.

ख़ैर, बात महाराष्ट्र की करते हैं. थोड़ा इतिहास में जाते हैं. 1959 का वह समय सबको याद होगा जब एबी वर्धन अकेले विदर्भ से वामपंथी ख़ेमे से चुनाव जीते थे. महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों मराठवाड़ा, खानदेश, मध्य, दक्षिण और पश्चिम महाराष्ट्र में वामपंथ और समाजवाद की अच्छी ख़ासी उपस्थिति दर्ज थी. यह वह समय था जब संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने चुनाव जीता था. यह समाजवादी राज्य निर्मिति का आंदोलन था. अगर संयुक्त महाराष्ट्र समिति चुनाव जीत जाती तो परिदृश्य कुछ और ही होता. केरल के बाद महाराष्ट्र पहला राज्य होता जहां वामपंथ की सरकार होती. यह हो न सका. विदर्भ ने कांग्रेस का साथ दिया. उस कांग्रेस का साथ दिया जिसने कालांतर में विदर्भ के साथ सबसे अधिक विश्वासघात किया. जब हम आज के संयुक्त महाराष्ट्र में वामपंथ की बात करते हैं तो हम भूल रहे हैं कि इसका इतिहास सन 1960 से पहले का नहीं है. सीपी एंड बेरार से जो आठ ज़िले अलग कर महाराष्ट्र में शामिल किए गए उस समय बापू जी अणे ने कहा था कि महाराष्ट्र को तीन राज्यों में विभक्त कर दिया जाए. विदर्भ, मुंबई और महाराष्ट्र, लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र का गठन हो गया. ख़ैर, बात वामपंथ की हो रही है. सीपी एंड बेरार से अलग हुए ज़िलों में भी संयुक्त महाराष्ट्र के लिए वामपंथी और समाजवादी आंदोलन काफ़ी तीव्र हुए. कई वामपंथी, समाजवादी, विचारक, समाजसेवी नेता हुए जिन्होंने इन आंदोलनों का नेतृत्व किया. यह बात अलग रही कि 1959 के चुनाव में विदर्भ से सिर्फ़ ए.बी. वर्धन ही विजयी हो पाए. बापू जी अणे ने महाराष्ट्र के विभाजन की जो वकालत की थी, उसमें सांस्कृतिक, जातिगत विविधता की बात थी. सच भी था. विदर्भ सीपी एंड बेरार से अलग हुआ था. मराठवाड़ा निज़ाम से अलग हुआ था. पश्चिम अलग और मध्य महाराष्ट्र अलग और खानदेश अलग, मुंबई की संस्कृति तो सबसे अलग. इन सभी क्षेत्रों में वामपंथी और समाजवादी आंदोलनों का अच्छा ख़ासा प्रभाव रहा. अगर ये अलग राज्य नहीं बन पाए तो उसका कारण था, उस समय चली भाषाई आधार की लहर. यह आंदोलन किसी राजनेता ने नहीं चलाया था. इसमें समाजवादी, वामपंथी, पत्रकार, बुद्धिजीवी जैसे लोग थे. यह मास मूवमेंट था. माडखोलकर ने संयुक्त महाराष्ट्र का प्रस्ताव बेलगाम में रखा था. दुर्भाग्य की बात है कि वही बेलगाम आज भी महाराष्ट्र में नहीं है. उस समय वामपंथ को समर्थन क्यों मिला? क्योंकि यह परंपरागत सत्ताधारी वर्ग के ख़िलाफ़, श्रमिकों, दलितों, शोषितों का आंदोलन था. यह समाजवादी राज्य की निर्मिति का आंदोलन था. संयुक्त महाराष्ट्र में लगभग 50 साल कामकाजी वर्ग के बीच समाजवादी वामपंथ ही हावी रहा. 1964 में सीपीएम की स्थापना हुई. वैसे ट्रेड यूनियन आंदोलन में आईटीयूसी पहली संगठन है. मुंबई का पोर्ट ट्रस्ट, मिल मज़दूर, कोयला श्रमिकों की आवाज़ उठाने वाला यह पहली यूनियन थी. आज जो लोग आराम से टीए, डीए और अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं, उसकी बुनियाद में इन्हीं यूनियन नेताओं का बहा हुआ पसीना है.

महाराष्ट्र से वामपंथ के जुड़ाव का एक और बड़ा उदाहरण है 22 जून 1940 में नागपुर में फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना. सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र में इतनी व्यापक पृष्ठभूमि होते हुए भी वामपंथ और यहां तक कि समाजवाद भी पनप क्यों नहीं पाया? आख़िर क्या कारण था इसके पीछे. अगर संयुक्त महाराष्ट्र के उसी आंदोलन का जज्बा फिर से जगाना हो तो क्या-क्या रास्ते निकल सकते हैं. एकमत से यह विचार तो सामने ज़रूर आया कि वामपंथ और समाजवाद का एकीकरण हुए बिना आज मज़बूत हो चुकी साम्राज्यवादी ताक़तों से लड़ना मुश्किल है. एक ओर महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में एक दिन में 100 मर्सिडीज कार की बुकिंग होती है और वहीं से बामुश्किल 80 कि.मी. दूर बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं. आख़िर इस असमानता को समाप्त करने का क्या कोई विकल्प भारतीय लोकतंत्र में बचा है?

प्रगतिशील लेखक संघ के माध्यम से सामाजिक क्रांति लाने में जुटे विदर्भ साहित्य संघ के डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी का कहना है कि मार्क्सवादी सोच का राजनीतिक अनुवाद भारत में नहीं हो पाया. इसका कारण यह था कि वामपंथ की राजनीति में जातिगत व्यवस्था, धर्म के आधार पर व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है. वामपंथी आंदोलन धन पर भी आधारित नहीं रहा. यह मज़दूरों, मध्यम वर्ग के लोगों का चेहरा है. महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है. संतों ने भी सामाजिक समानता और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात कही. संत ज्ञानेश्वर ने स्थापित मान्यताओं को बदला. संतों ने समसामयिक सामाजिक चेतना का आंदोलन कर सामाजिक समता के विचार समाज में स्थापित किए. इसी कारण यहां कार्ल मार्क्स को समझने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई. आज भी महाराष्ट्र में शेतकरी कामगार पक्ष अस्तित्व में है. यह कभी वामपंथ का बड़ा हिस्सा हुआ करता था. अब क्लासिकल मार्क्सवाद से ऊपर उठकर साइंटिफिक सोशलिज्म की शिक्षा युवा पीढ़ी को दी जानी चाहिए. आज हावी होती जा रही साम्राज्यवादी राजनीति से निजात पाना ज़रूरी हो गया है. प्रमुख मार्क्सवादी विचारक रघुवीर सिंह खन्ना का मानना है कि सत्ताधारियों ने सदियों पहले से ही हमारी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को छिन्न-भिन्न करने के लिए पंडों को आगे कर दिया था. महाभारत, रामायण और संत परंपरा में कहीं भी सामाजिक विषमता की बात नहीं की गई. पंडों ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश किया. मार्क्स को रशिया या चीन की तरह ही अपनाना भारत के लिए कहां तक उचित है. मार्क्स ने भी कहा था कि देश की संस्कृति के अनुरूप जो प्रासंगिक हो, उसे ही अपनाया जाना चाहिए. भगत सिंह को इतने वर्षों बाद माना गया कि वे वामपंथी थे. हमें अपनी सोच में सुधार करना होगा. वामपंथ में हम कामरेड शब्द का इस्तेमाल करते हैं. इसकी जगह अगर भाई शब्द का इस्तेमाल करें तो क्या फ़र्क़ पड़ेगा. वैसे भी कामरेड फ्रेंच शब्द है. माओ ने चीन की संस्कृति को लेकर चीन में परिवर्तन की बात कही. हम भी महाराष्ट्र में संत परंपरा को अपना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही किया जो वामपंथ करना चाहता है. लोहिया अध्ययन केंद्र के सचिव और प्रमुख समाजवादी विचारक हरीश अड्यालकर का मानना है कि समाजवाद सीधे लोगों से बात करता है. जयप्रकाश नारायण भी मार्क्सवादी ही थे. जब वह पढ़ाई पूरी कर भारत पहुंचे और महात्मा गांधी के संपर्क में आए तो उन्हें गांधी का मार्ग ज़्यादा उपयुक्त लगा. उन्होंने महसूस किया कि यहां के लोगों का जीवन अलग क़िस्म का है. यहां लोग जातियों, उपजातियों में बंटे हुए हैं. बता दें कि अड्यालकर कई वर्षों से ट्रेड यूनियन आंदोलन भी जुड़े हुए हैं. उनका कहना है कि यहां सिर्फ़ मज़दूरों से क्रांति नहीं होगी. सभी पार्टियों को एक करने का काम लोहिया ने किया. अब वामपंथ को समाजवाद से जुड़ना होगा. तभी दो गठबंधन में होते जा रहे राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण का कोई हल निकल पाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

1959 का वह समय सबको याद होगा जब एबी वर्धन अकेले विदर्भ से वामपंथी ख़ेमे से चुनाव जीते थे. महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों मराठवाड़ा, खानदेश, मध्य, दक्षिण और पश्चिम महाराष्ट्र में वामपंथ और समाजवाद की अच्छी ख़ासी उपस्थिति दर्ज थी. यह वह समय था जब संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने चुनाव जीता था. यह समाजवादी राज्य निर्मिति का आंदोलन था. अगर संयुक्त महाराष्ट्र समिति चुनाव जीत जाती तो परिदृश्य कुछ और ही होता. केरल के बाद महाराष्ट्र पहला राज्य होता जहां वामपंथ की सरकार होती. यह हो न सका.

घटता मराठी मोह या कुछ और

महाराष्ट्र सरकार की अंग्रेजी परस्त शिक्षा नीति का असर मराठी पुस्तकों के प्रकाशन उद्योग पर भी तेज़ी से पड़ रहा है. पिछले चार-पांच सालों में मराठी पुस्तकों के प्रकाशन में तेज़ी से कमी दर्ज की गई है. अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने के बढ़ते क्रेज और पांचवीं से सेमी अंग्रेजी पढ़ाए जाने की राज्य सरकार की नीति से मराठी पुस्तकों का प्रकाशन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. तीन-चार सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो प्रकाशित मराठी की किताबों की संख्या में क़रीब एक करोड़ की कमी आई है. वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी की पुस्तकों के प्रकाशन में 20 लाख से भी अधिक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. यह तथ्य उजागर हुआ है कि कक्षा एक से 12वीं तक की पुस्तकों की छपाई, वितरण और बिक्री करने वाली राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित व अभ्यास क्रम संशोधन मंडल (बाल भारती) द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के आंकड़ों से. यह परिदृश्य महाराष्ट्र में मराठी भाषा के प्रति बढ़ती अरुचि को दर्शाता है या फिर इसके पीछे कुछ और रहस्य छुपा हुआ है. राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन व अभ्यास क्रम संशोधन मंडल के आंकड़ों पर नज़र डाले तों इसकी हक़ीक़त का पता चलता है. बाल भारती के व्यवस्थापक अशोक गायकवाड़ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक़ 2009-10 में कक्षा एक से बारहवीं तक मराठी माध्यम की 9 करोड़ 8 लाख पुस्तकें प्रकाशित की थीं. वर्ष 2010-11 में यह आंकड़ा घट कर 8 करोड़ 16 लाख पर आ गया यानी एक वर्ष में एक करोड़ मराठी पुस्तकों की छपाई मंडल को कम करनी पड़ी. 2011-12 में इस आंकड़े में और कमी दर्ज की गई. 2011-12 में मंडल ने मराठी माध्यम की 8 करोड़ 21 लाख पुस्तकें प्रकाशित की गईं. 2011-12 में हुई बढ़ोत्तरी के विषय में गायकवाड़ ने बताया कि 2009-10 की छपाई की गई पुस्तकें बचीं. जिनकी सप्लाई 2011 में की गई जिसके कारण कम छपाई की गई. जैसे-जैसे मराठी की पुस्तकों की छपाई में कमी आती जा रही है, वैसे-वैसे अंग्रजी माध्यमों की पुस्तकों की मांग बढ़ रही है, जिसके चलते अंग्रेजी की पुस्तकों के प्रकाशन में बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है. बाल भारती ने 2009-10 में जहां 2 करोड़ 21 लाख अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों का प्रकाशन किया था, वहीं वर्ष 2010-11 के दरम्यान 2 करोड़ 46 लाख और 2011-12 में अब तक 2 करोड़ 43 लाख पुस्तकों की छपाई हो चुकी है. यदि मांग बढ़ती है तो और पुस्तकों की छपाई की जाएगी.

मराठी पुस्तकों के प्रकाशन के संबंध में आ रही कमी के बारे में व्यवस्थापक गायकवाड़ का कहना है कि आज सेमी अंग्रेजी की सरकारी नीति भी इसका एक कारण है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है. मुख्य वजह यह है कि आज हर अभिभावक-पालक अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर व अन्य उच्च डिग्री की शिक्षा दिलाना चाहता है. इसलिए उसकी इच्छा होती है कि उसका बच्चा अंग्रेजी में प्रवीण हो, ताकि उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने व नौकरी करने में किसी तरह की दिक्क़त न हो, इसलिए वह अंग्रेजी मीडियम का चयन करता है. उन्होंने यह भी बताया कि बाल भारती के पास सिर्फ़ प्रिंटिंग का काम है और हर वर्ष की मांग के अनुसार हमें मराठी-अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों का प्रकाशन करना पड़ता है. सेमी अंग्रेजी कोर्स होने के कारण विज्ञान, गणित की पुस्तकें अंग्रेजी में ही आती हैं. इसके चलते अंग्रेजी मीडियम की पुस्तकों की मांग अधिक होती है. हर वर्ष क़रीब 10 प्रतिशत की दर से अंग्रेजी पुस्तकों की मांग बढ़ रही है. इस संबंध में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कदम का कहना था कि स्कूल खुलने के साथ ही पूरे राज्य से विद्यार्थियों की प्राप्त संख्या के आधार पर मराठी-अंग्रेजी पुस्तकों का प्रकाशन करना होता है. स्वाभाविक तौर पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों व विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के साथ ही अंग्रेजी की पुस्तकों की मांग भी बढ़ रही है. वर्तमान में अंग्रेजी का क्रेज है. अंग्रेजी को जॉब की भाषा समझा जाता है. सफल व्यवसाय संचालन के लिए भी अंग्रेजी आना ज़रूरी समझा जाने लगा है. इन परिस्थितियों में आज के अभिभावकों का अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के प्रति झुकाव होना स्वाभाविक है. इसलिए यदि राज्य में अंग्रेजी की पुस्तकों की मांग बढ़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है. हर पालक चाहता है कि उसका बेटा-बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त कर योग्य बने और कोई उच्च पद प्राप्त करे. लिहाज़ा मराठी की पुस्तकों के प्रकाशन में कमी आ रही है. हालांकि स्कूली पुस्तकों को छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र में मराठी पुस्तकों की अभी भी मांग है, पर युवा पीढ़ी का अंग्रेजी मोह तेज़ी से बढ़ रहा है और मराठी के प्रति घट रहा है. यह सब शिक्षा व बाज़ार के वैश्वीकरण के कारण हो रहा है. चूंकि आज कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है इसलिए हर कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है. इसका असर पुस्तकों के प्रकाशन पर भी पड़ रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

गडबड़ी की आशंका

बाल भारती द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009-10 और 2010-11 के बीच मराठी पुस्तकों के प्रकाशन में क़रीब एक करोड़ पुस्तकों की कमी आई. दूसरी ओर अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन में मात्र 20-25 लाख पुस्तकों की वृद्धि हुई. मराठी व अंग्रेजी की कमी व बढ़ोतरी के आंकड़ों के अनुपात में क़रीब 70-75 लाख का फ़र्क़ आ रहा है. इन आंकड़ों में तालमेल न बैठने से कहीं न कहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ होने का संदेह होता है. बाल भारती को इसकी जांच करनी चाहिए कि यह गड़बड़ी उसके अंदर या बाहर. कहीं कोई अवैध रूप से बाल भारती की टेस्ट बुक का प्रकाशन तो नहीं कर रहा है? पूछताछ करने पर इस संबंध में संबंधित अधिकारी भी जवाब देने में असमर्थ रहे.

तीन-चार सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो प्रकाशित मराठी की किताबों की संख्या में क़रीब एक करोड़ की कमी आई है. वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी की पुस्तकों के प्रकाशन में 20 लाख से भी अधिक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है.

पीरपांचाल का सबसे ऊंचा ग्लेशियर पार किया

महाराष्ट्र को शर्मिला पर गर्व है

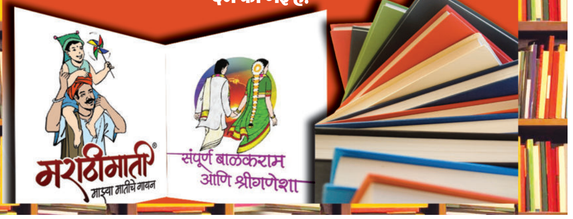

पर्वतारोहण की बात शुरू होते ही हिमालय के ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और उनकी चोटियों के दृश्य आंखों के सामने तैरने लगते हैं. विशेषकर विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ते पर्वतारोहियों की घटनाएं मन को रोमांचित करने लगती हैं और मन कह उठता है कि काश, हम भी हिमालय की गोद में बसे पहाड़ों पर चढ़ने के रोमांच का अनुभव ले पाते. पर्वतारोहण आज भारत में पर्यटन, खेल और एडवेंचर का रूप ले चुका है. हालांकि पर्वतारोहण में जोखिम होता है, पर इसकी ओर युवा वर्ग का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है. इसमें पुरुषों के साथ ही महिला पर्वतारोहियों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है. पर्वतारोहियों में एवरेस्ट की अब हिमालय की अनछुई चोटियों को छूने का रुझान अधिक देखा जा रहा है, जिनके लिए अधिक जोखिम व रोमांच से भरे रास्तों पर चलना पड़ता है. शर्मिला चटर्जी ऐसी ही युवा पर्वतारोही हैं, जो पर्वतारोहण के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहती हैं. कुछ नए मुक़ाम हासिल करना चाहती हैं. इसी वर्ष 10 जून को शर्मिला ने पीरपंचाल का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कुग्ती पास पार किया. इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5040 मीटर है. यहां से मणि महेश कैलाश पर्वत का शिखर भी दिखता है. शर्मिला इस ऊंचाई पर पहुंचने वाली महाराष्ट्र की पहली महिला पर्वतारोही हैं. इस अभियान से लौटते ही उन्होंने चौथी दुनिया से अपने अनुभव बांटे. शर्मिला चटर्जी बताती हैं कि उनका पर्वतारोहण अभियान का शुभारंभ हिमाचल के थारमोर चंबा गांव से हुआ. चंबा का मार्ग सबसे ख़तरनाक है.

चंबा से हमने दुर्गम रास्तों से चलना शुरू किया और हडसर हमारा पहला डेस्टीनेसन था. चंबा का आख़िरी गांव कुग्ती है जहां गद्धी ट्राइब के लोग रहते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय बकरी और भेड़ पालना है और यही उनकी रोज़ी-रोटी का मुख्य साधन भी है. यहां के निवासी गर्मी का मौसम शुरू होते ही जोखिम भरे रास्तों को पार करते हुए अपनी भेड़-बकरियों को लेकर स्फीति घाटी में चले जाते हैं. अपने पशुओं से औलाद की तरह प्यार करते हैं. स्फीति वैली में इनके पशुओं को अच्छी घास उपलब्ध हो जाती है. एलियस हमारा अगला कैंप था. यह ग्लेशियर है. यहां का तापमान -17 डिग्री सेल्सियस था. इस ग्लैशियर पर 16 घंटे चलना पड़ा. यहां पर वजीर जी यानी भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय और मोराली माता का मंदिर हैं. आगे का सफ़र शुरू करने से पहले वजीरजी से पूजा-अर्चना करके अनुमति मांगनी पड़ती है.

चार धाम का भाग होने से वहां से सरकार को अच्छा लाभ भी हो सकता है लेकिन सड़कों की हालत खराब हैं. कई सेक्टर में अच्छे होटल भी नहीं हैं. निजी-सार्वजनिक आधार पर यहां होटल खोले जाने चाहिए. माउंटेनियर स्कूल से रोजगार की अच्छी संभावनाएं बन जाती हैं.

ऐसी मान्यता है कि वजीरजी की अनुमति के बिना जो भी आगे जाता है तो संकटों से घिर जाता है. उसे अपना अभियान बीच मे अधूरा छोड़ कर लौटना पड़ता है. चार दिन हर सुबह तड़के रात 3.30 बजे से सैकड़ों भेड़-बकरियों के साथ हमें आगे के लिए निकलना पड़ता था. शाम को छह बजे आराम करते थे. इस दरम्यान वर्षा भी शुरू हो गई थी. दिन को 10 बजते ही जब सूर्य निकलता था, तो भूस्खलन का ख़तरा भी बढ़ जाता था और काफ़ी धीरे-धीरे संभल कर आगे बढ़ना पड़ता था. पानी न मिलने पर वहां की बर्फ़ खाकर प्यास बुझानी पड़ती थी. इन सात दिनों के सफ़र में पांच दिन बर्फ़ में गुज़ारने पड़े. स्फीति वैली में ज़रूर काफ़ी समृद्धि दिखी. यहां बड़े-बड़े मकान हैं. यहां का आलू और राजमा प्रसिद्ध है. लेह हाईवे के कारण यहां संपन्नता नज़र आती है. यह सफ़र 18 जून को मनाली में समाप्त हुआ.

बारिश का मौसम छोड़कर शेष 8 माह उत्तराखंड की वादियों में बिताने वाली शर्मिला कहती हैं कि यह राज्य उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वहां शांति है. वहां की आबोहवा शुद्ध है. वहां गंगा का उद्गम गोमुख है, जिसकी प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है. वहां बसे लोग ईमानदार हैं, उनकी मानसिकता अच्छी है. बच्चों का रोज़गार मुख्यतः पर्यटन पर आधारित है. चार धाम का भाग होने से वहां से सरकार को अच्छा लाभ भी हो सकता है, लेकिन सड़कों की हालत ख़राब है. कई सेक्टर में अच्छे होटल भी नहीं हैं. निजी-सार्वजनिक आधार पर यहां होटल खोले जाने चाहिए. माउंटेनियर स्कूल से रोज़गार की अच्छी संभावनाएं बन जाती हैं. एकल पर्वतारोही के रूप में शर्मिला ने 1983 में अभियान की शुरुआत की. 1987 में उत्तर व पश्चिम सिक्किम, 2006 में गोमुख से तपोवन, नंदनवन, भागीरथी 1, 2, 3 और 2008 में मणिमहेश का पर्वतारोहण उनकी अब तक की सफलताओं में शुमार रहा है. एक ख़तरनाक क़िस्सा बताना वह नहीं भूलती हैं. कहती हैं मणिमहेश पर्वतारोहण के दौरान घोड़े का धक्का लग जाने से वह खाई में गिर गईं, लेकिन अपने हाथों के सहारे झूलती रहीं. घोड़े वाले ने तुरंत उन्हें बचाया. आज भी वह गहरी खाई याद आती है तो मन सिहर उठता है. वह चाहती हैं कि महाराष्ट्र सहित पूरे देश के लोग साल भर का कुछ समय निकाल कर हिमालय की तराई में बिताएं. इससे पूरा साल वे ऊर्जा से भरे रहेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

रामटेक नगर परिषद

बिना टैंकर अबाधित जलापूर्ति

राज्य के किसी भी शहर में गर्मी के दिनों में बिना टैंकर के संपूर्ण रूप से जलापूर्ति की बात गले के नीचे नहीं उतरती. मुंबई हो या नागपुर, औरंगाबाद हो या अमरावती, हर जगह गर्मी के दिनों में जलापूर्ति के लिए टैंकर का सहारा लेना ही पड़ता है. भले ही वह कुछ बस्तियों या वार्डों तक ही सीमित क्यों न हो. रामटेक नगर पालिका में भी ऐसा ही होता था. हर साल टैंकर से पेयजल की आपूर्ति में लाखों रुपये ख़र्च कर दिए जाते थे. ऐसे में ऐन गर्मी के पहले फरवरी में यहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद की ज़िम्मेदारी माधुरी मडावी ने संभाली और रामटेक में अपने कार्यकाल का पहला गर्मी का मौसम ही बिना टैंकर के जलापूर्ति कर दिखा दिया. भौगोलिक क्षेत्र वही, जलापूर्ति योजना वही, जनसंख्या में बढ़ोत्तरी. फिर कौन सा चमत्कार हुआ कि प्रत्येक नागरिक को पानी भी मिलता रहा और टैंकर भी नहीं लगाए गए. पिछले 5 वर्षों से रामटेक नगरपालिका में शुरू टैंकर के नाम पर शासकीय धनराशी के दुरुपयोग के खेल को बंद कर दिखा दिया. साथ ही पूरे राज्य की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के लिए एक सबक़ भी उन्होंने दिया. लगभग 40 हज़ार की आबादी वाला छोटा सा शहर है रामटेक. यह नागपुर ज़िले में है. कहने को यह छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक ख्याति बड़ी है. कहते हैं कि कालिदास ने यहां अपनी कालजयी रचना मेघदूतम की रचना की थी. पूर्व प्रधानमंत्री स्व. नरसिंह राव का यह पसंदीदा संसदीय क्षेत्र था. प्रधानमंत्री बनने के पूर्व नरसिंह राव इसी क्षेत्र से चुनाव जीत कर दिल्ली पहुंचे थे. धार्मिकता से ओत-प्रोत रामटेक समूचे अंचल का जाना-माना पर्यटन स्थल भी है. पिछले पांच वर्षों तक इसी नगरपालिका के अंतर्गत गर्मी के दिनों में पेयजल की टैंकरों से आपूर्ति के लिए 23 लाख 86 हज़ार 608 रुपये ख़र्च किए जा चुके थे. वर्ष 2006-07 में 5,09,258 रुपये, 2007-2008 में 7,24,200 रुपये, 2008-09 में 1,58,400 रुपये, 2009-10 में 4,14,590 रुपये और 2010-11 फरवरी के पूर्व में 6,80,160 रुपये टैंकरो से जलापूर्ति पर ख़र्च हुए. पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष के गर्मी के मौसम में जनवरी माह से पानी के लिए हाहाकार मच जाता था. संबंधित वॉर्ड के पार्षदों द्वारा नगरपालिका पर नागरिकों का मोर्चा ले जाकर पर्याप्त जलापूर्ति की मांग की जाती थी. सूत्रों के अनुसार पार्षदों द्वारा ऐसा इसलिए किया जाता था जिससे टैंकर लगाए जाएं. जनवरी माह से लेकर मानसून की बरसात होने तक टैंकर दौड़ने शुरू हो जाते थे. प्रतिदिन 80 से लेकर 100 टैंकरों से जलापूर्ति की जाती थी. इसी वर्ष 2 फरवरी को माधुरी मडावी ने रामटेक नगरपालिका के मुख्याधिकारी का पदभार ग्रहण किया तो कुछ पार्षदों ने पानी की समस्या का उल्लेख करते हुए उनके सामने टैंकर द्वारा जलापूर्ति करने का सुझाव रखा. मुख्याधिकारी ने पानी समस्या अध्ययन और सर्वेक्षण के लिए पार्षदों से समय मांगा. सुबह-शाम शहर के विभिन्न भागों में घूमकर अध्ययन और सर्वेक्षण के बाद मडावी इस निष्कर्ष पर पहुंचीं कि जलापूर्ति की समस्या किसी भी वर्ष में नहीं थी. उन्होंने टैंकरों से जलापूर्ति करने से मना कर दिया. इतना ही नहीं जलापूर्ति विभाग के कर्मचारियों की बार-बार बैठक बुलाकर योजना की कमियों को दूर कर अधिक सहज बनाने के निर्देश दिए. फरवरी से लेकर मई तक टैंकर से जलापूर्ति न किए जाने के कारण कुछ पार्षदों ने मुख्याधिकारी मडावी की आलोचना भी की, किंतु वह अपने निर्णय पर अडिग रहीं. नगरपालिका की तिजोरी से टैंकर के नाम पर गत 5 वर्षों में पानी की तरह ख़र्च की गई शासकीय धनराशि को इस वर्ष ख़र्च नहीं होने दिया और दिखा दिया कि टैंकरों द्वारा जलापूर्ति किए जाने के नाम पर अभी तक अनावश्यक रूप से शासकीय धन की बर्बादी हुई. उन्होंने टैंकर के घालमेल को जनता के सामने लाकर लगभग 6,80,160 रुपए की बचत इस बीते गर्मी के मौसम में की.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष गर्मी के मौसम में जनवरी माह से पानी के लिए हाहाकार मच जाता था. संबंधित वॉर्ड के पार्षदों द्वारा नगरपालिका पर नागरिकों का मोर्चा ले जाकर पर्याप्त जलापूर्ति की मांग की जाती थी.

पार्षद से मुख्याधिकारी

माधुरी मडावी

माधुरी मडावी राज्य के सबसे पिछले और नक्सलग्रस्त इलाक़े गड़चिरोली की रहने वाली हैं. सन 2008 में महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पहले वह गड़चिरोली नगरपालिका में पार्षद थीं. कई साल तक नागपुर विश्वविद्यालय की सीनेट सदस्य भी रह चुकी हैं. गड़चिरोली में रहते हुए मडावी उस समय सुर्ख़ियों में आईं थीं जब उन्होंने महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान नागपुर में नक्सली मुठभेड़ में मारे गए पुलिस कर्मियों के परिजनों की दयनीय व्यथा का मामला उठाया था. इसके लिए उन्होंने लगभग दो हफ्ते अनशन भी किया था.

ये क्या हो रहा है...

आया और गया, बाकी कुछ न रहा

इसे नागपुर का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कि यहां विकास कार्यों को लेकर ज़ोर-शोर से पोंगा बजाया जाता है. नागपुर का औद्योगिक-आर्थिक विकास होगा. विदर्भ के लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा. उपराजधानी वासियों के भाग्य खुल जाएंगे. नागपुर सहित पूरे विदर्भ के चहुंमुखी विकास के दरवाज़े खुल जाएंगे. हर नए प्रोजेक्ट के आने पर चहुंओर ये बातें सुनाई देती हैं. कभी किसी नेता के मुख से तो कभी किसी वरिष्ठ अधिकारी के मुख से. सभी प्रोजेक्ट के आने की श्रेय लूटने की होड़ में शामिल हो जाते हैं. इस रस्साकशी में निकला परिणाम खोदा पहाड़,

निकली चुहिया की कहावत को चरितार्थ करता है. जब बूटीबोरी एमआईडीसी प्रोजेक्ट आया था, तब भी कुछ ऐसी ही बातें हुईं जो अब मिहान के आने पर हो रही हैं. तब ख़ूब हल्ला मचाया गया था कि एशिया का सबसे बड़ा पंचतारांकित औद्योगिक क्षेत्र होने का गौरव उपराजधानी और विदर्भ को मिला. इससे विदर्भ से बेरोज़गारी दूर हो जाएगी. मगर आज एशिया के फाइव स्टार इंडस्ट्रियल क्षेत्र के सभी स्टार ग़ायब हो गए हैं और नाम का बूटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र रह गया है. इक्का-दुक्का औद्योगिक इकाइयां ही बची रह गई हैं. पंचतारांकित के पांचों तारों को एक-एक कर टूट-टूट कर आसमान से ज़मीन पर गिरते नागपुर वालों ने देखा है. मिहान के नाम पर आने वाले प्रोजेक्ट के तहत भी ऐसा ही दुर्भाग्य जुड़ा नज़र आ रहा है. पहले वायुसेना का गरूड़ आया और कुछ दिन नागपुर के विमानतल पर विश्राम कर उड़ गया. फिर बड़ी गर्जना के साथ वायुसेना की 44-स्क्वाड्रन गजराज आया और वह भी अब उड़ कर चंडीगढ़ की ओर रवाना हो गया. ऐसा ही वाक़िया नागपुर को टाइगर कैपिटल बनाने का मामला है. टाइगर कैपिटल धीरे-धीरे भोपाल-जबलपुर की ओर खिसक रहा है. अब वायुसेना में शामिल सी-130 हर्क्युलस सुपर जेट आने की गर्जना सुनाई दे रही है. वह भी कुछ दिन विश्राम कर गरजते हुए कब उड़ जाएगा, यह तो भविष्य ही बताएगा. पर आख़िर यह हो क्या रहा है? उपराजधानी के साथ आया और गया, बाक़ी कुछ न बचा का खेल क्यों खेला जा रहा है. आज मिहान भी बूटीबोरी की राह पर अग्रसर होता नज़र आ रहा है. मिहान के कर्ताधर्ता कहते हैं कि फ़लां-फ़लां कंपनी ने दो-तीन माह में अपना काम शुरू करने का वादा किया है. कहां गए वे तमाम लीडर जिन्होंने मिहान, कार्गोहब के आने पर विदर्भ की युवा आंखों में उज्जल भविष्य के सपनों को जगाया था. आईटी के क्षेत्र में नागपुर को पुणे, बंगलुरू की तुलना में खड़ा कर दिया था. ख़ुशहाल विदर्भ के ख्वाब दिखाए थे. युवा हाथों को रोज़गार अब तक क्यों नहीं मिला? उपराजधानी की तक़दीर बदलने में मिहान कहां अटक कर रह गया है? जिन किसानों की ज़मीन मिहान के नाम पर अधिग्रहीत की गई वे क्यों ठगा-सा महसूस कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल आहिस्ता-आहिस्ता विदर्भ के मानस पटल पर उभरने लगे हैं, क्योंकि मिहान भी बूटीबोरी की तरह अब तक सफ़ेद हाथी ही साबित हुआ है. इतना ज़रूर हुआ है कि मिहान के क़सीदे पढ़कर नेताओं ने वाहवाही लूटी है और वर्धा रोड में ज़मीन की ख़रीद-बिक्री से करोड़ों कमाए हैं. आज मिहान के आवरण से घोटालों की बेल निकलने लगी है, चाहे फिर ज़मीन डी-नोटीफिकेशन का मामला हो या किसानों की ज़मीन अधिग्रहीत करने का या किसानों से किए गए वादे पूरे करने का. वर्तमान स्थिति में कोई नेता व अधिकारी यह बताने को तैयार नहीं है कि मिहान प्रोजेक्ट कब तक साकार होगा? उससे नागपुर सहित विदर्भ को कब फ़ायदा होगा? सवाल अंतहीन हैं, पर जवाब न सरकार के पास है और विदर्भ के बड़बोले नेताओं के पास है. एक तरह से महाराष्ट्र की उपराजधानी को मज़ाक़ सा बना कर रख दिया है राजनीतिक कलाबाज़ों ने. यहां जो भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है उसे कोई और ले जाता है और विदर्भ के राजनेता अपने अहम में दूर-दूर खड़े एक-दूसरे को हाथ मलते देख मुस्कराते रहते हैं. आख़िर उनका जाता क्या है? जाता है विदर्भ का सौभाग्य, क्योंकि बड़े-बड़े प्रोजक्ट नागपुर के नाम पर बनते हैं उसकी सामरिक महत्ता को ध्यान में रखकर, पर दुर्भाग्यवश एक भी प्रोजेक्ट यहां ठहर नहीं सका. एक एमआईडीसी बूटीबोरी ने थोड़ा विश्राम भी किया तो उसका क्या हश्र कर दिया गया. यह विदर्भ व नागपुर के राजनीतिक नेतृत्व की अकुशलता-असफलता की कहानी बताता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे को उनके सुतारवाड़ी स्थित निवास स्थान में जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते पत्रकार भावे.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के जनता दरबार में मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़, पुलिस महासंचालक अजीत पारसनीस.

गंगाप्रसाद मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक माय ड्रीम चाइल्ड का विमोचन करते हुए महापौर अर्चना डेहनकर, वनराई के विश्वस्त गिरीश गांधी, एस. एन. विनो, दत्ता मेघे डींड यूनिवर्सिटी के उपकुलपति वेदप्रकाश मिश्रा आदि.

शतरंज विश्व चैम्पियन विश्वनथान आनंद नागपुर में एनआईआईटी के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए.

नागपुर से प्रकाशित साप्ताहिक जीरो माइल का महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा संकुल में लोकार्पण करते हुए रमेश बंग, विधायक देवेंद्र फडणवीस, गिरीश गांधी, बनवारीलाल पुरोहित, संपादक आनंद शर्मा व अन्य.

नागपुर स्थित जी कुमार आरोग्य धाम में आयोजित संधिवात मधुमेह रोग निदान शिविर में महिला मरीज की जांच करते चिकित्सक.

नागपुर के डॉ. आंबेडकर हवाई अड्डे पर मिले जिंदा कारतूस दिखाते हुए पुलिस अधिकारी.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

अल्पसंख्यक समुदाय को आकर्षित करने का इससे अच्छा अवसर कांग्रेस को फ़िलहाल तो मिलना नहीं था. इसलिए आलाकमान ने देशमुख के इस प्रस्ताव को लपक लिया.

त्याग किसी का फल मिला किसी को

चव्हाण ने पार्टी आलाकमान के दरबार में हाज़िरी लगाकर मैडम (सोनिया गांधी) से संजय दत्त को राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाने की सिफ़ारिश उनके त्याग का उल्लेख करते हुए की थी, लेकिन आलाकमान का मन नहीं पसीजा. उनसे कहा गया कि राज्य के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल, रोहीदास पाटिल व अनंत गाडगिल भी राज्यसभा में जाने के इच्छुक हैं. इन्हें नाराज़ कैसे किया जा सकता है. मुख्यमंत्री आलाकमान के दरबार से मायूस होकर लौट आए.

राजनीति में कब किसकी बलि ले ली जाए और किसे बिना त्याग के फल खाने को मिल जाए यह राजनीतिक दलों के आलाकमान के अलावा कोई नहीं बता सकता है. राज्य में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के चुनाव के लिए विधान परिषद के सदस्य संजय दत्त से इस्तीफ़ा दिलाया गया. उन्हें आश्वस्त किया गया था कि मुख्यमंत्री चव्हाण द्वारा रिक्त की गई राज्यसभा की जगह को उन्हीं का निर्वाचन कर भरा जाएगा. यह आश्वासन स्वयं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दिया था, लेकिन जब चुनाव का समय आया तो राज्य के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के नाम दौड़ पर सबसे आगे और संजय दत्त का नाम सबसे पीछे दिखा. परंतु राज्य के कांग्रेसी तब आश्चर्य में पड़ गए जब अचानक प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हुसैन दलवई के नाम पर आलाकमान ने मोहर लगा कर राज्यसभा के लिए पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया. अब कांग्रेसी लीडरों में कानाफूसी शुरू हो गई है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का वज़न कम हो गया है और उनके प्रतिद्वंद्वी विलासराव देशमुख का दबदबा बढ़ गया है, परंतु ऐसा नहीं है. 12 जुलाई को हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में विलासराव देशमुख से ग्रामीण विकास मंत्रालय छीन कर कम महत्व के विज्ञान तकनीकी और भू-विज्ञान विभाग सौंपकर उनके दबदबे को भी कम कर दिया गया है. आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि दलवई का नाम दौड़ में कहीं नहीं था. अब संजय दत्त उस घड़ी को लेकर पछता रहे हैं जिस घड़ी उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपनी विधान परिषद की सीट छोड़ी. अब उनके दर्द को सुनने-समझने वाला कोई नहीं मिल रहा है. ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री चव्हाण उनके त्याग को भूल गए हैं. चव्हाण ने पार्टी आलाकमान के दरबार में हाज़िरी लगाकर मैडम (सोनिया गांधी) से संजय दत्त को राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाने की सिफ़ारिश उनके त्याग का उल्लेख करते हुए की थी, लेकिन आलाकमान का मन नहीं पसीजा. उनसे कहा गया कि राज्य के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल, रोहीदास पाटिल व अनंत गाडगिल भी राज्यसभा में जाने के इच्छुक हैं. इन्हें नाराज़ कैसे किया जा सकता है. मुख्यमंत्री आलाकमान के दरबार से मायूस होकर लौट आए.

आलाकमान इस दरम्यान राज्य के केंद्र में बैठे अन्य नेताओं से भी राज्यसभा के लिए प्रत्याशी का नाम सुझाने को कहा और यहीं सब गड़बड़ हो गई. पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय विज्ञान तकनीकी मंत्री विलासराव देशमुख ने आलाकमान के सामने राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के नेतृत्व को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया. अल्पसंख्यक समुदाय से सबसे पहले नागपुर के अनीस अहमद का नाम सामने आया जिस पर देशमुख ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने हुसैन दलवई का नाम आलाकमान के आगे कर दिया. अब राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के मतों को अपनी-अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सत्तारूढ़ लोकशाही अघाड़ी (गठबंधन) के दोनों साझीदार यानी कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस में रणनीतियां रची जा रही हों तो इस प्रस्ताव को मानने के अलावा आलाकमान के सामने कुछ बचा ही नहीं था. अल्पसंख्यक समुदाय को आकर्षित करने का इससे अच्छा अवसर कांग्रेस को फ़िलहाल तो मिलना नहीं था. इसलिए आलाकमान ने देशमुख के इस प्रस्ताव को लपक लिया. ऊपर से ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी अपनी सहमति दे दी. मगर यहां विलासराव देशमुख ने एक तीर से तीन निशाने साधने में सफल हो गए. पहले तो आदर्श सोसायटी मामले में घिरे देशमुख ने हुसैन दलवई को राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनवा कर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को यह जता दिया कि दिल्ली में अब उनका दबदबा है. भले वे कितने ही विवादों में घिरे हों पर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. दूसरा निशाना उन्होंने शिवराज पाटिल को बनाया और उनका दिल्ली में पुनर्वास होने से रोक दिया. उन्हें संकेत दिया कि वे अभी राजस्थान के राजभवन में राजनीतिक वनवास में ही रहें. तीसरा निशाना बने राज्य के पूर्व मंत्री अनीस अहमद. अनीस अहमद ने राज्य में विलासराव देशमुख के मंत्रिमंडल में रहते हुए उनके परिवार के ट्रस्ट द्वारा वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन हड़पने का मुद्दा उठाया था. तब से देशमुख अनीस अहमद से खार खाए बैठे थे और अब जाकर उन्हें हिसाब बराबर करने का मौक़ा मिला. साथ ही अनीस के मुक़ाबले राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के सामने एक वैकल्पिक नेतृत्व भी खड़ा कर दिया.

अल्पसंख्यक समुदाय के मतों को लेकर चिंतित आलाकमान के सामने मुख्यमंत्री चव्हाण द्वारा पेश पूर्व विधायक की दावेदारी रंग न ला सकी. अब संजय दत्त न इधर के हैं, न उधर के. राज्यसभा जाने के लालच में विधान परिषद की सीट छोड़ी, पर आज वे न विधानमंडल में हैं, न राज्यसभा जा पाए. मुख्यमंत्री भी निराश होकर आलाकमान के द्वार से निराश होकर लौट आए. अब उन्हें समझ में आ रहा है कि राज्य की राजनीति कितनी विकट है.

आलाकमान ने उनसे स्पष्ट कहा कि संजय दत्त का पुनर्वास राज्य विधान परिषद में ही समय आने पर किया जाए. फ़िलहाल संजय दत्त के लिए केंद्र में कोई जगह ख़ाली नहीं है. यही कारण है कि राज्य के राजनीतिक विश्लेषकों का मत है कि आलाकमान की नज़र में विलासराव देशमुख का क़द बढ़ा है, क्योंकि वे समय के साथ राजनीति करते हैं. पृथ्वीराज चव्हाण अब तक देशमुख की राजनीति को समझ नहीं पाए हैं और उन्हें यह अति आत्मविश्वास हो गया था कि आदर्श सोसायटी घोटाले में बार-बार नाम आने से उनकी आलाकमान नहीं सुनेगा. वे अपनी साफ़-सुथरी छवि पर अधिक भरोसा कर बैठे. यहीं वे मात खा गए. इसका प्रतिफल संजय दत्त को भोगना पड़ रहा है. इसी को कहते हैं त्याग किसी ने किया और फल मिला किसी को.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

वर्ल्ड क्लॉस टॉउनशिप, सर्टिफाईड इन्वेस्टमेंट, ग्यारन्टेड रिटर्न्स!

The Palm City

'द पाम सिटी' दिपावली 2013 उपरांत भव्य रंगारंग
कार्यक्रम द्वारा फेज I का पजेशन दिया जाना तय हैं। इस 30 माह की
अवधि में समय समय पर होनेवाली मूल्यवृध्दि के कारण
पजेशन के समय 'द पाम सिटी' के दाम रु.3000/- प्रति वर्ग फुट से ज्यादा रहेगें।

जरा सोचें, आपका फायदा निर्णय आज लेने में है या निर्णय कल लेने में

दि.5 जुलाई से
2250/-

आपका निर्णय आपकी विजय

Ashtavinayak EMPIRE
आपकी खुशियों के सह-निर्माता

MODERN AMENITIES
- Approach Road Palm Street
- Palm Square 10,000 Ft. with large Fountain
- 6.50 Lac Sq.ft. Green Zone
- Mini Theater
- 3 Swimming Pool
- 2 Mini Cricket Ground
- Township Area 33 Acre
- Road Sizes 45 & 30 Ft.
- Grand Entrance
- Club House with All Modern Facilties
- School CBSE Pattern
- Proposed Hospital
- Palm Commercial Plaza
- Door Step Bus Facility
- Rain Water Harvesting
- Sewage & water Treatment Plant

कॉरपोरेट ऑफिसः पांचवा माला,लक्ष्मीसदा अपार्टमेंटस्, साई मंदिर के पास छत्रपती चौक, वर्धा रोड, नागपुर

Note: This advertisement is only a conceptual presentation of the project & not a legal offering. "Condition.

20% मार्जिन मनी 80% बैंक लोन
मार्जिन मनी का भुगतान
दो माह में दो किश्तों में

Akruti Advt.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 25 जुलाई-31 जुलाई 2011

www.chauthiduniya.com

Website : sanjeevanibuildcon.in

"संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI STATION
BIT Pithoria, Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9661337777 / 9472722024

9472727767 / 9162779209

पसमांदा मुस्लिम राजनीति

अपनों ने ही धोखा दिया

सरोज सिंह

तारीख़ गवाह है कि तहरीक और तंज़ीम का सियासी इस्तेमाल इसके रहनुमा जातीय महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के हथकंडे के तौर पर करते रहे हैं. ऐसे बहुत से नाम हैं जो मक़सद की पूर्ति होते ही ऐसी जमात और विचारों को चूल्हे में डालने से नहीं चूकते हैं, लेकिन जब राजनीति की रोटी सेंकने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर इस चूल्हे में फूंक मारकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं. बिहार में पसमांदा मुस्लिम राजनीति इससे अछूती नहीं रह पाई. इसके तमाम रहबर कुर्सी के चक्कर में ख़ुद तो चक्करघिन्नी बन ही गए, साथ ही उन्होंने अपने अनुनायियों की भावनाओं के साथ भी जमकर खिलवाड़ किया. इसी की नुमाइश गत एक जुलाई को भी हुई. यह तमाम पसमांदा मुसलमानों के लिए अहम दिन है. यह मौक़ा था पसमांदाओं के मसीहा अब्दुल कय्यूम अंसारी की जयंती का. इस दिन जदयू के पसमांदा राजनीति के दो चेहरे अपने सियासी आक़ाओं के समक्ष अपनी क़ाबिलियत प्रदर्शित करने के लिए दो अलग जगहों पर अब्दुल कय्यूम अंसारी के जन्मदिन के अवसर पर सियासी जलसे में व्यस्त रहे. जदयू के राज्यसभा सांसद अली अनवर ने आरा में तो विधान परिषद के उपसभापति तथा जदयू में पसमांदा सियासत के नए चेहरे सलीम परवेज़ ने पटना में इसका आयोजन किया. इन दोनों ख़ेमों की ओर से इस जलसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी शरीक होने का दावा किया गया, लेकिन इन दोनों में किसी के मंच पर नीतीश दिखाई नहीं दिए. कारण में उनकी तबियत का ख़राब होना बताया गया. हालांकि, सियासी हलक़ों में इसे पसमांदा राजनीति के कम होते असर के तौर पर प्रचारित किया गया, स्वभाविक भी है.

उन्नीस सौ नब्बे के दशक में बिहार में शुरू हुए पसमांदा आंदोलन का प्रसार बड़ी तेज़ी से हुआ. मुसलमानों की बड़ी आबादी वाले पसमांदा तबक़े के लिए यह आंदोलन एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया. लोगों ने इस आंदोलन के रहनुमाओं को सर आंखों पर बिठाया, लेकिन मात्र दस-बारह सालों में इसके नेता राजनीतिक कुर्सी की भीख के लिए अपने हाथ सत्ताधारियों के पास हाथ फैलाने लगे. जब किसी आंदोलन का रहनुमा सत्ता या राजनीतिक कुर्सी का हिस्सा बनता है तो सबसे पहले उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है. फिर आंदोलन का यही गूंगापन उसे बेमौत मारने के लिए काफ़ी होता है. इसकी नुमाइश हाल ही में अररिया के भजनपुरा में मारे गए पसमांदा मुसलमानों के मामले में हुई. पुलिसवालों की दरिंदगी के शिकार पसमांदा मुसलमानों के लिए पसमांदा सियासत के पैरोकारों की ज़ुबान नहीं खुली. पुलिसकर्मियों की उस वहशियाना हरकत की निंदा करने की बात तो दूर पीड़ितों के परिवार वालों की असमय मौत पर शोक प्रकट करने का जज्बा भी नहीं दिखा सके.

जबकि सन 2004 तक पसमांदा आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार के दो बड़े धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों- जदयू और राजद की जीत-हार में पसमांदा मुस्लिम समुदाय के वोटरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. लेकिन इस आंदोलन से जुड़े दोनों पसमांदा नेताओं ने सत्ता से समझौता कर लिया और बदले में राज्यसभा की कुर्सी हासिल की. इस घटना का नतीजा यह हुआ कि आज पसमांदा आंदोलन बिखराव की ओर है. यह पसमांदा मुसलमानों के वोट की शक्ति ही थी जिससे विवश होकर लोकजनशक्ति पार्टी ने एक तीसरे पसमांदा मुसलमान साबिर अली को राज्यसभा भेजा. शायद आज़ादी के बाद यह पहला अवसर था जब बिहार से लगभग एक ही समय में तीन-तीन पसमांदा मुसलमान राज्यसभा के लिए चुने गए. लोजपा के राज्यसभा सांसद साबिर अली भी कहते हैं कि सत्ता से नज़दीकी के कारण ही पसमांदा तहरीक बेजान हो कर रह गई है. वह कहते हैं कि मुसलमानों और ख़ासकर पसमांदा मुसलमानों के सशक्तीकरण के लिए सत्ताविरोधी

असली और नक़ली को पहचाने जनता : अनवर

पसमांदा समाज को उसका वाजिब हक़ दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले अली अनवर का कहना है कि उनके जीवन का मक़सद ही इस समाज को आगे ले जाना है. वह कहते हैं कि अभी बहुत सारे नेता पसमांदाओं के लिए आंसू बहा रहे हैं, पर असली और नक़ली की पहचान तो इस समाज को ख़ुद करनी है. वह कहते हैं कि उन्हें ख़ुशी है कि अब सड़क से लेकर संसद तक और गांव से लेकर देश-दुनिया में पसमांदा समाज की आवाज़ गूंज रही है. अली अनवर चाहते हैं कि दलित मुसलमानों व ईसाइयों को अनसूचित जाति का दर्जा जल्द से जल्द मिले. इसको लेकर वह 28 जुलाई को संसद के सामने बड़ा प्रदर्शन भी करने वाले हैं. उनका आरोप है कि केंद्र की यूपीए सरकार इसमें अड़चन डाल रही है. अनवर कहते हैं कि पसमांदा समाज को इसकी आबादी के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली है. खुले बाज़ार की नीति के कारण भी इस समाज का काफ़ी अहित हुआ है. अली अनवर का मानना है कि जज्बाती सवालों से दूर रहकर रोज़ी रोटी के सवाल को तवज्जो देने से ही पसमांदा समाज आगे बढ़ेगा.

पसमांदा आंदोलन की ज़रूरत है और ऐसे में सत्तालोभी पसमांदा नेताओं के हाथों से इस आंदोलन को अलग करके ही इसे फिर से कामयाब बनाया जा सकता है. केंद्र सरकार द्वारा गठित सच्चर कमेटी ने हालांकि दलित हिंदुओं से धर्म परिवर्तित कर बने मुसलमानों के लिए अनुसूचित जातियों की तर्ज़ पर आरक्षण देने की सिफ़ारिश की है, लेकिन इस रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, जिसमें कहा गया है कि दलित पसमांदा मुसलमान समुदाय हीन भावना से ग्रसित हैं. इनमें आत्मविश्वास जगाने की ज़रूरत है. लेकिन यह काम सरकारी स्तर के बजाय इस समुदाय के नेतृत्व के स्तर पर ही संभव है और यह काम सामाजिक आंदोलनों से ही किया जा सकता है. लेकिन यह तो सियासत में कुर्सी पाने का ज़रिया मात्र बनकर रह गया. राज्यसभा सांसद अली अनवर ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. एम एजाज़ अली के बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा से अलग पसमांदा मुस्लिम महाज़ नामक एक संगठन बनाया. विरोध की वजह थी मुसलमानों में कथित अगड़ी जाति मलिक को पिछड़ी जाति के तौर पर मान्यता दिए जाने की कोशिशों के ख़िलाफ़ डॉ. एम. एजाज़ अली को आवाज़ उठाना गंवारा नहीं था. लेकिन जदयू से राज्यसभा सांसद बनने के बाद अली अनवर भी अपने वास्तविक नीति सिद्धांत भूल गए. नीतीश सरकार में मलिक को पिछड़ी जाति का दर्जा दे दिया गया, लेकिन उन्होंने चूं-चपड़ भी नहीं की. इसी बीच पसमांदा तबक़े के एक जागरूक ख़ेमे ने अली अनवर की जगह सलीम परवेज़ को इस संगठन का सदर चुन लिया. उन्होंने तब पसमांदाओं के हक़ के लिए संघर्ष करने का दावा किया था. साथ ही किसी राजनीतिक दल के सहयोग से संसदीय पद ग्रहण करने पर पसमांदा मुस्लिम महाज़ का अध्यक्ष पद छोड़ देने का दावा किया था. लेकिन जदयू से विधान पार्षद और पुन: उपसभापति बनने के बाद वह अपना वादा भूल गए. लिहाज़ा इस महाज़ के दो-दो अध्यक्ष हैं.

पसमांदा मुसलमानों के पिछड़ेपन और ग़रीबी का मुख्य कारण उनके नेतृत्व की ख़ुदग़र्ज़ी ही है. जैसे-जैसे मुस्लिम रहनुमाओं की राजनीतिक ख़ुदग़र्ज़ी बढ़ती गई वैसे-वैसे आम मुसलमानों की आर्थिक और शौक्षिक, समस्या बेक़ाबू होती गई. केंद्र सरकार द्वारा गठित राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सारी सच्चाइयों को उजागर करती है. बिहार के शहरी मुसलमानों में ग़रीब हिंदुओं की तुलना में ग्यारह फ़ीसदी ज़्यादा है. अगर पसमांदा मुसलमानों की बात करें तो यह ग़ैरबराबरी और भयावह दिखता है. हालांकि मुस्लिम सियासत के इन अजब ग़जब पैरोकारों की व्यक्तिगत लाभ-हानि पर आधारित सियासी करतब से खुर्राट सियासतदां भी शरमा सकते हैं. लेकिन उनका समाज इन नेताओं को देख रहा है और अपने रहबरों से न्याय दिलाने की उम्मीद पाले हुए है. इनके संयम की भी सीमा है इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि किसी अनहोनी से पहले ही पसमांदाओं की नैया पार लग जाए, नहीं तो इनकी किश्ती डुबोने का कलंक इनके रहबरों पर ही लगेगा.

feedback@chauthiduniya.com

Ph:0612-3296829, 9334252869, 9386941721

Approved by Govt. of India

. . . The Way to Grow

SKY CONSULTANCY SERVICE PVT. LTD

DIRECT & CONFIRM ADMISSION

Contact : 604, 6th Floor LUV-Kush Tower Exhibition Road, Patna-1

Ph: 0612-3296829
9334252869
9386941721

2010 Admission Report

Bangalore Chennai
Delhi/NCR Punjab
Pune Bhopal

OUR EDUCATION PARTNER

Our Copration with you from 2001 to 2011

SCSPL

Engineering | MBA/PGDBM | MBBS | MCA | B.Ed

B.Pharma | Polytechnic | BBA | ITI

Branch: Yadav Market, Near Circut House Pakri Chowk Ara,
Mob;9798662051, 9334006756, Muzaffarpur Chhapra

Email : consultancy.sky.patna@gmail.com

बड़े पैमाने पर नक़ली सीमेंट का कारोबार बंगाल से बिहार तक

नीरज कुमार सिंह

सरकार मिलावटख़ोरों एवं काला बाज़ारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने एवं रोकथाम के लिए चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन हक़ीक़त यह है कि आज भी मिलावट एवं नक़ली सामानों के निर्माण का धंधा परवान पर है. वस्तु स्थिति यह है पश्चिम बंगाल का उत्तरी बंगाल का इलाक़ा ख़ासकर उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी दार्जलिंग नक़ली एवं मिलावटी सामानों के निर्माण का हब बन चुका है. मालूम हो कि जलपाईगुड़ी ज़िला अंतर्गत बीरपाड़ा एवं सीमावर्त्ती भूटान में सीमेंट से मिलती जुलती मिट्टी की प्रचुरता है, जिसमें पानी मिलाने से सीमेंट की तरह का घोल बन जाता है. सीमेंट से मिलती जुलती इसी मिट्टी को ट्रकों में भरकर बंगाल समेत पूर्णिया प्रमंडल के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जहां इसे सीमेंट के बड़े-बड़े गोदामों में असली सीमेंट के साथ मिलाकर बोरों में भरा जाता है. इस तरह के एक मामले का ख़ुलासा विगत दिनों किशनगंज के फायरिंग गोला स्थित सुभाष अग्रवाल के गोदाम में स्थानीय पुलिस की छापेमारी में हुआ. यहां लफार्ज, एसीसी जैसे नामी ब्रांडों के बोरों में इस मिट्टी को भरकर नक़ली सीमेंट बनाया जाता था. इस छापेमारी से तत्काल इस तरह के कारोबारियों में हड़कंप मच गया, लेकिन अधिक मुनाफ़े को देखते हुए वर्तमान में फिर से इस धंधे ने फिर से ज़ोर पकड़ लिया.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार, बंगाल की सीमा से सटे बंगाल के दालकोला, कानकी, इस्लामपुर, सोनापुर, विधाननगर सिल्लीगुड़ी वहीं बिहार के किशनगंज पूर्णिया के बासी गुलाबबाग, कसबा, रामनगर, कटिहार रौतारा आदि जगहों में सीमेंट के गुप्त गोदामों में इस तरह की सीमेंट बनाने का खेल जारी है. इस संबंध में स्थानीय लोग सीमेंट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. साथ ही उनका कहना है कि जहां सरकार द्वारा विकास संबंधी कार्य जैसे पुल, स्कूल भवन सड़क आदि का निर्माण कराया जा रहा है, वहीं आम लोगों के लिए बनने वाले भवन की क्या गारंटी न जाने कब छत ही गिर जाए. हाल के दिनों में किशनगंज के कई प्रखंडो में नव निर्मित विद्यालयों की छत गिरने की घटनाएं घटी हैं. आज आम लोग सीमेंट का सही मूल्य चुकाने के बावजूद ठगे जा रहे हैं. इस संबंध में प्रबुद्ध नागरिकों का कहना है कि जब तक सरकार इस प्रकार के अवैध कारोबारियों से संबंधित कोई सख्त क़ानून बनाकर इसका सही ढंग से अनुपालन नहीं कराती है तब तक इस प्रकार के धंधों पर लगाम नहीं लगाया जा सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

देवघर: दो अरब का ज़मीन घोटाला

देवघर में दो अरब रूपए से अधिक की ज़मीन का जाली सेल सर्टिफिकेट से बिक्री होने का मामला उजागर हुआ है. ज़िले के उपायुक्त मस्तराम मीणा ने मामले की शिकायत मिलने पर गोपनीय जांच कार्रवाई, जिसमें शहर के आसपास के 10 मौजा का 400 एकड़ ज़मीन के सेल सर्टिफिकेट जाली पाए गए हैं. मामले के उजागर होने पर भूमाफियाओं एवं संबंधित पदाधिकारियों में हड़कम्प मच गया है. सूत्रों के अनुसार, गहन छानबीन होने पर इससे कई गुना अधिक रुपए अथवा हज़ार एकड़ से अधिक का फ़र्ज़ी काग़ज़ातों के जरिए बिक्री होने का खुलासा होने की प्रबल आशंका है. मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त मस्तराम मीणा ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की बात कही है. उपायुक्त ने तत्काल प्रभाव से मौजा चेतनारी के 229 एकड़, रामपुर के 17 एकड़ , गौरा के 96 एकड़ एवं करनीबाग के 43 एकड़ अंतर्गत जमाबंदी एवं दाग नं की ज़मीन की खरीद बिक्री, दाखिल खारिज, हस्तातरण एवं भू सत्यापन पर रोक लगा दी है. उक्त मौजा की जमीन का निबंधन पर पूर्णत रोक लगा दिया गया है. जानकारों के अनुसार, यदि मामले की सीबीआई से जांच कराई जाय तो शहर की कई नामी गिरामी हस्तियों के नाम उजागर हो सकते हैं. उपायुक्त ने पिछले कुछ वर्षों में संबंधित विभागों में पदस्थापित पदाधिकारियों की सूची बनानी प्रारंभ कर दी है जिनके कार्यकाल में मामले पाए गए हैं. उपायुक्त ने बताया कि इस समस्या की जड़ एल ए है, जिसमें ही जाली हस्ताक्षर पाए गए हैं. रजिस्टर 2 में भी हेराफेरी एवं फर्जी हस्ताक्षर पाए गए हैं. इन्होंने बताया कि अवर निबंधन कार्यालय, दुमका में उपलब्ध सर्टिफिकेट की पंजी का वोल्यूम नंबर, प्लॉट इण्डेक्स रजिस्टर, विलेज इडेक्स रजिस्टर से मिलान करने पर पूरा मामला पकड़ा गया. उपायुक्त ने कहा कि ज़िले की भूमि संबंधी कागजातों एवं दस्तावेजों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है, जो गहन जांच का विषय है. इस प्रसंग में यह बताना आवश्यक है कि जानकारों के अनुसार देवघर शहरी क्षेत्र का महत्वपूर्ण नक्शा एवं दस्तावेज आदि जिला प्रशासन कार्यालय से काफी दिनों से गायब है. यहां तक कि संताल परगना आयुक्त कार्यालय एवं कोलकाता अभिलेखागार में भी देवघर का नक्शा एवं अभिलेख आदि गायब हैं. इससे स्पष्ट है कि भूमि खरीद बिक्री करने वाले के षड्यंत्र में स्थानीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी भी शामिल रहे हैं. देवघर के शहरी क्षेत्र में ट्रस्ट की ज़मीनों को बेचने का भी मामला काफ़ी सुर्ख़ियों में रहा है. गोचर, नन सेलेबल को सेलेबल बनाकर बिक्री की ख़बर तो आम बात है. यह सब काफी दिनों से बेरोक टोक चल रहा है. जबकि यहां जमीन बिक्री से पूर्व भारी भरकम राशि शुल्क के लेकर अंचल कार्यालय में एनओसी निर्गत करने का प्रावधान है जो शायद प्रदेश में कहीं भी नहीं है. ऐसे में इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ? जिले के उच्चाधिकारी इतने दिनों तक क्या कर रहे थे? क्या सच में वैसे पदाधिकारियों को सजा मिलेगी, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं ? क्या इस मामले से जुड़े सफेदपोश हस्तियों को कानून के शिकंजे में पकड़ा जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र शायद ही मिल पाएगा.

रणजीत झा
feedback@chauthiduniya.com

बगहा पुलिस लाइन: किसानों की ज़मीन पर नज़र

[illegible]

अरविन्दनाथ तिवारी
feedback@chauthiduniya.com

फास्ट फूड से बचें : घोष

पिछले कुछ वर्षों में भारत जैसे विकासशील देशों में मधुमेह रोगियों की संख्या में बड़े पैमाने पर इज़ाफ़ा हुआ है. मधुमेह रोग के [illegible]

सेहत

नीरज कुमार सिंह
feedback@chauthiduniya.com

सहरसा: डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं

चिकित्सा कर्मियों पर बार-बार होने वाले हमले का कारण क्या है? डॉक्टर को भगवान कहने वाले आम लोग इन्हें अब शैतान क्यों समझने लगे हैं? इन पर मरीज के इलाज में अनदेखी व जान लेने जैसे गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं?

मनोज ठाकुर

कोसी का पीएमसीएच कहा जाने वाला सदर अस्पताल, सहरसा ख़ुद बीमार है. यहां काम करने वाले चिकित्सक व चिकित्साकर्मी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. हाल के दिनों में मरीजों के तीमारदारों द्वारा डॉक्टरों से किए गए दुर्व्यवहार से सारा चिकित्सीय कार्य भय के साये में हो रहा है.

ऐसा ही वाकया बीती 6 जुलाई की आधी रात को हुआ जब गोली से घायल मरीज को कुछ लोग सदर अस्पताल लेकर आए. मरीज की मौत अस्पताल आने के क्रम में हुई हो या अस्पताल आकर, जो भी हो लेकिन इसकी मौत फिर चिकित्साकर्मी पर कहर बनकर टूटी. मृतक के परिजन खोज-खोज कर अस्पताल कर्मी की पिटाई करने लगे और अस्पताल कर्मी जान बचा कर भाग खड़े हुए. फिर आई पुलिस. मामले को शांत समझ छिपे अस्पताल कर्मी पुन: अस्पताल वापस आये और अहले सुबह शव का पोस्टमार्टम करने जुटे. लेकिन वहां भी पुलिस की मौजूदगी में हमले हुए, जिसमें डॉ. एस के सादा और उनके सहायक विष्णुदेव सिंह घायल हुए. अगर पुलिस वहां मौजूद नहीं होती तो शायद इनकी जान भी जा सकती थी. आखिरकार डॉक्टरों के सब्र का बांध टूट गया और वे मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी, अस्पताल की सुरक्षा के लिए सैफ जवानों की नियुक्ति और अस्पताल की घेराबंदी आदि मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गये. प्रश्न इठता है कि अस्पताल में ऐसी घटनाएं घटती क्यों है? चिकित्सा कर्मी पर बार-बार होने वाले हमले का कारण क्या है? डॉक्टर को भगवान कहने वाले आम लोग इन्हें अब शैतान क्यों समझने लगे हैं? इन पर मरीज के इलाज में अनदेखी व जान लेने जैसे गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? 6 जुलाई की रात की घटना में भी ऐसे ही आरोप इन पर लगे. हालांकि आरोपी डॉक्टर सादा कहते हैं कि वह मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था. कुछ असामाजिक तत्वों ने आरोप लगाकर घटना को अंजाम दिया. इस मामले पर सहरसा एसपी ए रहमान कहते हैं कि दोनों ही आरोप गंभीर हैं. पुलिस जांच कर रही है. जो भी दोषी होंगे वे बख्शे नहीं जायेंगे. वहीं हड़ताल के दौरान मरने वाले नरेश साह के मौत की खबर जब डॉक्टर सादा को दी गई तो उन्होंने कहा अब या तो डाक्टर मरेगा या मरीज. मतलब स्पष्ट है कि वे आहत हैं. जनवरी से अबतक दर्जनों निजी क्लीनिकों पर हमले की घटना प्रमंडल में घट चुकी है. आखिर ऐसी घटना होती ही क्यों हैं. क्या चिकित्सा जैसे पवित्र पेशे में कुछ लापरवाह लोगों का प्रवेश हो गया है. जो लोगों का दोहन करना ही अपना फर्ज मानते हैं या आम लोगों की उम्मीदें डॉक्टरों से बढ़ गयी है. जिस पर वे खरे नहीं उतर पा रहे हैं या अस्पताल में हैं सुविधाओं की कमी है. लेकिन इतना तो तय है कि ऐसी घटना पर रोक लगाने के लिए लोगों का विश्वास खोते जा रहे अस्पताल कर्मियों को भी आत्ममंथन करना होगा. और जान बचाने की खातिर अस्पताल की ओर रुख करने वाले आम लोगों को भी अपने किए पर विचार करना होगा. नहीं तो ऐसी घटनाऐं घटती रहेगी. आखिर अस्पताल में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए नियुक्त किये गये सैफ के जवानों के संगीनों के साये में वे कबतक इलाज करते रहेंगे व इलाज करवाते रहेंगे.

पिछले एक दशक में ऐसी सैकड़ों घटनाएं प्रमंडल के सहरसा, मधेपुरा व सुपौल जिले में घट चुकी है. हर घटना में मरीज की मौत पर डॉक्टर पिटते रहे हैं लेकिन ऐसी घटना से न तो अस्पताल कर्मी सबक ले रहे हैं और न ही घटना को रोकने के लिए कोई प्रशासनिक पहल हो रही है. बता दें कि सभी अस्पताल में रोगी कल्याण समिति कार्यरत हैं. जिनका उद्देश्य है रोगियों और डॉक्टरों के बीच सौहार्द कायम करना. लेकिन इनकी भूमिका कहीं से भी नजर नहीं आती है. हर घटना पर समिति के सदस्य अनुपस्थित रहते हैं. जबकि अस्पताल से सुविधा प्राप्त करने में सबसे आगे वही दिखते हैं. ऐसे में अपने को असुरक्षित महसूस करते अस्पताल कर्मी व डॉक्टर अपना सर्वोच्च हुनर मरीज को कैसे दे पायेंगे. और आम लोग भी इनपर कैसे विश्वास कर पायेंगे. इतना तो तय है कि कुछ दोष लोहा का तो कुछ लौहार का अवश्य होगा.

दूसरी बात यह कि प्रशासन भी इन्हें कहां तक सुरक्षा मुहैया करा पाएगा. सदर अस्पताल तो एक है जबकि निजी नर्सिंग तो सैकड़ों की संख्या में हैं. आख़िर प्रशासन कहां-कहां सैफ के जवानों को नियुक्त करेगी. इनके पास इतने बल भी नहीं है. मतलब साफ़ है. डॉक्टर व मरीज दोनों सशंकित रहेंगे. बिना इनके बीच आपसी सौहार्द कायम किये, इनकी सुरक्षा की गारंटी का कोई औचित्य नहीं दिखता.

feedback@chauthiduniya.com

हर घटना पर समिति के सदस्य अनुपस्थित रहते हैं. जबकि अस्पताल से सुविधा प्राप्त करने में सबसे आगे वही दिखते हैं. ऐसे में अपने को असुरक्षित महसुस करते अस्पताल कर्मी व डाक्टर अपना सर्वोच्च हुनर मरीज को कैसे दे पायेंगे. और आम लोग भी इनपर कैसे विश्वास कर पायेंगे. इतना तो तय है कि कुछ दोष लोहा का तो कुछ लौहार का अवश्य होगा.

क्या कहते हैं शहर के कुछ नामी-गिरामी चिकित्सक

डॉ. के. एस. मिश्रा: अभी जो माहौल है उसमें यह घटना दोहराई जायेगी. लोगों की मनोवृति बदल गयी है. वे समझते हैं कि डॉक्टर मृत को भी तुरंत जीवित कर सकते हैं, जो संभव नहीं है. प्रशासन भी लड़खड़ाया हुआ है. इन घटनाओं को रोकने के लिए लोहे का हाथ चाहिए. जो वर्तमान में डीआईजी, कमिश्नर दे सकते हैं.

डॉ. अवनिश कर्ण: सदर अस्पताल चिकित्सकों व कर्मियों की कमी की समस्या से जूझ रहा है. और रोगियों की बढ़ती भीड़ के लिए उचित साधन भी वहां उपलब्ध नहीं हैं. जिसका एक सुनिश्चित हल ढूंढे बिना ऐसी घटना पर रोक संभव नहीं है.

डॉ. ए. के. ईसर: जनता को अब डॉक्टरों पर विश्वास नहीं रह गया है. वे घर से इलाज को निकलते हैं तो समझते हैं कि डॉक्टर ठगेंगे. पहले इनका विश्वास तो हासिल करें डॉक्टर.

डॉ. अजय कुमार सिंह: अस्पताल में चिकित्सक की कमी इन घटनाओं को अंजाम दिलाने का प्रमुख कारण है. इनको रोकने के लिए हर आठ घंटे पर एक सर्जन, एक गायनाकोलोजिस्ट, एक एनेसथेटिक व एक फिजीसियन होना चाहिए. लोगों को भी डॉक्टर की मजबूरी समझना चाहिए.

क्या कहते हैं शहर के कुछ बुद्धिजीवी लोग

लड्डू बाबा: डॉक्टर के लिए मरीज प्रतिदिन एक परीक्षा है, जिसे वे भूल चुके हैं. और पूर्णत: व्यवसायिक हो गये हैं. जिससे आम लोगों में इनके प्रति श्रद्धा और सम्मान की कमी देखी जा रही है.

अशोक कुमार सिंह: डॉक्टरों और मरीजों के बीच दोस्ताना संबंध होना चाहिए. न कि ग्राहक और व्यापारी जैसा संबंध. हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं भी व्यावसायिक हो गयी हैं. जिसके कारण दोनों के बीच भावनात्मक संबंध नहीं बन पा रहा है. इसीलिए ऐसी घटनाएं होती हैं.

एक नज़र

बाबाधाम में शीघ्र दर्शनम् पूजा हमेशा मिलेगी

बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रावणी मेले के दौरान 500 रुपए शुल्क में ही शीघ्र दर्शनम् पूजा की सुविधा श्रद्धालुओं को हमेशा ही मिलेगी. यह निर्णय मंदिर प्रबंधन बोर्ड की बैठक में लिया गया है. मंदिर कार्यालय के काउंटर पर शुल्क जमा कर सुविधा का लाभ श्रद्धालु उठा सकेंगे. श्रावणी मेले में भारी भीड़ के कारण 3 से 5 किलोमीटर लंबी कतार लग जाती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े एवं महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसे देखते हुए मंदिर प्रबंधन बोर्ड ने शीघ्र दर्शनम् पूजा की सुविधा सीमित संख्या में पिछले वर्ष प्रारंभ की थी, जिसमें सफलता के बाद इस वर्ष यह सुविधा जलार्पण अवधि में हमेशा ही दी जाएगी. बोर्ड के सदस्य एवं पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा ने बताया कि श्रावणी मेले में बाबाधाम आने वाले श्रद्धालुओं को यह सुविधा काफी महत्वपूर्ण होगी तथा प्राप्त शुल्क से मंदिर कोष भी बढ़ेगा.

अनुशासनहीन नेताओं को सज़ा होगी : कृष्णानंद झा

जमशेदपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की करारी हार के बाद पार्टी के नेताओं में आपसी बयानबाजी एवं आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो गया है. पार्टी हाईकमान ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. जिसके बाद दोषी नेताओं को सजा दी जाएगी. यह जानकारी प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा ने देते हुए बताया कि 18 जुलाई को रांची में अनुशासन समिति की बैठक होने वाली है जिसमें सभी पक्षों पर विचार विमर्श होगा, इसके बाद हाईकमान को रिपोर्ट भेजी जाएगी. झा ने कहा है कि पार्टी नेताओं को आपसी बयानबाजी से परहेज करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पार्टी संविधान के तहत् ही चुनाव परिणाम पर बहस होनी चाहिए. झा ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश के कुछ नेताओं में अनुशासनहीनता की सूचना है. पत्रकारों के पूछने पर झा ने बताया कि नए प्रदेश का चयन शीघ्र ही होगा, जिसमें आदिवासी एवं गैर आदिवासी मुद्दा अहम् होगा.

देवघर से दुमका के बीच दौड़ी ट्रेन

संताल परगना के दिलों को छूने वाली रेल का शुभारंभ 12 जुलाई को पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक सहित कई वरीय रेल पदाधिकारियों की उपस्थिति में चतुर्थवर्गीय रेलकर्मी सुफल मांझी ने हरी झंडी दिखाकर एक इतिहास रचा. झारखण्ड की उपराजधानी दुमका ज़िले वासियों का बहुप्रतिक्षित रेल का सपना पूरा हो गया. जसीडीह जंक्शन से दो घंटे में पैसेंजर ट्रेन प्रसिद्ध तीर्थस्थल बासुकीनाथ धाम होते हुए दुमका पहुंचेगी. नवनिर्मित देवघर रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था क्योंकि पहले दिन टिकट लेकर यात्रियों की भीड़ स्टेशन से रेल यात्रा करने के लिए उमड़ पड़ी थी. वर्तमान में सिर्फ़ एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन जसीडीह से दुमका चलेगी और शाम तक वापस आएगी. महाप्रबंधक ने बताया कि आने वाले समय में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और यात्री एवं एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा.

– रणजीत झा

रोसड़ा में सड़कों का बुरा हाल

लालू-राबड़ी राज हो या नीतीश कुमार का सुशासन, रोसड़ा के लोग कोई फ़र्क़ महसूस नहीं कर रहे हैं. सड़क निर्माण की दिशा में सत्ता शासन की लापरवाही के कारण रोसड़ावासी नारकीय माहौल में जीवनयापन करने को विवश हैं. सरकार ने आश्वासन दिया कि युद्धस्तर पर कार्य कर एसएच-55 सिंघियाघाट से डाकबंगला चौक, बड़ी दुर्गा स्थान, अम्बेडकर चौक, सिनेमा चौक, महावीर चौक, गांधी चौक रोसड़ा से बेगूसराय ज़िले के सागी चौक तक की सड़क का कायाकल्प किया जायेगा. लेकिन कार्य में कोई प्रगति नहीं होते देख लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है.

–विकास कुमार

करियर दुनिया

छात्रों के लिए पटना बना सपनों का शहर

राजधानी पटना एक ओर जहां राजनीति गढ़ के रूप में जाना जाता है वहीं दूसरी ओर शैक्षिणक माहौल के लिए भी आज सुर्ख़ियों में है. बिहार के युवा प्रदेश ही नहीं राष्ट्र स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. इसके पीछे सिर्फ़ बिहार का शैक्षणिक वातावरण और युवाओं की मेहनत का परिणाम है. छात्र कई तरह की समस्याओं से जूझते हुए भी अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए सूबे के सुदूर गांवों से आकर राजधानी में कई समस्याओं को झेलते हुए भी पढ़ाई कर रहे हैं. चौथी दुनिया की टीम ने इन्हीं समस्याओं को जानने के लिए कुछ छात्रों से बात की.

आरा की रहने वाली निक्की भारद्वाज बताती हैं कि पटना एजुकेशन के लिए हब बन गया है और मध्यम वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को कोटा या दिल्ली में नहीं भेज सकते. जहां तक मेरा सवाल है तो मैं जेडी वीमेंश कॉलेज से प्लस 2 कर रही हूं. आगे की मेरी तैयारी मेडिकल में जाने की है, जिसके लिए मैं जी जान से पढ़ाई कर रही हूं. पटना में अकेले रहने के सवाल पर बताया कि लड़कियों को पटना में अकेले रहना थोड़ा परेशानी भरा है लेकिन करियर को मंजिल तक पहुंचाने के लिए तो थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा. महेश कुमार फतुहा निवासी ने बताया कि मैंने तो रेलवे का पास बनवा लिया और मैं प्रति दिन अपने घर से पटना क्लास करने आ जाता हूं इसलिए मुझे रहने व और अन्य मामलों में ज़्यादा परेशानी नहीं होती. पढ़ाई के नाम पर बताया कि मुझे नहीं लगता कि अब बिहार के लड़कों कोटा, दिल्ली या बैंगलोर जाने की ज़रूरत है. पटना में सबकी आमदनी के हिसाब से कोचिंग संस्थान खुल गए हैं जो कि आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत दिख रहे हैं. दरभंगा की रहने वाली कंचन कुमारी का सपना मीडिया में जाने का है. कंचन बताती है कि अभी तो मैं मैट्रिक पास कर इंटर में विज्ञान संकाय से पढ़ाई कर रही हूं. लेकिन आगे की मेरी प्लानिंग मीडिया में जाने की है जिसके लिए पटना में एडवेंटेज मीडिया और जाकिर हुसैन जैसे नामी संस्थान तैयारी करा युवाओं के करियर को उज्जवल बना रहे हैं, इसलिए पटना मेरे लिए पसंदीदा शहर बन गया है. कंचन ने बताया कि अभी मैं पटना में लॉज में रहकर पढ़ाई कर रही हूं. मम्मी पापा से अलग रहना थोड़ा मुश्किल तो है पर लॉज के सारे दोस्त हमारे अच्छे हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती.

मुजफ्फरपुर का रहने वाला कुमार केशव एआईईईई, आईआईटी एवं जेई की तैयारी कर रहा है. केशव ने बताया कि पढ़ाई के रूप में पटना का माहौल अन्य जिलों के मुताबिक काफी बढ़िया है. यहां आज बाहर से शिक्षक आकर क्लास ले रहे हैं जो कि छात्रों के लिए बहुत बढ़िया ऑफर मिल रहा है. वहीं केशव ने बताया कि ट्यूशन फी को लेकर थोड़ी परेशानी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि मध्यमवर्गी परिवार के छात्रों के बीच इसका तालमेल अच्छा नहीं बैठ पा रहा. क्योंकि आज पटना के किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाएं आईएससी एवं आई कॉम की दो साल की तैयारी करने में चालीस से पचास जार रुपये लग जाते हैं जो कि ग़रीब परिवार के बच्चों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है. बक्सर की रहने वाली पूजा बताती है कि मैं एमबीए करना चाहती हूं इसके लिए मैं इंटर में वाणिज्य संकाय से इंटर कर रहीं हूं और मैं इसकी तैयारी केलिए कॉमर्स इंस्टीट्यूट में नामांकन को लेकर तैयारी कर रही हूं. पूजा के मम्मी पापा पटना में ही रहते हैं इसलिए पूजा को पटना में रहने के लिए कोई कठिनाई नहीं होती है.

इंटर का छात्र सारण छपरा निवासी अमन कुमार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा में 21 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण है. अमन एआईएसी गणित विषय से कर रहे हैं. अमन ने बताया कि मैं एआईईईई, आईआईटी को फेस करने के लिए सी लेबर की तैयारी कर रहा हूं. मेरे मां बाप और मेरा सपना है कि मैं इंजीनियर बनूं. मेरे पिता जी किसान हैं और मेरे बड़े भाई फौज में हैं. मैं इन्हीं की मदद से पटना में रूम पार्टनर बनकर पढ़ाई कर रही हूं. वहीं दूसरी ओर नालंदा की रहने वाली नेहा कुमारी बताती है कि मैं बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहती हूं इसलिए मैं वाणिज्य संकाय से इंटर कर रही हूं और मेरा सपना है आत्मनिर्भर होना, जिसके लिए मैं तैयारी कर रही कर रही हूं. अकेले रहने के सवाल पर नेहा बताती है कि मुझे याद है मेरी बड़ी दीदी को डॉक्टर बनने की तमन्ना थी लेकिन पापा ने अकेले रहने की इजाजत नहीं दी. क्योंकि उस समय बिहार में बलात्कार, अपहरण और क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ गया था लेकिन नीतीश सरकार में सबकुछ शांत हुआ है. इसलिए अब पटना जैसी सिटी में अकेले रहने पर भी पैरेंट्स नहीं घबराते. जहानाबाद के रहने वाले मुकेश कुमार ने बताया कि वैसे तो जहानाबाद में भी अब अच्छे-अच्छे कोचिंग संस्थान और कॉलेज खुल गए हैं लेकिन पटना का मजा ही कुछ और है. यहां पर छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार कॉलेज और कोचिंग संस्थान चुनने की आज़ादी. क्योंकि पटना में कम ख़र्च में भी अच्छी तैयारी की जा सकती है. मुकेश ने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रोबलम यहां आवास की है, जो कि छात्रों को जल्दी मिलती नहीं और मिलती भी है तो मकान मालिक मजबूर जानकर महंगे दामों पर छात्रों से किराया वसूली करते हैं.

– देवेन्द्र कुमार दुबे

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अमन कुमार, कंचन, कुमार केशव, महेश कुमार, मुकेश कुमार, नेहा, निकी भारद्वाज, पूजा

गणित के लिए थ्योरी पर कमांड ज़रूरी : पंकज

प्रो. पंकज कुमार

पंकज क्लासेस के निदेशक गणितज्ञ प्रो. पंकज कुमार का कहना है कि हर एक विद्यार्थी का सपना होता है आईआईटी पास करना, जो तभी संभव है जब आप गणित की थ्योरी पर कमांड करें. इसके बाद आप मैथ बना सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि थ्योरी के बिना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता. सफलता के लिए मेहनत, लगन के साथ-साथ सही प्लानिंग बेहद ज़रूरी है. सही प्लानिंग बिना तनाव के पढ़ाई और घरवालों के समर्थन से ही संभव हो सकता है. छात्र जहां इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, वहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी वे अव्वल आना चाहते हैं. विद्याथी आईआईटी – जेईई की तैयारी करते हैं और इसे अपना लक्ष्य बनाते है और वो हासिलकर लेता है. मेरा मानना है कि अगर आप एक कदम आगे की सोंचेगे तो बीच की सभी चीजें अपने आप पूरी हो जाएंगी. विद्यार्थी कम से कम घर में 6 से 7 घंटा पढ़े तो इसे सफलता अवश्य मिलेगी. लेकिन जरूरी है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल करें. सफलता के लिए मार्गदर्शन और मार्गदर्शक दोनों ही की जरूरत होती है.

अगर आप एक क़दम आगे की सोचेंगे तो बीच की सभी चीजें अपने आप पूरी हो जाएंगी. विद्यार्थी कम से कम घर में 6 से 7 घंटा पढ़ें तो इसे सफलता अवश्य मिलेगी.

- **आईआईटी–** जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी रातों रात नहीं होती. इसके लिए एक भूमिका तैयार करनी होगी वो तभी संभव होगा जब इसे एक कुशल मार्गदर्शक मिले.
- **प्रश्न हल कैसे करें** – सबसे पहले सभी प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ें. इसके बाद देखें कौन से प्रश्न आप आसानी से बना पाते हैं और उसे हल करें. इसके बाद जटिल प्रश्न को टच करें और यथा संभव हल करें.
- निगेटिव अंक वाले प्रश्न कैसे हल करें – निगेटिव अंक वाले प्रश्न अगर आप जानते हों तो हल करें नहीं तो हल न करें.

EIILM UNIVERSITY SIKKIM
COURSES BA, BSc. B.Com. M.A., Misc. Mcom., Mphil, B.C.A, B.B.A., M.C.A., M.B.A.
Study Centre at
ST. MICHAEL ANGLO VIDYALAYA, TIWARI CHOWK, DEOGHAR
ENGLISH MEDIUM UNDER C.B.S.E
HOTEL FACILITY
RUN BY
KERALA EDUCATIONAL & SOCIAL WELFARE SOCIETY
Mob. : 9430345258 (J.C.RAJ)

EXPERT BANK COACHING
MODERN STUDY CENTER
West of Patel Field, Kashipur, SAMASTIPUR
A. Kumar (Anil Kumar)
Chairman, Modern Study Centre & Expert Bank Coaching
BANK COACHING अवसर Join करें
Contact : 9835006852, 9471043020.

ऋण सुविधा
वाहन ऋण, सावधि ऋण,
कैश क्रेडिट, पैक्सों के वास्ते
ऋण, सुविधा सस्ते ब्याज दर पर उपलब्ध है
विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क करें
दि [illegible] कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड

School No.-52012 Affi No. : 3430163
RED ROSE SCHOOL 10+2
Affiliated to C.B.S.E., Delhi
Up to Secondary Level
CASTARI'S TOWN, B. DEOGHAR (JHARKHAND), PIN-814112
पूरा विद्यालय परिवार पावन मास 'सावन' के शुभअवसर पर सभी कांवरियों/शिवभक्तों के प्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता है।
बाबा बैद्यनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें
युद्धिष्ठर प्र. राय
सचिव
Mob. 09234987535